चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 18 जुलाई- 24 जुलाई 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मैं आ रहा हूं

नीतीश कुमार

शराबबंदी जैसे मसले पर खुलकर अपनी राय प्रकट करते हुए मुझे खुशी हो रही है. इस अभियान की सबसे बड़ी सार्थकता यह है कि धीरे-धीरे देशभर की महिलाएं इससे जुड़ रही हैं और जो सक्रिय तौर पर अभियान में शामिल नहीं हो पा रही हैं, वह भी खुद को इससे जुड़ा महसूस कर रही हैं. महिला संगठनों के साथ, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और गैर सरकारी संस्थाओं का इस अभियान से जुड़ना रेखांकित करने लायक है. यहां तक कि योग और प्राकृतिक उपचार का भी इसके साथ जुड़ना मुझे हृदय से प्रसन्नता दे रहा है. शराबबंदी का काम बहुत बड़ा काम है, इसका अहसास मुझे पहले से ही था, लेकिन ये इतना बड़ा है इसका अहसास इसको लागू करने के बाद हुआ. जब मैं युवा था, जेपी मूवमेंट में था, उस समय से और यह कहें कि छात्र जीवन से ही मैं शराब के खिलाफ रहा. मेरे मन में ये बात आती थी कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो शराब जरूर बंद करूंगा. जब बिहार में काम करने का मौका मिला नवंबर 2005 से, तब कई बार ये बात मेरे दिमाग में आती थी कि कैसे 1977 में जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय मोरारजी भाई देसाई जी भी शराब के बहुत खिलाफ थे. बिहार में उस समय समाजवादी नेता जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की थी. लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया गया. जब भी शराबबंदी लागू करने की बात मेरे मन में आई, तो अनेक तरह के तथ्य दिमाग में कौंधते थे. अमेरिका ने भी इसे लागू किया था, फिर उसको वापस लेना पड़ा. लोग रूस की भी बात करते थे. अनेक लोग देश और प्रदेश की बात करते थे. ये भी कहते थे कि लागू तो कर दिया जाता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है और इससे दो नंबर का कारोबार बढ़ता है. जहरीली शराब बनने लगती है.

ऐसे शुरू हुआ मद्य निषेध दिवस

मैं कई काम करता रहता हूं. कई कामों में व्यस्त रहता हूं. बिहार जैसे राज्य को संभालना और बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाना था. अन्य सभी प्रकार के कार्यों में लगे रहने के बावजूद मन में यह एक बात अटकी रहती थी. जब हम 2010 में दोबारा आए तो हमने एक फैसला किया. मैंने कहा कि जो उत्पाद विभाग इसको देखता है, उसका पूरा नाम है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग. मैंने विभाग के लोगों से कहा कि ये केवल उत्पाद ही नहीं है, एक्साइज़ डिपार्टमेंट ही नहीं है, बल्कि मद्य निषेध का भी काम इसी का है. अंततोगत्वा, प्रोहिबिशन (निषेध) लागू करना इसका ध्येय है. हमने तय किया कि डिपार्टमेंट का एक पक्ष तो यह है कि उत्पाद से आमदनी बढ़ रही है और सरकार की आमदनी भी बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं है. धीरे-धीरे शराब का पूरा कारोबार स्वत: चैनल में आने लगा. मैं तो कुछ जानता नहीं था. मैंने घंटों सिर्फ इस डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों के साथ बैठ कर केवल उन्हें सुना. उन लोगों के सामने अपनी जिज्ञासा रखता गया. मुझे ऐसा बताया गया कि इसमें मोनोपोली है. मैंने कहा कि इस मोनोपोली को तोड़ दीजिए. मोनोपोली को तोड़ दिया गया और हमने होलसेल ट्रेड बनाया. इसे सरकार ने ले लिया और नतीजा देखिए उसका. पहले दो से तीन सौ करोड़ शराब के व्यापार से आता था जो बढ़ते-बढ़ते 5000 करोड़ हो गया. लेकिन, जब इसकी आमदनी बढ़ती थी तो मेरे मन में बेचैनी बढ़ती थी. दुकानें ज्यादा नहीं बढ़ीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा कि इसकी चर्चा और इसका प्रचलन दोनों बढ़ा.

जब हम 2010 में दोबारा जीतकर आए थे तो हमने यही कहा कि मद्य-निषेध पर ध्यान दीजिए. मद्य-निषेध दिवस का आयोजन शुरू किया गया. 26 नवंबर को हमने दूसरी बार शपथ ली तो कहा कि 26 नवंबर को मद्य-निषेध दिवस होगा. हमारे यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं और दूसरे ग्रुप की महिलाएं आंदोलन करती थीं, तो हम उनको शाबाशी देते थे और कहते थे कि जिस गांव में शराब बंद हो जाएगी और लोग शराब से मुक्त हो जाएंगे, उस गांव को पुरस्कृत करेंगे. उनके लिए अतिरिक्त योजना भी देंगे. इनसेंटिव देना शुरू किया. अगर बच्ची अच्छी पेंटिंग बनाती है तो उनको पुरस्कृत करना, कोई अच्छी तस्वीर बनाए, पेंटिंग बनाए, उसको पुरस्कार देना, कोई शराबबंदी के लिए नारा अच्छा लिखे तो उसको पुरस्कार देना प्रारंभ किया. मैसेज वगैरह भी मेरा खूब चलता था. एक सिलसिला शुरू किया, लेकिन मैंने देखा कि इन सबसे शराब की खपत बढ़ती ही गई. मन में दुविधा थी, 1977 में जब सरकार बनी थी, जब शराबबंदी लागू की गई और फिर बाद की सरकार ने उसे वापस ले लिया, इसलिए मन में दुविधा थी.

अगर सरकार को शराब के व्यापार से पांच हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती थी तो इसका मतलब था कि लोग कम से कम दस हजार करोड़ रुपये की शराब पी रहे थे. शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में हर साल दस हजार करोड़ रुपया बचेगा. जिसके पास पैसा बचेगा वो उसे खर्च भी करेगा. पैसा बाजार में ही जाएगा. किसी दूसरे काम में पैसा खर्च होगा. आदमी बेहतर खाना खाएगा, ढंग के कपड़े पहनेगा, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देगा. इससे भी तो व्यवसाय और बाजार बढ़ेगा.

आज यूपी में 17000 करोड़ रुपये की कमाई शराब से मिलने वाले टैक्स से है. लोग पूछते हैं कि उसका विकल्प क्या होगा. विकल्प तो है. बिहार में दस हजार करोड़ की शराब का व्यापार था, उत्तर प्रदेश में तो लोग 25 से 30 हजार करोड़ रुपये की शराब पी रहे हैं. अगर यूपी के लोग 25-30 हजार करोड़ रुपये की शराब पीना छोड़कर दूसरी चीजों पर खर्च करेंगे, तो ये आमदनी कहां जाएगी? क्या इससे बाजार में, व्यापार में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा?

शराबबंदी का श्रेय महिलाओं को

पिछले साल 9 जुलाई 2015 को पटना में महिलाओं का एक कार्यक्रम था. ग्राम वार्ता कार्यक्रम का आयोजन वीमन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा पटना के सबसे बड़े सभागार श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया था. नारी सशक्तिकरण पर बात कहकर अभी हम बैठे ही थे कि पीछे से कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई शराबबंदी की. मुझको लगा कि शराब बंद करने की बात कर रही हैं. हमारे साथ जो साथी बैठे थे, मैंने उन लोगों से पूछा कि महिलाएं क्या कह रही हैं, तो उन लोगों ने कहा कि वे शराबबंदी लागू करने की बात कर रही हैं. मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे मन की सारी दुविधा मिट गई और मैं माइक पर आया और मैंने कहा कि अगली बार आएंगे तो पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे. जुलाई का महीना था और नवंबर में परिणाम निकला. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये तीनों महीने चुनाव के थे. चुनाव अभियान चल रहा था. बिहार में पांच से छह चरणों में चुनाव होते हैं. लंबा चुनाव चलता है. यह घटना चुनाव परिणाम आने से दो महीने पहले की है. मैंने कहा कि अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे और लोगों ने फिर तीसरी बार मौका दे दिया. 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हुआ. 26 नवंबर को मद्य-निषेध दिवस था, उसी दिन मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था. मैंने उस कार्यक्रम में जाकर कहा कि एक अप्रैल से बिहार में शराबबंदी लागू की जाएगी. जब इसका ऐलान कर दिया तो इसकी पूरी तैयारी भी की. बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के साढ़े पांच लाख समूह हैं. 2017 तक वह संख्या बढ़कर दस लाख हो जाएगी. अभी इससे 56 लाख ग्रामीण परिवार जुड़े हुए हैं. बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. पंचायत शिक्षकों के नियोजन में भी 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया हुआ है. यहां भारी संख्या में महिलाएं प्राइमरी टीचर्स हैं. इन महिला शिक्षकों व स्कूल के बच्चों को मोबिलाइज किया.

शराबबंदी के लिए एक बड़ा कार्यक्रम 30 जनवरी को लॉन्च किया गया था. मैंने खुद एक-एक चीज को देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर 1977 में ऐसा क्या हुआ था, जिससे शराबबंदी असफल हो गई. एक-एक पहलू पर गौर किया कि क्या-क्या होना चाहिए. बहुत लोग शराब की लत के इस कदर शिकार हो जाते हैं कि वे शराब नहीं छोड़ पाते. बिहार में पहले नशामुक्ति केंद्र काम नहीं करता था. मैंने हर जिले में नशामुक्ति केंद्र खोला, जिला अस्पतालों में नशामुक्ति के लिए ओरिएन्टेशन या ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करवाया. एम्स और बैंगलोर की एक संस्था को जोड़कर यह कार्यक्रम शुरू किया गया. एक-एक पहलू को देखा गया. कानून में क्या कमी है, उसका अध्ययन करके उसमें सुधार लाने के लिए संशोधन किया गया. यह सब करने से मार्च तक एक माहौल बना. मैंने महिलाओं की मांग पर पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया और इसे लागू किया. महिलाओं में इस प्रकार का मोबिलाइजेशन होना चाहिए और इसके माध्यम से हर जगह एक सशक्त अभियान चले, ये काम हमें करना है. बच्चों को कहा गया कि वे अपने अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाएं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और दूसरों को शराब नहीं पीने के लिए प्रेरित करूंगा.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मैं आ रहा हूं

पृष्ठ 1 का शेष

लोगों ने शपथ पत्र दिए

यह खुशी की बात है कि बिहार में 31 मार्च तक एक करोड़ उन्नीस लाख पुरुषों ने शपथ पत्र भरा है. पूर्ण शराबबंदी का संदेश घर-घर तक पहुंचा. नौ लाख लोगों ने दीवारों पर नारे लिखे. मैंने पटना से नारा लिखकर नहीं भेजा था. लोगों ने स्वत: यह सब किया. नारा लिखने में भी लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई. लोगों ने खुद नारे बनाए. शराबबंदी पर लोगों ने गीत बनाए. मैं जहां-जहां जाता हूं, लोग वह गीत सुनाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है. हजारों जगहों पर नुक्कड़ नाटक, गीत के कार्यक्रम आयोजित हुए और अभी भी हो रहे हैं. एक अप्रैल से पहले बिहार के हर घर तक संदेश पहुंच गया था कि बिहार में शराब बंद होने वाला है. यह भी कहा गया था कि 31 मार्च को जितनी भी शराब है, सब नष्ट कर दिया जाएगा. बड़े पैमाने पर बुलडोजर से शराब की बोतलों को नष्ट किए जाने की तस्वीरें भी जारी की गईं. बिहार में एक स्वस्थ माहौल बना. शुरुआत में यह नीति बनी थी कि गांव में देसी-विदेशी शराब सब बंद कर दिया जाए और शहरों में अभी कुछ दिन विदेशी शराब चालू रहे. मुझे ऐसा लगा था कि गांव में माहौल बन गया है, फिर शहरों में माहौल बनाया जाएगा. उसके बाद वहां भी चरणबद्ध तरीके से शराब बंद कर देंगे. एक अप्रैल से 90 प्रतिशत शराब की दुकानें बंद हो गईं. लेकिन शहरों में जब शराब की दुकानों पर महिलाओं ने विरोध दर्ज कराना शुरू किया तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ. अभी मैं सोच रहा था कि शहरों में वातावरण बनाएंगे तब शराब बंद करेंगे. यहां तो पहले से ही माहौल बना हुआ है. महिलाएं दुकान नहीं खुलने दे रही हैं. यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई इसलिए पांच अप्रैल से शहर में भी शराब की बिक्री बंद कर दी गई. देशी-विदेशी सारी शराब की दुकानें बंद हो गईं. बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई. बिहार ड्राई स्टेट बन गया.

लोग पूछने लगे कि सरकार ने फेजवाइज शराबबंदी की घोषणा की थी, अब इसे पांच दिन में ही लागू कर दिया. मैंने कहा कि किसने कहा था फेजवाइज और ये कब कहा था कि दूसरा फेज कितने दिनों में आएगा? विधानसभा में जब इस पर बहस चल रही थी तो विपक्ष ने पूछा कि विदेशी शराब कब बंद कीजिएगा, दूसरा फेज कब लागू होगा? मैं इसका जवाब नहीं देता था. मैं कहता था कि जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बंद हो जाएगा. समयसीमा बताने की कोई जरूरत ही नहीं है. मैंने अपना वादा पूरा किया और एक अप्रैल से देसी और पांच अप्रैल से शहरों में विदेशी शराब भी बंद कर दिया. बिहार में एक नया एक्साइज एक्ट आया और पूरे बिहार में लागू हो गया. 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की कोई बात ही नहीं है, पूरे सौ प्रतिशत शराबबंदी लागू हुई.

बिहार से लगी सीमा पर समस्या

बिहार से सटे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल

के बॉर्डर हैं. इन इलाकों में खूब शराब मिलती है. कुछ लोग आदत से लाचार हैं, जो उन इलाकों में जा कर शराब पी लेते थे. यूपी के बलिया इलाके में तो बकायदा शराब दुकानदारों ने खाट वगैरह का भी इंतजाम कर दिया कि आइए यहीं पीकर रात में आराम करिए. बिहार सरकार ने बॉर्डर एरिया में इतनी सख्ती बरती है कि ऐसे लोगों को मुश्किल हो रही है. प्रशासन को बेहतर इक्वीपमेंट्स उपलब्ध कराए गए. इस सब से दूसरे राज्यों में जा कर पीने वालों और शराब का दो नंबरी धंधा करने वालों में डर पैदा हो गया. पूर्ण शराबबंदी की घोषणा के हफ्ते भर के अंदर शराब ले जाते हुए एक एंबुलेंस को पकड़ा गया. तात्पर्य यह है कि एंबुलेंस की भी चेकिंग की जा रही है. दूसरी तरफ हमने कानून में यह प्रावधान किया कि कोई शराब बनाएगा, जहरीली शराब बनाएगा और इसे पीकर किसी की मौत होगी, वैसी स्थिति में शराब बनाने वाले को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा होगी. अगर शराब पीकर कोई ड्रामा करते हुए दिख जाए, तो उसे दस साल की सजा होगी. हर प्रकार से कानून को कड़ा बनाया गया. यह भी प्रावधान रखा गया कि कोई पुलिस या एक्साइज़ वाला जानबूझकर निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करेगा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी. एक उदाहरण बताता हूं. जीटी रोड बॉर्डर एरिया से जुड़ा हुआ है. वहां से एक शिकायत आई कि बिहार से बाहर के एक व्यक्ति को एक्साइज वालों ने तंग किया और उस आदमी से पैसे की मांग की. उसे धमकाया कि इतना पैसा दो नहीं तो एक्साइज एक्ट में बुक कर देंगे. जैसे ही ये शिकायत आई, इसकी जांच की गई. इस बात का प्रमाण मिला कि उस व्यक्ति ने एटीएम से पैसा निकाल कर एक्साइज वालों को दिया था. इस मामले में न सिर्फ मुकदमा हुआ बल्कि 48 घंटे के अंदर उन सातों एक्साइज वालों को बर्खास्त भी कर दिया गया.

पुलिस वालों ने भी शपथ पत्र भरा

लोग कहते थे कि शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस वाला मिलीभगत कर धंधा करने लगेगा. इसके लिए मैंने एक-एक थानेदार से यह शपथ पत्र भरवाया कि उनके इलाके में शराब का कोई धंधा नहीं होगा. मैंने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनके इलाके में शराब का धंधा पकड़ा गया, तो उन पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही दस साल तक उनकी किसी भी थाने में पोस्टिंग नहीं होगी. एक-एक पहलू पर गौर करते हुए कानूनी पक्ष पर काम किया गया. इसका परिणाम है कि अब बिहार में प्रभावशाली तरीके से शराबबंदी लागू है. मैं झारखंड या उत्तर प्रदेश, जहां भी गया, वहां के मुख्यमंत्रियों से बोला कि मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, अपनी टीम भेज दीजिए बिहार और खुद देख लीजिए कि समाज में क्या सार्थक परिवर्तन घटित हो रहा है. शराब से सबसे ज्यादा पीड़ित तो गरीब आदमी ही है. पहले गरीब अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में बर्बाद कर देता था. मान लीजिए कि एक गरीब आदमी ने एक दिन में 200 रुपये कमाए, तो कम से कम डेढ़ सौ रुपये शराब में खर्च कर देता था. शाम को शराब पीकर घर लौटने के बाद झगड़ा, मारपीट करता था. महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती थीं. बिहार में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत अभियान चलाया है इसके खिलाफ. अभी मैं शराबबंदी लागू करने के बाद चैन से नहीं बैठने वाला हूं और न ही अधिकारियों को चैन से बैठने दूंगा. बिहार में नौ डिवीजन हैं. सभी डिवीजन में मैंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का सम्मेलन किया, उनके अनुभव को सुना कि तब और अब में क्या बदलाव आए हैं? एक-एक महिला जब शराबबंदी को लेकर अपना अनुभव सुनाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है. महिलाएं जब बताती हैं कि किस तरह उनका परिवार उजड़ गया था, बर्बाद हो गया था, वे लड़ती थीं और जब शराबबंदी लागू हो गई है तो कैसे उनके जीवन में बदलाव आ गया है. महिलाएं बताती हैं कि उनके पति जब पहले आते थे, तो शराब पीकर आते थे और मारपीट करते थे, लेकिन अब वे शाम में बाजार से सब्जी लेकर आते हैं. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 20
18 जुलाई- 24 जुलाई 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

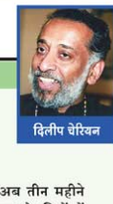
दिलीप चेरियन

जाधव को मिला सेवा विस्तार

कर्नाटक के मुख्य सचिव अरविंद जाधव 30 जून को रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनको अब तीन महीने का विस्तार मिला गया है. इस विस्तार से पर्यवेक्षकों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ. हाल के दिनों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कैबिनेट में फेरबदल के बाद असंतोष का सामना करना पड़ा था. सरकार में मंत्री पद न मिलने की वजह से नाराज विधायकों के समर्थकों ने गुस्से का प्रदर्शन किया था. मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले 14 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था. विद्रोह का आलम यह है कि विभिन्न विरोधी गुट लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं. इसके थमने का कोई संकेत नहीं दिखाई देता. इस पृष्ठभूमि में सिद्धारमैया ने सावधानी से चलने की कोशिश की है और अपने विश्वस्त मुख्य सचिव को बरकरार रखा है. जाधव, 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वह सिद्धारमैया सरकार में दूसरे मुख्य सचिव हैं जिन्हें सेवा विस्तार प्रदान किया गया है. सूत्रों का कहना है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव के रत्नप्रभा उनकी जगह लेंगे जब उनका कार्यकाल सितंबर में समाप्त होगा. ■

सीएम के खास होने का खास फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन, जो पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए को राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मुख्य सलाहकार नामित किया है. मुख्यमंत्री शायद यादव परिवार के भीतर आम सहमति के अभाव की वजह से नए मुख्य सचिव के बारे में फैसला नहीं ले सके. अभी कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार को कार्यवाहक मुख्य सचिव बना दिया गया है. हालांकि, वे पूर्णकालिक मुख्य सचिव के पद की दौड़ में आगे हैं. कुमार की एक अच्छी छवि है लेकिन पर्यवेक्षक इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि वे इस पद को पा सकेंगे. हालांकि, कुमार को मुख्यमंत्री का विश्वास हासिल है. सूत्रों का कहना है कि अखिलेश जल्द ही नए मुख्य सचिव की घोषणा कर सकते हैं. लेकिन निर्णय में इसलिए देरी हो रही है, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता इस शीर्ष पद के लिए अपने लोग चाह रहे हैं. जाहिर है, अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव अपने विश्वस्त बाबू दीपक सिंघल, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को मुख्य सचिव बनाना चाह रहे हैं. लेकिन मुख्यमंत्री अपने भरोसे के बाबू को इस पद पर लाना चाहते हैं. उम्मीद है ये सस्पेंस अल्पकालिक होगा और चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए इसलिए जल्द ही नए मुख्य सचिव की घोषणा हो जाएगी. ■

बाबू बनाम नेता

हालांकि नेताओं और बाबुओं के बीच सीमांकन स्पष्ट है, लेकिन कभी-कभी यह धुंधला हो सकता है. केरल में राज्य के परिवहन मंत्री ए के ससिनन्द्रान और परिवहन आयुक्त टामिन जे थाचांकरे के बीच एक बाबू द्वारा आदेश के ऊपर सार्वजनिक विवाद हो गया. इससे सवाल खड़ा हुआ कि क्या बाबू को जनता से जुड़े मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है. बाबू ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था कि ऐसे दुपहिया वाहन चालकों जो हेलमेट नहीं पहनते को पेट्रोल नहीं बेचा जाएगा. मंत्री ने कथित तौर पर इस आदेश को बेवकूफी भरा और अवैध कहा. हालांकि बाबू ने कहा वे ऐसा आदेश दे सकते हैं ताकि दोपहिया चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित हो सके. इस विवाद ने नौकरशाही को विभाजित कर दिया है. कुछ बाबू अपने सहयोगी के समर्थन में हैं. बाबू इससे भी नाखुश हैं कि मंत्री ने सार्वजनिक मंच पर परिवहन आयुक्त की निंदा की. ■

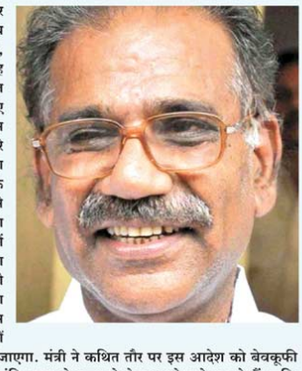

सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई

नीतीश कुमार

शराब पर पूर्ण रोक का अभियान सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है. वर्तमान सामाजिक विद्रूप को दूर कर बेहतर समाज स्थापित करना बड़ी चुनौती है. परिवर्तन की लड़ाई में आर्थिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शराब की आय को त्याज्य माना जाना चाहिए. यह नैतिक आय नहीं है. शराबबंदी को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि पांच हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कहां से होगी? मैंने कहा कि इसे हम नुकसान नहीं मानते हैं. शराब का व्यापार कोई नैतिक व्यापार नहीं है. अनैतिक व्यापार से राजकोष में आमदनी हो, यह अच्छी बात नहीं है. अगर सरकार को शराब के व्यापार से पांच हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती थी तो इसका मतलब था कि लोग कम से कम दस हजार करोड़ रुपये का शराब पी रहे थे. शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में हर साल दस हजार करोड़ रुपया बचेगा. जिसके पास पैसा बचेगा वो उसे खर्च भी करेगा. पैसा बाजार में ही जाएगा. किसी दूसरे काम में पैसा खर्च होगा. आदमी बेहतर खाना खाएगा, ढंग के कपड़े पहनेगा, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देगा. इससे भी तो व्यवसाय और बाजार बढ़ेगा. इसका मतलब है कि दूसरे तरीके के टैक्स के जरिए सरकार के खजाने में पैसा आएगा. क्या शराब को छोड़कर धरती पर कोई दूसरा व्यापार नहीं है?

बिहार में गन्ना बहुत होता है, चीनी मिलें हैं. पहले लोग गन्ना से स्प्रीट बनाते थे. मैंने कहा कि अब इससे एथेनॉल बनाएं. भारत में पेट्रोल में दस प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की अनुमति है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. हम बाहर से पेट्रोल मंगाते हैं, इसमें पैसा खर्च होता है. अगर एथेनॉल बनेगा और उसे पेट्रोल में मिलाया जाएगा, तो उतना पेट्रोल बचेगा. देश का पैसा बचेगा. स्प्रीट से बेहतर मूल्य एथेनॉल का मिलता है. चीनी मिल और डिस्टिलरी वालों ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, बस हमारे एथेनॉल को खरीद लिया जाए. इसके बाद बायर कंपनी के साथ मीटिंग में मैंने कहा कि सरकारी पॉलिसी के मुताबिक उनके लिए एथेनॉल खरीदना अनिवार्य है. मैंने यही बात यूपी में कही थी. बिहार से ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में उगता है. उत्तर प्रदेश में एथेनॉल का कम उत्पादन हो रहा है, जबकि इसकी उत्पादन क्षमता कहीं ज्यादा है. देश में जितनी एथेनॉल की जरूरत है, उतना उत्पादन नहीं है. मैंने अपने पहले कार्यकाल में पूरी कोशिश की थी कि गन्ने से एथेनॉल बनाया जाए. लेकिन, इससे संबंधित केंद्रीय कानून की वजह से ऐसा नहीं हो सका था. यूपी में स्प्रीट की जगह एथेनॉल का उत्पादन किया जाए तो यूपी की आमदनी और बढ़ जाएगी. आज यूपी में 17,000 करोड़ रुपये की कमाई शराब से मिलने वाले टैक्स से है. लोग पूछते हैं कि उसका विकल्प क्या होगा. विकल्प तो है. बिहार में दस हजार करोड़ का शराब का व्यापार था, उत्तर प्रदेश में तो लोग 25 से 30 हजार करोड़ रुपये का शराब पी रहे हैं. अगर यूपी के लोग 25-30 हजार करोड़ रुपये की शराब पीना छोड़कर दूसरी चीजों पर खर्च करेंगे, तो ये आमदनी कहां जाएगी? क्या इससे बाजार में, व्यापार में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा? पैसा अगर बाजार में रोटेट करे तो वहां की इकोनॉमी ग्रो करेगी और टैक्स के रूप में आमदनी भी होगी.

लिहाजा, जो यह कहता है कि शराब से होने वाली आमदनी का विकल्प नहीं है तो वह गलत बोल रहा है. यह सिर्फ लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है. मैंने भी कहा कि बिहार जैसे राज्य के विकास के लिए बहुत पैसा चाहिए. एक-एक पाई का महत्व है. जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी स्कीम में पैसा घटा दिया है और राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया है. अब मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्र, आईसीडीएस आदि में राज्य का अधिक पैसा लग रहा है. इसके अलावा राज्य की अपनी भी योजनाएं हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए. इसलिए शराबबंदी का फैसला काफी सोच-समझ कर लिया गया है. मैंने यह फैसला किया है कि इस अनैतिक व्यापार को नहीं चलने दूंगा. कई लोग यह भी बोलते हैं कि शराब पीना उनकी खाने-पीने की आजादी से जुड़ी हुई है. खाने-पीने की आजादी का मैं भी पक्षधर हूं, लेकिन भारत के संविधान में शराब पीने की आजादी नहीं है. यह मौलिक अधिकार का अंग नहीं है. इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कई बार फैसला आ चुका है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस बात का जिक्र है. शराब का व्यापार करना या शराब का सेवन करना मौलिक अधिकार नहीं है.

शराबबंदी अब अभियान है

देश के कई हिस्सों में शराबबंदी का अभियान चल रहा है. राजस्थान में स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा जी ने एक-एक पंचायत में वोट करवा कर वहां शराबबंदी करवाने की प्रस्ताव पास करवाया था. लेकिन इस पर राज्य सरकार ने अमल नहीं किया. इसलिए शराबबंदी को ले कर 14वीं बार उन्होंने आमरण अनशन किया और अपने प्राण त्याग दिए. वर्धा में तो पहले से शराबबंदी थी. नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली और चंद्रपुर में महिलाओं ने आंदोलन कर पिछले साल से शराबबंदी लागू करा दी है. सरकार ने यहां शराबबंदी तो लागू की, लेकिन अभी भी शराब की बिक्री जारी है. चंद्रपुर, वर्धा से महिलाओं का एक जत्था मुझसे पटना में मिला. किसान मंच के विनोद सिंह जी, जो वीपी सिंह से जुड़े हुए लोग हैं, ने भी मुझे लखनऊ बुलाया. वहां भी शराबबंदी को ले कर चर्चा हुई. राजस्थान से लेकर हर प्रदेश की चर्चा हुई. झारखंड के धनबाद में महिलाएं काफी समय से शराबबंदी के लिए अभियान चला रही हैं. बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद उनका गुस्सा बाहर आया. झारखंड में अब महिलाएं इतनी सक्रिय हो चुकी हैं कि वे शराब की दुकानों को बंद करा देती हैं, तोड़ भी देती हैं. मैं तो अपने यहां ये आह्वान करता हूं कि जहां भी कोई शराब की भट्ठी चलाने की कोशिश करे, उसे तोड़ दीजिए. पूरी सरकार आपके साथ है.

पूरे देश में जो माहौल बन रहा है उसे कितने दिन तक रोक सकते हैं. मैं मानता हूं कि इससे एक सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ेगी. सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं. लोगों के आचार, विचार, व्यवहार में परिवर्तन ही तो सामाजिक परिवर्तन है. महिलाएं कहती हैं कि पहले उनके पति जब शराब पीकर आते थे तो बड़े क्रूरूप दिखते थे, क्रूरता करते थे, लेकिन अब अच्छे दिखते हैं. यह सामाजिक परिवर्तन ही तो है. महिलाएं शराबबंदी की प्रणेता हैं. उनकी सभाओं में दस हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति होती है. महिलाओं का स्वयं सहायता समूह भी काफी संगठित हो रहा है और बहुत सकारात्मक भूमिका निभा रहा है. एक घटना मैं बताता हूं. पूर्णिया में पोस्टमॉर्टम करने वाला बिना दारू पीए पोस्टमॉर्टम कर ही नहीं सकता था. लोग उसे ज्यादा पैसा देकर किसी तरह पोस्टमॉर्टम करवाते थे. अब शराब छूटने के बाद वह बिलकुल स्वस्थ हो गया है और आराम से पोस्टमॉर्टम का काम कर रहा है. बिहार की महिलाएं अब इतनी जागरूक हैं कि वे इस पर नजर रख रही हैं कि शराब छूटने के बाद लोग कहीं अफीम या ड्रग्स तो नहीं लेने लगे हैं.

अपराध में भी कमी आई है

मैंने ग्राउंड लेवल पर एक सर्वे करवाया कि कौन लोग शराब पीते हैं? महिलाएं अपने घर की तो निगरानी कर ही रही हैं, साथ ही पड़ोसियों पर भी नजर रख रही हैं. उन्हें सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. बिहार में शांति का माहौल सृजित हो रहा है. मैंने शराबबंदी लागू होने के बाद अपराध का आंकड़ा निकलवाया. 1 अप्रैल से 25 जून 2015 तक का आंकड़ा और 1 अप्रैल से लेकर 25 जून 2016 तक का आंकड़ा निकलवा कर इसकी तुलना करवाई. पता चला कि संज्ञेय अपराध में साढ़े चौदह प्रतिशत, हत्या में 38 प्रतिशत, डकैती में 24 प्रतिशत, दंगा-फसाद में 56 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण जैसे मामलों में 70 प्रतिशत, बलात्कार के मामलों में 22 प्रतिशत, एससी-एसटी उत्पीड़न के मामले में 23 प्रतिशत की कमी आई है. सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है कि शराब पीने के बाद होने वाली सड़क दुर्घटना में 30 प्रतिशत की कमी आई है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी रोड एक्सीडेंट में कमी लाने की बात सोच ही रहे थे कि मैंने कहा कि गडकरी जी पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दीजिए तो सड़क दुर्घटना में 30 प्रतिशत की कमी खुद ही आ जाएगी. सबसे अधिक मौतें शराब पीने के बाद होने वाले रोड एक्सीडेंट से होती हैं. बिहार में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में भी 33 प्रतिशत की कमी आ गई. इसके क्या लाभ हैं? एक महत्वपूर्ण लाभ तो यह भी है कि पहले बिहार में जहां दरवाजे तक बारात पहुंचने में घंटों लगते थे, अब कम समय लगता है. पहले बारात में चलने वाले लोग शराब पी लेते थे. एक ही जगह नाच रहे हैं तो नाच रहे हैं. लड़की पक्ष वाला कुछ बोल नहीं पाता था. अब, दरवाजे तक पहुंचने में देर नहीं लगती. तुरंत ढोल-बाजा बजाया और लग गया दरवाजा. मैं अभी झारखंड में अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, जो पहले मिनिस्टर थे, की बेटी की शादी में गया था. हम सारे लोग डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे थे. बारात आ ही नहीं रही थी. पूछने पर बताया जाता था कि बस दस मिनट में बारात लग जाएगी. मुझे सवा ग्यारह बजे धनबाद से पटना ट्रेन से लौटना था. मैंने उनसे कहा कि देखिए, 200 मीटर दूर से आने वाली बारात को इतना समय लग रहा है, झारखंड में भी शराबबंदी लागू करवा दीजिए तो पांच मिनट में बारात लग जाएगी. यानी, शराबबंदी का एक ये भी लाभ तो है ही. अब तो जो पीने वाले लोग थे, वो भी आज मेरी तारीफ कर रहे हैं. तीन महीने के बाद अब उनकी आदत भी छूट गई है. लोग खुश हैं कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य तो संवर गया. यानी, शराबबंदी के दूरगामी फायदे भी हैं.

शराब के साथ योग नहीं हो सकता

शराबबंदी के पक्ष में तो सारे धर्म हैं. कौन सा धर्म है जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है? विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग और जनांदोलनों से जुड़े समूह भी इसके समर्थन में हैं. मेधा पाटेकर जी भी शराबबंदी के हक में हैं. ये लोग देश के अन्य राज्यों में भी शराबबंदी लागू करने के लिए बैठकें कर रहे हैं. आज तक देश में जितने विचारक हुए, गांधी जी, अंबेडकर साहब, जेपी, लोहिया, वीपी सिंह, मोरारजी भाई देसाई, सब शराबबंदी के पक्षधर थे. ये कौन लोग हैं जो शराब चाहते हैं, शराब के पक्षधर हैं? गुजरात में तो स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी शराबबंदी को जारी रखा था. मेरी अपनी समझ है कि प्रधानमंत्री जी भी शराबबंदी के पक्षधर हैं. मैं उनसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं. मैं बताना चाहता हूं कि हमलोग भी वर्षों से योग करते हैं. बिहार के मुंगेर में योग का इंटरनेशनल स्कूल है लेकिन शराब के साथ योग कभी पूर्ण नहीं हो सकता है. प्रधानमंत्री जी, अगर आप सचमुच योग के हिमायती हैं तो शराबबंदी करवाइए. देशभर में नहीं तो कम से कम भाजपा शासित राज्यों में ही शराबबंदी लागू करवा दीजिए.

1917 में गांधी जी ने निलहों पर अत्याचार के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया था. चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही इस देश में आजादी की लड़ाई ने जन आंदोलन का रूप लिया था. चंपारण सत्याग्रह का सौवां साल शुरू हो गया है. मैंने सोचा कि चंपारण सत्याग्रह के सौवें साल में शराबबंदी लागू कर गांधीजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए. देशभर के लोगों को शराबबंदी के सत्याग्रह से जुड़ना चाहिए. मैं समझता हूं कि देशवासियों का भी दायित्व है कि वे एक वातावरण बनाएं. इस काम में जो भी स्वयंसेवी संगठन, आंदोलनकारी संगठन, महिलाओं का समूह लगा है, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं. लोग लगातार मुझसे मिलने आ रहे हैं. वे अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में शराबबंदी के लिए मुहिम चलाना चाहते हैं. मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सबलोगों के साथ हूं, जो शराब के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं. पिछले दिनों मैं उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में गया था. वहां शराबबंदी के लिए मुहिम चलाई जा रही है. लोगों ने मुझसे कहा कि जेवर तो छोटी जगह है, वहां क्या करने जाएंगे? मैंने कहा कि जेवर तो फिर भी एक कस्बा है, शराबबंदी के लिए अगर किसी गांव में भी जाना पड़ा तो मैं जाने के लिए तैयार हूं. इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

वैकल्पिक आय और रोज़गार की संभावना

यह सब काम मैं सम्मान पाने के लिए नहीं कर रहा हूं. यह तो एक वैचारिक प्रतिबद्धता है. पूर्ण शराबबंदी से ही भारत की तरक्की हो सकती है. बिहार से शुरू हुआ कारवां अब थमेगा नहीं. शराब के व्यवसाय से जुड़े लोगों को समय रहते अच्छे व्यवसाय की ओर शिफ्ट कर लेना चाहिए. शराब बेकार की चीज है. लोगों के जीवन को बरबाद करने वाला व्यवसाय है और कुछ लोग इसे रोजगार से जोड़ कर देखते हैं. बिहार में भी कुछ लोगों ने शुरुआत में जुलूस निकाला और कहा कि शराब की दुकान बंद होगी तो रोजगार छीन जाएगा. मैंने कहा कि बिहार में सुधा दूध का काउंटर खोल लीजिए. मैं पूर्णिया कमिश्नरी एक कान्फ्रेंस में गया था. महिलाएं मुझे वहां एक गांव में ले गईं. इस गांव में पहले लोग शराब बनाते थे. उस गांव के कई परिवार बेरोजगार होने से डरे हुए थे. ऐसे सभी परिवारों को गाय खरीदने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया गया. उनसे कहा गया कि अब दूध का काम कीजिए. नौ परिवार की महिलाओं को गाय खरीदने के लिए खुद मैंने अपने हाथ से चेक दिए. उन लोगों ने खुशी-खुशी दूध का धंधा शुरू कर दिया है. आज वे सब खुश हैं. शराबबंदी के बाद भी वैकल्पिक आय और रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड त्रासदी
हिमालय की चेतावनी है

हिमालय क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन की घटना कोई अनोखी और नई चीज़ नहीं है. बादल का फटना मौसम विज्ञान से जुड़ी एक ऐसी घटना है जो पहाड़ों पर हमेशा होती रहती है और आगे भी जारी रहेगी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान बादल फटने की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से भूस्खलन भी पहले के मुकाबले अधिक हो रहे हैं.

शफीक आलम

उत्तराखंड में एक बार फिर तेज़ बारिश और बादल फटने की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. राज्य के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में बीते 1 जुलाई को लगातार बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया, हालांकि खुफ़ रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या इससे अधिक बताई जा रही है. चूंकि सबसे अधिक बारिश चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में हुई इसलिए सबसे अधिक नुकसान इन्हीं जिलों में हुआ है. हालांकि तेज बारिश की वजह से राज्य की छोटी और बड़ी नदियों में आए उफान के बाद पानी नीचे उतर गया और उत्तर काशी में गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आए मलबे को साफ़ करने के बाद चारधाम की यात्रा शुरू कर दी गई. लेकिन अचानक बारिश और बादल फटने के बाद जिस प्रकार नदियों का जल स्तर बढ़ा उसने उत्तराखंड के लोगों को एक बार फिर जून 2013 जैसी त्रासदी के खौफ में जीने को मजबूर कर दिया. मौसम विभाग ने खतरे को भांपते हुए चेतावनी जारी कर दी जिसका मतलब होता है कि आपदा की वजह से त्रासदी आ सकती है. लिहाजा अधिकारियों को किसी भी तरह की त्रासदी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए. अब सवाल यह उठता है कि 2013 के बाद फिर उसी तरह की त्रासदी क्यों दस्तक दे रही है? क्या वैसी तबाही फिर आ सकती है? क्या हिमालय में मानवीय हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से बड़ी त्रासदी आ सकती है?

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना के जवान स्थानीय लोगों की मदद करते हुए.

अगर हम इन सवालों के जवाब जानना चाहें, तो सवालों के जवाब हैं हां. क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर पिछले वर्षों के दौरान हुए अध्ययन और बार-बार प्रकट होने वाली आपदाएं यह साबित करती हैं कि मानवीय हस्तक्षेप से की वजह से यह सब कुछ हो रहा है. हिमालय में जहां भूस्खलन की संख्या में वृद्धि हुई है, तो वहीं बादल फटने की घटनाएं भी पहले के मुकाबले अधिक हो रही हैं और उसका नतीजा यह है कि तबाही अब भयानक रूप ले रही है. बनारस हिंदु विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक डॉ सरफ़राज़ आलम इसके लिए जलवायु परिवर्तन और प्रकृति से मानव हस्तक्षेप को मानते हैं. उनका कहना कि पिछले पिछले कुछ सालों में केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे हिमालय में विकास के नाम पर बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं, जिसका नतीजा प्राकृतिक आपदा से आने वाली तबाही के रूप में हमारे सामने है. उनका कहना है कि उत्तराखंड में गरीबी है और वहां के लोगों को रोजी-रोटी की तलाश में अपना घर-बार छोड़ कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है. यहां हुए निर्माण कार्यों की वजह से स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर तो पैदा हुए हैं, लेकिन इसके नतीजे में उन्हें भूस्खलन और बाढ़ की तबाही के रूप में प्रकृति की मार झेलनी पड़ रही है. यानी उत्तराखंड के लोगों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति बनी हुई है.

हिमालय क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन की घटना कोई अनोखी और नई चीज़ नहीं है. बादल का फटना मौसम विज्ञान से जुड़ी एक ऐसी घटना है जो पहाड़ों पर हमेशा होती रहती है और आगे भी जारी रहेगी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान बादल फटने की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से भूस्खलन भी पहले के मुकाबले अधिक हो रहे हैं. इसके लिए जहां हिमालय क्षेत्र में हो रहे अंधाधुंध निर्माण कार्यों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं मौसम के बदलाव को भी इसकी वजह बताया जा रहा है. राज्य में हो रहे निर्माण कार्यों से पैदा हुई स्थिति को राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी स्वीकार कर चुके हैं. वह कहते हैं कि हमारे पहाड़ कभी इतने कमज़ोर नहीं थे, कच्ची सडकों पर भारी वाहनों के चलने से ये कमज़ोर हो गए हैं. उनकी इस बात की पुष्टि डॉ सरफ़ाज़ भी करते हैं, उनका कहना है कि

यदि हिमालय में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भूकंप आता है तो उससे देश को एक बड़ी भयानक त्रासदी से गुजरना पड़ सकता है. अब सवाल यह है कि क्या इस त्रासदी से बचाव मुमकिन है? तो इस का जवाब है हां मुमकिन है. लेकिन देश के नीति-निर्माताओं को शायद इस भयानक स्थिति का अहसास नहीं है.

पहाड़ काट कर बनाई गई सड़कों पर वाहनों के लगातार चलने की वजह से गुरुत्वाकर्षण असंतुलन पैदा होता है. जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि होती है.

हिमालय और मानसून का बहुत ही गहरा रिश्ता है और ये दोनों एक दुसरे पर आश्रित हैं. अगर हिमालय नहीं होता तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून नाम की कोई चीज़ नहीं होती और वहीं मानसून हिमालय की नदियों और हिमनदों को संचालित रखने में अहम किरदार अदा करता है. जैसा कि पहले भी कहा गया कि विकास परियोजनाओं ने पर्यत के स्वाभिक स्वरूप को बिगाड़ दिया है. मौसम का मिजाज बदलने में भी इनकी अहम भूमिका है. होली गंगा नाम की किताब के लेखक कौशल किशोर कहते हैं कि प्रकृति अपनी नैसर्गिक अवस्था में वायुमंडल में जमा वाष्प को समान रूप से वितरित करती है. जबरन किए गए मानवीय हस्तक्षेप का नतीजा बादलों के फटने के रूप में सामने आता है. आज हिमालय में जलविद्युत परियोजनाओं के साथ ही अंधाधुंध विकास के अनेक नमूने मौजूद हैं. अकेले उत्तराखंड में 70 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. भविष्य में ऐसी आपदाओं की संख्या और उसकी विभीषिका और बढ़ेगी ही. दरअसल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के तहत राज्य में 45 पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं और कम से कम 199 छोटी और बड़ी परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं 260 मीटर ऊंचे टिहरी डैम के रिजरवायर में दरार आने की रिपोर्टें भी आ चुकी हैं. हिमालय में स्थित इस बड़े डैम के बारे में यह दावा किया जाता है कि यह रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप बर्दाश्त कर सकता है. लेकिन 2015 में आए नेपाल के भूकंप ने इस डैम की सुरक्षा पर एक बार फिर विशेषज्ञों को दुविधा में डाल दिया है और इसकी सुरक्षा को लेकर अब सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं.

बहरहाल मोनटाना यूनिवर्सिटी की जियोलॉजी की प्रोफेसर रेबेका बेनडिक्ट ने वर्ष 2015 में नेपाल में आए भयानक भूकंप और उससे पहले के भूकंपों का अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंची हैं कि हिमालय में रिक्टर स्केल पर 8 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है. अब ऐसी स्थिति में जब पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिकों की लगातार चेतावानी के बाद भी हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम के साथ मानवीय छेड़छाड़ जारी है. यदि हिमालय में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भूकंप आता है तो उससे देश को एक बड़ी भयानक त्रासदी से गुजरना पड़ सकता है. अब सवाल यह है कि क्या इस त्रासदी से बचाव मुमकिन है? तो इस का जवाब है हां मुमकिन है. लेकिन देश के नीति-निर्माताओं को शायद इस भयानक स्थिति का अहसास नहीं है. इसलिए वे हिमालय में चल रहे अंधाधुंध विकास कार्य को रोकने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं और हिमालय की बार-बार दी जा रही चेतावनी को नज़रंदाज़ कर रहे हैं.■

आसमानी बिजली

जानकारी से ही बचाव संभव

चौथी दुनिया ब्यूरो

मानसून आते ही इंसान पर एक आसमानी कहर टूटता है, जिसका नाम है बिजली. एक बिजली जहां जीवन में रौशनी लाती है, वहीं आसमानी बिजली की कौंध इंसानी जीवन में अंधेरा लेकर आती है. आम लोग इसे दैवीय आपदा समझ सहम जाते हैं, लेकिन सच ये है कि आसमानी बिजली के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है. बिजली बनने व उसके गिरने की प्रक्रिया आदि पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है. इस बारे में दुनिया भर में अध्ययन हो रहे हैं. आसमानी बिजली से जान माल के नुकसान से बचने के लिए वैज्ञानिक उपाय भी बताते हैं. हाल में बिजली गिरने से बिहार, झारखंड और मध्यप्रदेश में करीब 80 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए. इस प्राकतिक आपदा में 13 पशुओं की भी मौत हुई. बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद में आसमानी बिजली इंसानों पर कहर बनकर टूटी. झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी अलग-अलग जगहों पर बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई.

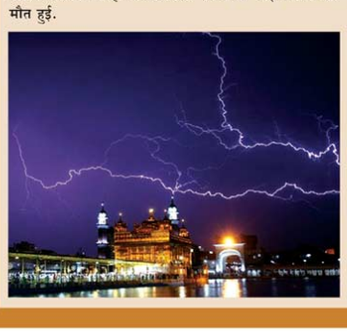

क्या है आसमानी बिजली: जब ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनाती है, तब इन बादलों के अंदर गर्म हवा की गति और नीचे ठंडी हवा होने से बादलों में धनावेश ऊपर की ओर एवं ऋणावेश नीचे की ओर होता है. बादलों में इन विपरीत आवेशों की आपसी क्रिया से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जिससे आसमानी बिजली उत्पन्न होती है. बादलों के अंदर विद्युत आवेश की मात्रा को फिल्ड मिल नामक यंत्र से मापा जाता है. बादलों की टकराहट या उनमें उपस्थित जल कणों के आपस में टकराने से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है. बिजली गिरने की अधिकतर घटनाएं किसी पेड़ या बिजली के खंभे के आसपास होती हैं. बादलों के अंदर उत्पन्न आवेश धरती की ओर आता है, तब इससे भवन और विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है. आसमानी बिजली गिरने पर बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धरती में पहुंचता है. धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, इसलिए इस घटना के दौरान विद्युत उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने का अधिक खतरा रहता है. बिजली में कुछ हजार से लेकर करीब दो लाख एम्पियर तक का धारा प्रवाह हो सकता है.

बिजली के प्रकार: बिजली के कई प्रकार होते हैं. एक है विस्तृत बिजली. विस्तृत बिजली काफी विस्तृत क्षेत्र पर होती है और इसका अविरल प्रकाश बादलों पर काफी दूर तक फैल जाता है. बिजली के दूसरे प्रकार को धारीदार या रेखावर्ण बिजली कहते हैं. इसमें एक या अधिक प्रकाश रेखाएं, सीधी या टेढ़ी इधर-उधर दौड़ती हुई प्रतीत होती हैं. इसमें विद्युत विसर्जन बादल से बादल में, बादल से धरती में अथवा बादल से वायुमंडल के बीच होता है. तीसरे प्रकार की बिजली को गेंद बिजली कहते हैं. यह गेंद की शक्ल में धरती की तरफ आती है. जैसे-जैसे यह धरती की ओर आती है, इसकी गति कम होती जाती है.

कैसे बचें आसमानी बिजली से: जब बिजली गिरने की आशंका हो या गिर रही हो तब जंगल में पेड़ के नीचे न खड़े हों. बिजली के खंभों और वृक्षों से दूर रहें. धात्विक वस्तुओं से भी दूरी बनाए रखें. विद्युत उपकरणों का उपयोग न करें. आपातस्थिति को छोड़कर मोबाइल, टेलीफोन का उपयोग नहीं करें. जंगल में होने पर निचले स्थान या घाटी क्षेत्र में रहें, लेकिन वहां आकस्मिक बाढ़ से भी सावधान रहें. किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े न हों. किसी जल स्रोत में तैर या नहा रहे हों तो उससे निकल कर भूमि पर आ जाएं. यदि आपके सिर के बाल खड़े हो रहे हों तो आपके आसपास खतरा हो सकता है. किसी अनहोनी से बचने के लिए अपने हाथों से बालों को ढककर सिर को घुटनों में छुपा लें. विद्युत से बचाव के लिए भवनों, सार्वजनिक इमारतों के ऊपर तड़ित चालक लगवाना चाहिए. बिजली गिरने के बाद तुरंत बाहर न निकलें. अधिकतर मौत तूफान गुज़र जाने के 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से होती है. अगर बादल गरज रहे हों, और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है. ऐसे में नीचे दुबककर पैरों के बल बैठ जाएं, अपने हाथ घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच. इस मुद्रा में आपका ज़मीन से कम से कम संपर्क होगा. छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें. धातु के माध्यम से बिजली आपके शरीर में घुस सकती है.

पीड़ित व्यक्ति की कैसे करें मदद: अगर किसी पर बिजली गिर जाए, तो तत्काल डॉक्टर की मदद मांगें. ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. अगर किसी पर बिजली गिरी है तो तत्काल उसकी नब्ज जांचें और अगर आप प्रथम उपचार देना जानते हैं तो अवश्य दें. बिजली गिरने से अक्सर दो जगहों पर जलने की आशंका रहती है. एक तो वो जगह जहां से बिजली का झटका शरीर में प्रवेश किया और जिस जगह से उसका निकास हुआ जैसे पैर के तलवे. ऐसा भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हों या उसे सुनना या दिखाई देना बंद हो गया हो. इसकी जांच कर नजदीकी चिकित्सक के पास पहुंचाएं.■

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव में उग्र हिंदूवादी धारा पर लौटेगी भाजपा!

महज़ संयोग नहीं है योगी से योग

भारतीय जनता पार्टी के पत्ते धीरे-धीरे खुलने लगे हैं. इलाहाबाद में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ठीक पहले भाजपा कैराना का कार्ड सियासत की बिसात पर खेल देती है और उस पर जब बहस-मुबाहिसा तेज होता है तो बूथ अध्यक्षों के समेलन में उग्र हिंदूवादी नेता महंत योगी आदित्यनाथ को महिमामंडित करने लगती है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कैराना पर कसमें खाईं-खिलवाईं और उन्हीं शाह ने गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की सभा में कहा कि योगी का नाम लेने मात्र से कार्यकर्ताओं में रोमांच होने लगता है. कुछ दिन पहले तक उग्र हिंदूवादी रवैये से दूर रहने की बातें कहने वाले भाजपा नेता फिर से कट्टर लाइन पर आते दिख रहे हैं...

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी उग्र हिंदूवादी धारा पर लौटेगी? गोरखपुर क्षेत्र के बूथ सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जिस तरह का रुख दिखाया, उससे तो यही संकेत मिलता है. बिहार चुनाव के बाद भाजपा सर्वधर्म-समभाव के भाव में दिखने लगी थी, लेकिन असम चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद भाजपा अपने तेवर बदलती दिखाई दे रही है. अमित शाह के दस्ते के विश्वासी सदस्य उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने हाल ही 'चौथी दुनिया' से हुई खास बातचीत में भाजपा के धर्मनिरपेक्षीय रुझान की तरफ सरकने का संकेत देते हुए साफ तौर पर कहा था कि राम मंदिर भाजपा का चुनावी मुद्दा नहीं है. ऐसा नहीं है कि उस साक्षात्कार में बंसल ने यूं ही कह दिया था कि भाजपा को अपनी राजनीति व्यापक करनी होगी. बंसल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अबतक सम्पूर्णता की राजनीति नहीं कर रही थी. ऐसी राजनीति, जिसमें हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमान, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी शरीक रहें. उस समय बातचीत का ऐसा ही टोन करीब-करीब सारे वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं का होने लगा था. लेकिन कैराना-फार्मूले ने अचानक ही सामने आकर यह बताया कि भाजपा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हिंदूवादी लाइन ही अख्तियार करेगी. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इलाहाबाद बैठक के दरम्यान आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मंच से ही अमित शाह ने जिस तरह कैराना का मसला उछाला था और सभा में शामिल लोगों से इस मसले पर हुंकार-समर्थन लिया था, उससे भाजपा की यूपी लाइन स्पष्ट हो गई थी. गोरखपुर में बूथ प्रमुखों के सम्मेलन में अमित शाह ने इस पर मुहर लगा दी, जब उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने मात्र से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों और भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोमांच आ जाता है. गोरखपुर क्षेत्र के 27 हजार बूथ प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने गोरखधाम पीठ के मुख्य महंत योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में ढेर सारी बातें कहीं. शाह ने यह प्रशंसा संयोगवश तो की नहीं होगी. सांगठनिक सभा-सम्मेलनों में संगठन के शीर्ष नेता ने सोच-समझ कर ही अपनी बात रखी होगी.

पूर्वी उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है. गोरखपुर क्षेत्र में 13 लोकसभा क्षेत्र और तकरीबन 65 विधानसभा क्षेत्र हैं. गोरखपुर क्षेत्र की 12 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है. आजमगढ़ की एक सीट मुलायम सिंह यादव ने जीती थी और रमाकांत यादव चुनाव हार गए थे. गोरखपुर सम्मेलन में सभी सांसद और इस क्षेत्र के सभी विधायक भी मौजूद थे. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा संगठन की तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव मौर्य, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य शिवप्रताप शुक्ल समेत कई दिग्गज शामिल हुए. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मंच पर आने के पहले गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ का भाषण चल रहा था, लेकिन शाह के आते ही भाषण थम गया. बाद में शाह ने फिर से योगी को बुला कर पूरा भाषण सुना. अमित शाह ने अपने संबोधन में जैसे ही कहा कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेते ही लोगों में रोमांच हो जाता है, लोग जोश से भर जाते हैं, तो सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ता योगी के समर्थन में नारे लगाने लगे, इससे माहौल असहज भी हुआ और शाह को थोड़ी नाराजगी भी हुई. अमित शाह ने अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ के कैराना वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि भाजपा कैराना में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ेगी. शाह ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार पर कई तीखे प्रहार किए और यहां तक कह डाला कि गायों की तस्करी करने वाले सबसे ज्यादा माफिया यूपी के ही हैं. शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार

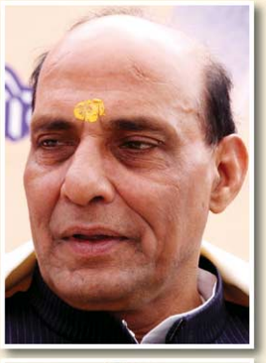

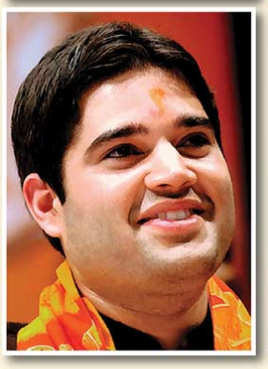

लाने के लिए सबको मिलकर सपा को बाहर करना होगा. शाह ने विकास के मसले भी उठाए और सपा सरकार के पिछड़ने के आंकड़े सामने रखे. उन्होंने गोरखपुर में एम्स स्थापित करने का मसला भी उठाया जिसमें यूपी सरकार अड़ंगे खड़े कर रही है. शाह ने कहा कि अगर राज्य सरकार एम्स के लिए जगह नहीं भी देगी तो मोदी सरकार कोई न कोई तरीका निकालेगी. शाह बोले कि मोदी खाद की फैक्ट्री तो खुलवा सकते हैं पर चीनी मिलें फिर से खोलने के लिए राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है. अमित शाह ने मायावती पर भी निशाना साधा और कहा कि बसपा छोड़कर जाने वाले नेताओं की ही खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं. ऐसा लगता है कि चुनाव तक बहनजी अकेली ही रह जाएंगी.

विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक समीक्षाओं और अर्थायनों में लगे सियासी पंडित योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक प्रशंसा के भी निहितार्थ निकालने लगे हैं. उनका मानना है कि अमित शाह विधानसभा चुनाव में यूपी का चेहरा कौन होगा, इस कयास पर विराम लगा गए हैं. लेकिन यह विचार भी कयास ही है, तबतक, जबतक कि आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से कोई घोषणा न हो जाए. पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस पर बिहार चुनाव के बाद से ही चर्चा होने लगी थी और इसमें कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ, स्मृति इरानी, वरुण गांधी और महेश शर्मा तक के नाम चल गए. लेकिन अब तक ये सब नाम चर्चाओं तक ही सीमित रहे हैं. कल्याण और राजनाथ को अलग रखें तो चर्चा में शुमार नामों में योगी का नाम ही सबसे मजबूत रहा, क्योंकि योगी की राजनीतिक जमीन भी काफी मजबूत है. योगी

> **"भाजपा के कैराना-फार्मूले ने अचानक ही सामने आकर यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हिंदूवादी लाइन ही अख्तियार करेगी."**

1998 में पहली बार 26 साल की उम्र में ही गोरखपुर से सांसद बने और तब से लगातार जीत रहे हैं. वे पांचवीं बार सांसद हैं. योगी भाजपा के लिए सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा हैं. उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है. अपने फायरब्रांड बयानों के कारण उन्हें ध्रुवीकरण का विशेषज्ञ माना जाता है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह योगी के नाम पर अपनी सहमति भी दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी आखिरी सहमति नहीं मिली है. यूपी के राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ बसपा और सपा को कड़ी चुनौती दे सकते हैं.

शुरुआती दौर में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी को संघ का समर्थन मिला, लेकिन बाद में यह फीका पड़ गया. मुखर वक्ता और विपक्षियों का सामना करने की मजबूत क्षमता के कारण स्मृति को संघ ने पसंद किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक स्थितियों में स्मृति का नाम प्रासंगिक नहीं रहा. स्मृति के बाद सुल्तानपुर के सांसद वरुण गांधी का नाम खूब तेजी से चला. वरुण 2009 में पीलीभीत से सांसद चुने गए थे. 2009 में ही मुस्लिम विरोधी बयान देकर वरुण सुर्खियों में आ गए थे. लेकिन धीरे-धीरे वरुण गांधी का नाम वृष्टिछाया-क्षेत्र में चला गया, इसके लिए वरुण भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का वैकल्पिक चेहरा बनने के लिए उन्होंने जो हथकंडे अपनाए, उसे भाजपा आलाकमान ने पसंद नहीं किया. विधानसभा चुनाव में यूपी के चेहरे के बतौर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का नाम भी चला. कभी कल्याण उत्तर प्रदेश का कट्टर हिंदूवादी चेहरा हुआ करते थे और प्रदेश के पिछड़ा वर्ग खास कर लोधी समुदाय में उनकी खासी पकड़ है. लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण कल्याण का विधानसभा चुनाव में जुझारू इस्तेमाल संभव नहीं है. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा में आए. लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह की छवि प्रदेश में अच्छी है और उन्हें भाजपा का धर्मनिरपेक्षीय चेहरा भी माना जाता है. राजनाथ सिंह का नाम अभी पार्टी में विचार में है, लेकिन निर्भर करता है कि भाजपा चुनाव में कौन सा लाइन चुनती है. केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का नाम भी संभावित चुनावी चेहरे के रूप में चर्चा में आया था, लेकिन पश्चिम में जाना-पहचाना चेहरा मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उतना घरेलू नहीं है. पिछड़ा समुदाय (लोध) की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती और ब्राह्मण सांसद व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के नाम भी चर्चा और सुगबुगाहटों में रहे हैं. उत्तर प्रदेश में चुनावी चेहरे की कवायबाजी का समय समाप्त हो रहा है, अब समय फैसलाकुन है.

जो बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर निकले हैं, उनका भाजपा में स्वागत करने की भी तैयारियां चल रही हैं. इन तैयारियों में पार्टी की वह रणनीति भी शामिल है कि उन्हें चुनाव में किस तरह का दायित्व दिया जाना है. बसपा से जुड़े बौद्ध भिक्षुओं को भी भाजपा के छत्र में लाने की पूरी तैयारी है. समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेताओं के भाजपा में आने की चर्चा है. जल्दी ही इस रोमांच का भी पटाक्षेप होने वाला है. जातीय समीकरणों के मुताबिक नेताओं के चेहरे फिट करने की कवायद तेज गति से चल रही है. केशव मौर्य को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना इसी रणनीति का हिस्सा था. कोइरी समुदाय के लोग प्रदेश में खासी संख्या में हैं, लेकिन इस समुदाय की राजनीतिक उपेक्षा होती रही है. इसे भाजपा अपने पक्ष में दुरुस्त करना चाहती है. सामाजिक-राजनीतिक तानाबाना दुरुस्त करने के इरादे से ही मुख्तार अब्बास नकवी को वाया झारखंड राज्यसभा पहुंचाया गया और ब्राह्मण नेता शिवप्रताप शुक्ल को राज्यसभा जाने का मौका मिला. इस बार भाजपा के जो जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष चुने गए, उसमें भी इस पहलू का विशेष ध्यान रखा गया. यही वजह है कि पहली बार भाजपा के 94 जिला और नगर अध्यक्षों में पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के 44, ब्राह्मण जाति के 29, ठाकुर जाति के 10, वैश्य जाति के नौ और दलित समुदाय के चार लोग शामिल हैं. पिछले लंबे अर्से से पार्टी के जिला और नगर अध्यक्ष अधिकतर ब्राह्मण और उसके बाद राजपूत जाति के हुआ करते थे.

पार्टी ने सांगठनिक ढांचे में फेरबदल इसलिए भी किया क्योंकि उत्तर प्रदेश के पिछले तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन काफी लचर रहा. वर्ष 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सपा और बसपा के बीच ही रहा. इसमें भाजपा और कांग्रेस कहीं नहीं रही. भाजपा तीसरे स्थान पर रही. वर्ष 1991 में भाजपा को 221 सीटें मिली थीं. भाजपा का यह अच्छा प्रदर्शन था. 2012 के चुनाव में भाजपा को 15 प्रतिशत वोट मिले जो बसपा के आधे थे. 2012 के विधान सभा चुनाव में 15 फीसदी वोट हासिल करने वाली भाजपा को अचानक 2014 के लोकसभा चुनाव में 42.63 प्रतिशत वोट मिले. लोकसभा चुनाव की जीत के दबाव-मनोविज्ञान से गुजर रही भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ मिल कर उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है. क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला चल रहा है. पूरे प्रदेश में सक्रियता है. रैलियों और सभाओं की अभी से लिस्ट तैयार हो रही है. इसमें वक्ता कौन होंगे, आयोजन की जिम्मेदारियां किन्हें दी जाएंगी और फंड मैनेजमेंट कैसे होगा, इस सबकी कवायद चल रही है. भाजपा का प्रदेश स्तरीय सांगठनिक चयन का काम भी खबर छपते-छपते पूरा हो जाने की संभावना है. चुनावी रैलियों को मुख्य तौर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह संबोधित करेंगे. खास रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

बाहर निकलने को बेताब जाति जनगणना का जिन्न

गत वर्ष इन्हीं दिनों भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी. तब आर्थिक जनगणना के परिणाम, जो बिहार के संदर्भ में भी चिंताजनक थे, पर बोलने से राजनेता बचते रहे. पर जाति जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किए जाने को मुद्दा बना दिया. जाति जनगणना की रिपोर्ट के प्रकाशन की मांग को लेकर राजद सुप्रीमो ने राजभवन मार्च किया, सैकड़ों लोगों के साथ गिरफ्तारियां दीं और उन पर मुकदमा भी किया गया था.

सरोज सिंह

जाति जनगणना और आरक्षण का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकलने को तैयार है. बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के दोनों बड़े दल-जनता दल(यू) व राष्ट्रीय जनता दल- के सुप्रीमो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद नए सिरे से इसे बोतल से बाहर निकालने की तैयारी में हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सांख्यिकी विषय पर पटना में संपन्न एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की पुरजोर मांग की, तो राजद सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण के मुद्दों को नए सिरे से उठाया. उन्होंने प्रधानमंत्री को चेताया कि आरक्षण पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बिहार के सुविख्यात शोध संस्थान आद्री की ओर से आयोजित संगोष्ठी में उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत देश-विदेश के नामचीन अर्थशास्त्री मौजूद थे. संगोष्ठी में मौजूद सभी वक्ताओं ने भारत के सामाजिक सांख्यिकी और उसके संग्रहण के मौजूदा तौर-तरीकों पर असंतोष जताया. इन सभी ने मौजूदा हालात में सुधार लाने पर जोर दिया ताकि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थानों व नीति-निर्धारकों का इन आंकड़ों में भरोसा पैदा हो सके. इसके बरअक्स, नीतीश कुमार ने नीति निर्धारण में उपयुक्त आंकड़ों की जरूरत को तो रेखांकित किया ही, साथ ही इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग कर अपना राजनीतिक एजेंडा भी पेश कर दिया. देश में यह जनगणना तीन-चार वर्ष पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है. उनका कहना था कि 1931 की जाति जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर ही अब तक जातियों को लेकर कोई बात की जाती है. इन 85 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है. अनुसूचित जाति- जनजाति की जनगणना तो होती है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की कोई जनगणना नहीं होती है. भारत सरकार ने पिछले वर्षों में जाति जनगणना करवाई थी, पर उसकी रिपोर्ट अब तक जारी नहीं की गई है. जातियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होने का असर योजना बनाने पर तो पड़ता ही है, साथ ही जातियों को हिस्सेदारी देने में भी परेशानी होती है. सूबे की सत्ता के छोटे भाई ने यह पत्ता खेला है, सो, बड़े भाई (लालू प्रसाद) को भी कुछ करना ही था. उसी दिन वे एक्शन में आ गए. उन्होंने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधान को समाप्त करने के यूजीसी के निर्देश का जोरदार विरोध किया. राजद सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम अपने पत्र में चेतावनी दी है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है. यह संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता है. आरक्षण पर आंच आई तो भारत के वंचित और गरीब सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरेंगे.

सूबे की राजनीति के बड़े भाई- छोटे भाई के राजनीतिक आलाप ने सियासत में कोई आलोड़न तो पैदा नहीं किया, लेकिन इससे उनकी भावी रणनीति के संकेत तो मिलते ही हैं. हिन्दी पट्टी ही नहीं, कई गैर हिन्दी भाषी राज्यों में भी राजनीति में जाति की भूमिका पहले की तुलना में बढ़ती जा रही है. धर्म के समानांतर इसे वोट का बड़ा और कई बार तो निर्विकल्प साधन मान लिया जाता है. कोई भी दल जाति की वकालत नहीं करता है, पर सभी जाति के नाम पर, जातियों को सुविधा देने के नाम पर, वोट का जुगाड़ करने की कोशिश में लगे रहते हैं. जातीय जनगणना की रिपोर्ट भी इसी राजनीति का एक हथियार बनता दिख रहा है. यह सही है कि देश में आरक्षण व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जातियों का नवीनतम आंकड़ा जरूरी है. इसके बगैर जरूरतमंदों को आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा. इसके अलावा सरकार के जनकल्याण कार्यक्रम को सफल व प्रभावकारी बनाने और उनके बेहतर परिणाम के लिए सामाजिक समूहों के अद्यतन आंकड़ों का होना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर कल्याण कार्यक्रमों को लक्षित सामाजिक समूहों तक पहुंचाना और उसके प्रभाव का मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाएगा. क्या राजनीतिक दल मात्र सैद्धांतिक व व्यावहारिक जरूरतों से प्रेरित होकर इसे उठा रहे हैं? इस सवाल का जवाब देना कठिन है, लेकिन एक राजनीतिक अभियान की चर्चा से उक्त सवाल के जवाब ढूंढने में मदद मिलेगी. गत वर्ष इन्हीं दिनों भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी. तब आर्थिक जनगणना के परिणाम, जो बिहार के संदर्भ में भी चिंताजनक थे, पर बोलने से राजनेता बचते रहे. पर जाति जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किए जाने को मुद्दा बना दिया. जाति जनगणना की रिपोर्ट के प्रकाशन की मांग को लेकर राजद सुप्रीमो ने राजभवन मार्च किया, सैकड़ों लोगों के साथ गिरफ्तारियां दीं और उन पर मुकदमा भी किया गया था. यह मुकदमा महागठबंधन की सरकार ने वापस लिया था, जिसे लेकर भाजपा ने काफी हंगामा किया था. उन दिनों बिहार चुनावी मोड में था. नीतीश कुमार ने उन दिनों जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग तो की थी, पर इसे मुद्दा नहीं बनाया था. राजद सुप्रीमो इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में सड़क पर आ गए. राजद सुप्रीमो को इसका राजनीतिक लाभ भी मिला और वे सूबे में पिछड़ों को नए सिरे से गोलबंद करने में कामयाब रहे. बाद में, लालू प्रसाद की उस मुहिम को धार दी संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान ने. राजनीति के जानकार मानते हैं कि छोटे भाई अपने बड़े भाई के ऐसे अनुभव से लाभान्वित होना चाहते हैं. उन्हें इस बार चुनावों के बहाने उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर अपने दल को स्थापित करना है. उन्हें लगता है कि जाति जनगणना के प्रकाशन का मुद्दा कुछ हद तक उनकी मदद कर सकता है. वैसे भी, आरक्षण जैसे मसले को यह गुणात्मक तौर पर विकसित ही तो करता है.

जद(यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिलहाल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सबसे अधिक दिखता है. यह विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक कौशल की अग्नि परीक्षा साबित होगा. गत विधानसभा चुनावों के समय वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे. उत्तर प्रदेश के सवाल पर ऐसा नहीं है, चुनाव की तैयारी के लिए उनके पास पर्याप्त समय है. हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नीतीश कुमार के दल के मुद्दे प्रायः जग-जाहिर हैं. वे और उनका दल संघ-मुक्त भारत के साथ-साथ आरक्षण की अब तक की तयशुदा सीमा में बढ़ोतरी और निजी क्षेत्र में इसके विस्तार को अपना चुनावी मुद्दा बनाएंगे. इसके साथ ही शराबबंदी को सबसे महत्वपूर्ण और शायद एकमात्र सामाजिक मुद्दे के तौर पर पेश करेंगे. इसे लेकर भाजपा ही नहीं, सपा को भी घेरकर इसे राजनीतिक स्वरूप देंगे. इस सूची में अब जाति जनगणना की रिपोर्ट का प्रकाशन भी शामिल हो रहा है. हालांकि जाति जनगणना की रिपोर्ट के प्रकाशन से आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी का मसला सीधे तौर पर जुड़ा है. आरक्षण की राजनीति करनेवाले राजनीतिक समूहों का मानना है कि देश में उन सामाजिक समूहों की आबादी पिछले दशकों में काफी बढ़ी है, जो आरक्षण के दायरे में हैं. अनुसूचित जाति-जनजाति की जनगणना तो आम जनगणना के साथ हो जाती है. हर दस साल पर उनकी आबादी का पता चल जाता है, पर पिछड़े समाजिक समूहों की जनसंख्या का पता नहीं चल पाता है. जनसंख्या की उचित जानकारी न मिलने के कारण विकास व जन कल्याण कार्यक्रमों में उनकी हिस्सेदारी का उचित आकलन नहीं हो पाता और इन सामाजिक समूहों की आबादी घाटे में रह जाती है. इन दलों और राजनेताओं का कहना है कि जातियों के आंकड़े सामने आने के बाद वे आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे और तब उनकी बात गंभीरता से सुनी जाएगी. आरक्षण की मौजूदा सीमा की पक्षधर राजनीति को तब जवाब देना आसान नहीं होगा. मंडल राजनीति के नीतीश कुमार या लालू प्रसाद जैसे नायकों के लिए जाति जनगणना की रिपोर्ट के प्रकाशन को मसला बनाना जरूरी है. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का बिहार विधानसभा चुनावों का अनुभव बताता है कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए उसके कमंडल का विरोध ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कमंडल में कैसा किस घाट का जल है, यह बताना भी ज्यादा जरूरी है.

भाजपा के कमंडल को बेअसर करने के लिए जिस आक्रामक राजनीति की जरूरत है, इसका गुर बड़े भाई लालू प्रसाद के पास है. बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो के इस गुर का स्वाद नीतीश कुमार चख चुके हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो किस तरह की भूमिका निभाएंगे, यह अब तक साफ नहीं है. मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल कर चुनावी अखाड़े में उनके उतरने की गुंजाइश अब तक दिखती नहीं है. राजद वहां चुनाव लड़ेगा, यह भी साफ नहीं है. राजद के कई वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के मैदान में जाने के पक्षधर नहीं हैं. हाल में संपन्न चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने भाग नहीं लिया था, जबकि पश्चिम बंगाल व असम में वह अपना प्रत्याशी दे सकता था. फिर भी, लालू प्रसाद जब तक कुछ बोलते नहीं हैं, इस पर कुछ भी कहना कठिन है. पुराने अनुभवों के आधार पर यह कहना कठिन है कि लालू प्रसाद किसी भी स्तर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की राजनीतिक हैसियत रखते हैं. लेकिन वह अपनी और अपने परिवार की भावी राजनीति के लिए आरक्षण जैसे सवाल के साथ गंभीर और आक्रामक बने रहना चाहते हैं, यह उनकी जरूरत भी है. इस मसले पर वे केंद्र सरकार से दो-दो हाथ करते दिखना चाहते हैं. यह सही है कि नीतीश कुमार उस हद तक आक्रामक और उत्तेजक राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर दिखाना है और वहां के मतदाताओं के बीच संघ मुक्त भारत को चमकाना है, तो उन्हें किसी उत्तेजक मसले की तलाश है. फिलहाल जाति जनगणना की रिपोर्ट का प्रकाशन ऐसा ही मसला बन सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आप की आंधी में उड़ता पंजाब

पंजाब में आम आदमी पार्टी एक विश्वसनीय विकल्प के रुप में उभरी है. इस बात की पुष्टि लोकसभा चुनाव के नतीजे ने भी की. आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चार सीट जीत कर पूरे देश को चौंका दिया था. लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर काफी उथल पुथल भी हुई. पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी है. नेताओं के बीच भी भारी गुटबाजी है. पंजाब में आम आदमी पार्टी के चार में से तीन सांसद पार्टी के साथ नहीं है. पार्टी में स्थानीय नेतृत्व नहीं है. यही वजह है कि केजरीवाल ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले रखी है.

मनीष कुमार

चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं. चुनावी राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए एक सप्ताह का वक्त भी काफी होता है. एक गलत फैसला या एक गलत बयान से जीती हुई बाजी हार में बदल जाती है. पंजाब चुनाव में तो अभी कई महीने बाकी हैं. अभी किसी भी पार्टी ने अपने-अपने पत्तों का खुलासा भी नहीं किया है. किसी पार्टी का उम्मीदवार भी तय नहीं हुआ है. ऐसे में चुनावी सर्वे ही एकमात्र माध्यम हैं जिसके जरिए लोग मतदाताओं के मूड को समझने की कोशिश करते हैं. हालांकि चुनावी सर्वे की सत्यता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं. आज का मतदाता इतना खामोश और परिपक्व हो चुका है कि एक्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हो जाते हैं. चुनावी सर्वे से हमें महज इशारा मिलता है. हवा के रुख का पता चलता है. इसलिए पंजाब चुनाव को समझने के लिए चुनावी सर्वे पर नजर डालना जरूरी है.

कुछ दिन पहले सी-वोटर्स का सर्वे आया. यहां ये बताना जरूरी है कि सी-वोटर्स के बारे में यह धारणा है कि इसका आंकलन भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुका होता है. सी-वोटर्स के सर्वे के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं. इस सर्वे के मुताबिक पंजाब के कुल 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी 94-100 सीट जीत सकती है. कांग्रेस पार्टी 8-14 सीटें जीत कर दूसरे स्थान पर रहेगी, तो वहीं अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6-12 सीटें मिलने की उम्मीद है. बेशक, इस सर्वे का नतीजा आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. लेकिन इस सर्वे में आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी है. इस सर्वे के मुताबिक 59 फीसद लोग अरविंद केजरीवाल को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. पंजाब के मतदाताओं की जनभावना को अरविंद केजरीवाल कैसे पूरा करेंगे यह देखना रोचक होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में पंजाब की जमीनी हकीकत यही है जैसा कि सी-वोटर्स के सर्वे के नतीजे में अनुमान लगाया गया?

दरअसल, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ माहौल है. मतदाता वर्तमान राज्य सरकार से नाराज हैं इस बात को सरकार चलाने वाले पार्टियों के लोग भी मानते हैं. इसमें दो राय नहीं है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में सरकार-विरोधी लहर का बड़ा असर होने वाला है. लोगों में नाराजगी की वजह कई हैं. नाराजगी की सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है. लोगों को लगता है कि अकाली दल - भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है. कई घोटाले उजागर हुए और प्रकाश सिंह बादल की गलती यह रही कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. दूसरी समस्या ये है कि बादल सरकार युवाओं को रोजगार मुहैय्या कराने में पूरी तरह से विफल रही है. पंजाब में औद्योगीकरण पूरी तरह से ठप्प रहा है. निवेश के मामले में भी पंजाब देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ता चला गया. युवाओं के लिए बादल सरकार अवसर प्रदान नहीं कर सकी और इसका असर ये हुआ कि नशे का जहर समाज में घुलता चला गया. सरकार विरोधी लहर का असर शहरों में ज्यादा दिखाई दे रहा है. शहरों में सरकार के प्रति ज्यादा नाराजगी है. वैसे भी, परंपरागत रूप से शिरोमणि अकाली दल की ताकत पंजाब के ग्रामीण मतदाता हैं और इस वर्ग में प्रकाश सिंह बादल की साख आज भी बरकरार है. अकाली दल की दूसरी समस्या यह है कि इस पार्टी में बादल परिवार के बाहर किसी भी नेता की कोई हस्ती नहीं है. यह आम धारणा है कि प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री के नाम पर मुखौटे की तरह रहे, असल में सारे फैसले उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल के हाथ में था. सुखबीर सिंह बादल के बारे में कहा जाता है कि वो तानाशाह की तरह पार्टी चलाते हैं. किसी दूसरे की बात सुनते ही नहीं है. दस साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद भी उनके रवैये में कोई बदलवा नहीं हुआ जिसकी वजह से अब पार्टी कार्यकर्ताओं, गठबंधन के नेताओं और आम जनता का धैर्य भी खत्म हो गया.

पंजाब में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई है. सारी पार्टियां कैंपेन मोड में आ चुकी हैं. पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है. बहुजन समाज पार्टी भी इस राज्य में फैली हुई है. साधारण स्थिति में यह कहा जा सकता था कि लोग वर्तमान सरकार से खुश नहीं हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी की जीत की स्थिति मजबूत है. लेकिन, इस बार पंजाब का चुनावी माहौल असाधारण है. इसकी वजह यह है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों की चुनावी-गणित बिगाड़ दी है. पंजाब चुनाव के नतीजे क्या होंगे? क्या कांग्रेस फिर से सरकार बना पाएगी? या पंजाब चुनाव के नतीजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो पंजाब चुनाव को लेकर लोगों के दिमाग में कौतूहल पैदा कर रहे हैं. कुछ लोगों को लगता है कि असंभव का संभव हो जाना ही राजनीति का चरित्र है.

भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल में तालमेल नहीं है. हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर यह गठबंधन टूट चुका है. वैसे, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक छोटी पार्टी है और केंद्रीय नेताओं ने इसके विस्तार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है. हालांकि, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता और कार्यकर्ता भी बादल सरकार से नाराज रहे लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की वजह से खुल कर विरोध नहीं कर सके. कई लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में अमृतसर से अरुण जेटली की हार इसी वजह से हुई थी. फिलहाल, हालात तो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं. इसका अर्थ ये है कि सरकार विरोधी लहर के साथ-साथ शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ तल्ख हुए रिश्ते का भी नुकसान उठाना पड़ेगा.

भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल में तालमेल नहीं है. हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर यह गठबंधन टूट चुका है. वैसे, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक छोटी पार्टी है और केंद्रीय नेताओं ने इसके विस्तार पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया. पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है. हालांकि, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता और कार्यकर्ता भी बादल सरकार से नाराज रहे लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की वजह से खुल कर विरोध नहीं कर सके. कई लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में अमृतसर से अरुण जेटली की हार इसी वजह से हुई थी.

कांग्रेस पार्टी के सामने पंजाब चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है. विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी लगातार हारती जा रही है. कांग्रेस पार्टी जिन जिन राज्यों में सरकार चला रही थी हर जगह सत्ता से बाहर होती चली जा रही है. लेकिन जिन राज्यों में विपक्ष में है वहां तो कम से कम चुनाव जीत कर पार्टी को अपनी उपस्थिति, प्रमाणिकता और औचित्य साबित करना होगा. असम और केरल में सरकार गंवाने के बाद, पंजाब में चुनावी जीत से ही कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिल सकती है. साथ ही, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पंजाब में चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए अनिवार्य है, नहीं तो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ गांधी परिवार की साख पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा. पंजाब की राजनीति और इतिहास को देखें तो सामान्य तर्क तो यही कहता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए. लेकिन जिस तरह का राजनीतिक-वातावरण है उसमें कांग्रेस पिछड़ती दिखाई दे रही है. अमरिंदर सिंह लोगों में विश्वास जगाने में विफल नजर आ रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पार्टी पहले से ही अंतर्कलह में उलझी हुई थी. हाईकमान अभी तक पंजाब के अंतर्कलह का हल निकाल नहीं पाया है. इनका नतीजा ये है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में तैयारी के लिहाज से सबसे पीछे है. पंजाब में चुनावी रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर को लगाया गया है. बताया ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर को लेकर अमरिंदर सिंह नाराज हैं. कांग्रेस की समस्या ये है कि उसके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह से ज्यादा विश्वसनीय कोई दूसरा चेहरा नहीं है.

पंजाब में भ्रष्टाचार है. पंजाब की कानून व्यवस्था खराब है. लोगों को लगता है कि पंजाब में माफिया राज है. बेरोजगारी की वजह से पंजाब का युवा नशे के जाल में फंस गया. न निवेश हुआ न विकास. यही वजह है कि वर्तमान सरकार से पंजाब के लोग जबरदस्त नराज हैं. लोग बदलाव चाहते हैं. सवाल यह है कि पंजाब की जनता के सामने विकल्प क्या है? सच्चाई ये है कि लोग अभी भी कांग्रेस से नाराज हैं. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी हों या कैप्टन अमिरंदर सिंह, लोगों के विश्वास को जीतने में कांग्रेस विफल रही है. यही वजह है कि पंजाब में तीसरी शक्ति का स्थान बना, जिसे आम आदमी पार्टी ने भरा है. फिलहाल, पंजाब का माहौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में है. जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी पहली पसंद बन गई है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी एक विश्वसनीय विकल्प के रुप में उभरी है. इस बात की पुष्टि लोकसभा चुनाव के नतीजे ने भी की. आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चार सीट जीत कर पूरे देश को चौंका दिया था. लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर काफी उथल पुथल भी हुई है. पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी है. नेताओं के बीच भी भारी गुटबाजी है. पंजाब में आम आदमी पार्टी के चार में से तीन सांसद पार्टी के साथ नहीं है. पार्टी में स्थानीय नेतृत्व नहीं है. यही वजह है कि केजरीवाल ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले रखी है. इतना ही नहीं सांगठनिक कार्यों से जुड़ा सारा फैसला दिल्ली से आए नेता लेते हैं. समझने वाली बात यह है कि हर पार्टी के अंदर इस तरह की खेमेबाजी होती है. पावर के लिए संघर्ष होता है. यह कोई नई बात नहीं है. हर पार्टी को इस विरोधाभास से गुजरना होता है. हर पार्टी अपने तरीके से पार्टी के आंतरिक कलह का हल निकालती है. जब पार्टी के सर्वोच्च नेता और सारे वरिष्ठ नेता एक साथ मिलकर चुनावी-रणनीति को बनाने से लेकर अमल करने पर शामिल हों तो पार्टी के अंदर खेमेबाजी पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है. अरविंद केजरीवाल यही कर रहे हैं. चुनाव प्रचार की कमान केजरीवाल ने अपने हाथ में रखी है. पार्टी के सारे बड़े नेता पिछले छह महीने से लगातार पंजाब में कैम्प कर रहे हैं. हर शहर और कस्बे में जाकर पार्टी को संगठित कर रहे हैं. अभी तक मुख्यमंत्री के उम्मीदावार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह तय है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी.

केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को लोगों का समर्थन मिल रहा है. केजरीवाल जहां जाते हैं लोगों की भीड़ होती है. दिल्ली से गए आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. लेकिन दिक्कत ये है कि पार्टी के पास स्थानीय चेहरे की कमी है. जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन उन्हें नेतृत्व देने वाले नेताओं की कमी है. आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों को इन कमियों के बारे में पता है इसलिए दिल्ली से नेताओं को लगातार पंजाब भेजा जा रहा है और अलग-अलग कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं और लोगों में उत्साह को बरकरार रखने की कोशिश हो रही है. इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बार पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है. कई विश्लेषकों को लगता है कि 2012 के चुनाव में मनप्रीत सिंह बादल ने भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव के आखिर तक वो मैदान में टिक नहीं सके. संसाधन की कमी, चुनाव तैयारी में कमी और अच्छे उम्मीदवार की कमी के बावजूद मनप्रीत सिंह 5 फीसदी वोट तो लेने में कामयाब हुए लेकिन एक भी सीट नही जीत सके. लेकिन समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और मनप्रीत सिंह की राजनीति में काफी फर्क है. सबसे बड़ा फर्क ये है कि केजरीवाल को न तो संसाधन की कमी है और न ही कार्यकर्ताओं की. अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सफलता से वर्तमान सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को अपने समर्थन में तब्दील किया है. पंजाब में दलितों में भी अपनी पैठ बनाई है. साथ ही वह कांग्रेस पार्टी के शहरी वोटरों का दिल जीतने में भी कामयाब रहे हैं. यही वजह है कि पंजाब में महौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में है. फिलहाल यह कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी को अब सिर्फ 117 अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है. लेकिन सभी राजनीतिक दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव और क्रिकेट मैच में एक समानता है. इसमें आखरी दांव तक जीत और हार का पता नहीं चलता है. पंजाब के लोग धार्मिक है, जज्बाती हैं और संवेदनशील भी हैं. चुनाव के दौरान दिल को छूने वाला एक वाक्य भी हार को जीत में बदल सकता है और अतिउत्साह में हुई छोटी सी गलती भी विध्वंशकारी साबित हो सकती है.■

manishbph244@gmail.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आगे बढ़ने के लिए नीतियां बदलने की ज़रूरत

उदारीकरण के 25 साल बाद क्या हुआ? हर कोई तो मर्सीडीज़ कार में नहीं घूम रहा है. इसका मक़सद क्या था? गरीब आदमी आज भी वहीं है, जहां था, किसान वहीं है, जहां था. किसानों की ज़िन्दगी में भी बहुत मामूली सुधार हुआ है. अगर हम वाकई वैसा देश बनना चाहते हैं जैसा देश बनाने की बात मोदी करते हैं, तो बहुत सारी नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है. उन्हें अलग-अलग विचारों वाले व्यक्तियों को शामिल कर एक थिंक टैंक बनाना चाहिए. उनके पास गुरुमूर्ति हैं. अगर वे गुरुमूर्ति को नीति निर्धारण में शामिल करें तो यह एक बेहतर कदम होगा. स्वदेशी जागरण मंच हमेशा छोटे और मंझोले उद्योगों के हितों के लिए लड़ता रहा है. यह सरकार के लिए अच्छा होगा यदि वह विकासोन्मुखी नीति बनाती है.

यह असल में कोई खबर नहीं है और ऐसा कुछ खास नहीं किया गया है जिस पर कमेंट किया जा सके. यह आसानी से समझा जा सकता है कि यूपी और पंजाब का चुनाव आ रहा है और किसी को भी काफी सोच-समझ कर आगे बढ़ना होगा, ताकि अपनी पार्टी के लिए बेहतर माहौल बनाया जा सके. एक साधारण विश्लेषण भी बता देगा कि मंत्रियों के चुनाव और पोर्टफोलियो बांटने में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो अनुप्रिया पटेल ऐसी नेता हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट के लिए लिया गया है. पटेल वहां सपा के बेनी प्रसाद वर्मा और नीतीश कुमार को काउंटर कर सकती हैं. अब वो कितना सफल और प्रभावी होती हैं, यह एक अलग विषय है. अन्य नेता कोई हैवीवेट (भारी-भरकम) नेता नहीं हैं, जो वास्तव में चुनाव को प्रभावित कर सकें.

राजस्थान को देखें, तो भाजपा ने दो मंत्रियों को हटाकर दो नए को मंत्रिमंडल में शामिल किया है. यह बदलाव ठीक है. जिन दो को हटाया गया है, वे अच्छा नहीं कर रहे थे. अब नए दो मंत्री कैसा काम करते हैं, देखना होगा. गुजरात से भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिस पर पार्टी की दृष्टि से देखें तो अमित शाह की छाप देखने को मिलती है. सरकार की दृष्टि से देखें तो कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ज्यादातर चीजों को पीएमओ से ही नियंत्रित किया जाएगा. सदानंद गौड़ा जैसे नन परफॉर्मिंग मंत्री, जिन्हें पहले रेलवे से कानून मंत्रालय भेजा गया था, को अब साइडलाइन कर दिया गया है क्योंकि वे वाकई अच्छा परिणाम नहीं दे सकते हैं. दो साल बाद होने वाले कर्नाटक चुनाव को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया. ऐसा कर भाजपा कर्नाटक के वोक्कालिगा समुदाय में गलत संदेश नहीं पहुंचाना चाहती थी. बाकी पोर्टफोलियो में बदलाव रुटीन है. इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है.

सरकार का असल प्रदर्शन आर्थिक स्थिति को देखकर समझा जा सकता है. महंगाई अब भी उच्च स्तर पर है. दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं. आम आदमी परेशान है. सरकार इस सबसे कैसे निपटेगी, कोई नहीं जानता. ऐसा प्रतीत होता है कि सोच में कोई समन्वय ही नहीं है. यह सरकार सुधार की बात करती है. 1991 में जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने सुधार की शुरुआत की, हम जैसे समाजवादी विचार के लोगों ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी थी. लेकिन, उसके बाद की सभी सरकारों ने उस विचार को अपनाया. 25 साल बाद आज आप देख सकते हैं कि इन 25 सालों में 25 लाख नौकरियां भी सृजित नहीं हो सकीं. बिना नौकरी सृजित किए, बिना निवेश के लिए वातावरण बनाए, सुधार (रिफॉर्म) को सफल नहीं माना जा सकता है. यह कुछ मामलों में जरूर सफल हुआ. अमीर लोगों की जिंदगी आसान हुई. सड़कें बनीं, मॉल बनीं, मल्टीप्लेक्सेज, विदेश से सामान का मुफ्त आयात आदि होने लगा. लिहाज़ा अमीर लोगों की ज़िन्दगी आसान हो गई. उस फैसले का एक परिणाम यह भी हुआ कि ज़्यादातर क़ानूनों को गैर आपराधिक बना दिया गया. वाजपेयी सरकार ने फेरा को फेमा में बदल दिया.

दुर्भाग्यवश यह सरकार भी भ्रमित नजर आ रही है. यह सरकार हमेशा लोगों को जेल भेजने का भय दिखाती रहती है. विजय माल्या देश छोड़कर जा चुके हैं. अन्य लोग भी डर अनुभव कर रहे हैं. फेमा एक मनी लांड्रिंग एक्ट है. प्रवर्तन निदेशालय कुछ लोगों को जेल में डालने के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है. वास्तव में यह सरकार करना क्या चाहती है, स्पष्ट नहीं है.

उद्योगपतियों की तरफ से यह सवाल किया जा रहा है कि आप (सरकार) एफडीआई लाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है? भारत में पर्याप्त संख्या में उद्योगपति हैं. सरकार बैंकरप्सी (दिवालिया) लॉ लाना चाहती है. अमेरिका से किसी कानून की नकल कर के लाने का कोई मतलब नहीं है. अमेरिका एक अलग किस्म की अर्थव्यवस्था है. वहां एक वास्तविक पूंजीवादी वर्ग है. भारत में कितने ऐसे अरबपति हैं जो निवेश करने में रुचि दिखाते हों. मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम ही हैं. यदि आज सरकार किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेचने की कोशिश करे तो मुश्किल से 5 या 6 बिडर सामने आएंगे, उसमें भी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला यही नाम होंगे.

प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 1969 में हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ही इसमें थोड़ी-बहुत तेजी आई. उससे पहले कुछ मुट्ठी भर घराने ही उद्योग आदि चलाते थे. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद एक साधारण आदमी ट्रक खरीद सकता था, रिक्शा खरीद सकता था, टैक्सी खरीद सकता था और एक स्वनियोजित उद्यमी बन सकता था. आज फिर उसी तरह के वातावरण की जरूरत है, जब एक छोटा आदमी लोन लेकर आत्मनिर्भर बन सके. पिछले 15 साल में बैंकों ने सिर्फ बड़ी कंपनियों को लोन दिया और वे लोन अब एनपीए बन चुके हैं. इसलिए इस तरह की रणनीति सफल नहीं हो सकी. बजाए इस तरह की रणनीति को बदलने के, सरकार एनपीए के लिए दोषी को जेल भेजने की बात करती है. उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी. आप करना क्या चाहते हैं?

> **सरकार बैंकरप्सी (दिवालिया) लॉ लाना चाहती है. अमेरिका से किसी कानून की नकल कर के लाने का कोई मतलब नहीं है. अमेरिका एक अलग किस्म की अर्थव्यवस्था है. वहां एक वास्तविक पूंजीवादी वर्ग है. भारत में कितने ऐसे अरबपति हैं जो निवेश करने में रुचि दिखाते हों. मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम ही हैं. यदि आज सरकार किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेचने की कोशिश करे तो मुश्किल से 5 या 6 बिडर सामने आएंगे, उसमें भी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला यही नाम होंगे.**

अगर आगे बढ़ना सरकार का मकसद है, अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, निवेश बढ़ाना है तो फिर यह माहौल सही नहीं है. आपको यह विश्वास दिलाना है कि कोई जेल नहीं जाएगा. अगर कोई आदमी लोन लेता है और उसे चुका नहीं पाता है तो यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं है. कानून के हिसाब से काम करिए. संपत्ति जब्त करिए, अपना लोन वसूलिए. सुब्रतो राय को बिना चार्ज किए जेल में रखने से, विजय माल्या के देश से बाहर जाने से आपको पैसा कैसे मिलेगा? यह बात समझ से परे है. रघुराम राजन ऐसा लगता है कि बैंकों पर शिकंजा कसने के कारण बने थे. जब उन्होंने घोषणा की कि वे दोबारा पद नहीं लेंगे तब बैंकों ने राहत की सांस ली. कई बैंकर्स मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि वे अपने उन बैंक खातों की दोबारा जांच करेंगे, जिनमें गड़बड़ी पैदा हुई है और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे. मुझे नहीं मालूम कि क्या वाकई रघुराम राजन बाधा उत्पन कर रहे थे. अगर ऐसा था तो यह अच्छा है कि उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा रहा है. हमें एक स्वतंत्र और सरकारी लाइन से इतर सोच वाले एक आरबीआई गवर्नर की जरूरत है, लेकिन वह काम भी करे. मौद्रिक नीति का निर्धारण रिजर्व बैंक ही करता है, करना भी चाहिए. ब्याज दर भी आरबीआई को ही तय करना है. मैं यह नहीं चाहता कि आप यह कमेंट करें कि रघुराम राजन ब्याज दर नहीं घटा रहे थे, इसलिए वे बुरे हैं. एक तरफ हम चाहते हैं कि महंगाई दर कम हो, इसके लिए रिज़र्व बैंक के पास जो एकमात्र उपाय है वह है ब्याज दर को काम करना. नए आरबीआई गवर्नर का चयन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा ही किया जाना चाहिए. सरकार इसके लिए सर्च कमेटी की बात करती है, यह हास्यास्पद है. यूएस, यूके या किसी भी पश्चिमी देश में सेंट्रल बैंक के मुखिया का चयन सत्ता में बैठी सरकार द्वारा होता है न कि किसी कमेटी द्वारा. इस पद के लिए मीडिया में जितने भी नाम आए हैं, उनमें से कुछ नाम अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें अगर गवर्नर बना दिया जाए तो यह किसी डिजास्टर (बर्बादी) से कम नहीं होगा. मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी बेहतर लोगों से सुझाव लेंगे और किसी अच्छे व्यक्ति को गवर्नर बनाएंगे. आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको आर्थिक कानूनों का डिक्रिमिनलाइजेशन करना होगा. ऐसा करना अभी की जरूरत है, अन्यथा अभी की नीति को बदलकर 1991 से पहले की नीति को अपनाइए, यह बुरा भी नहीं होगा. यह ज़रूर है कि अमीर लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, उन्हें लाइसेंस, परमिट की जरूरत पड़ेगी. उनकी ज़िंदगी थोड़ी नियंत्रित हो जाएगी. उदारीकरण के 25 साल बाद क्या हुआ? हर कोई तो मर्सीडीज़ कार में नहीं घूम रहा है. इसका मक़सद क्या था? गरीब आदमी आज भी वहीं है, जहां था, किसान वहीं है, जहां था. किसानों की ज़िन्दगी में भी बहुत मामूली सुधार हुआ है. अगर हम वाकई वैसा देश बनना चाहते हैं जैसा देश बनाने की बात मोदी करते हैं, तो बहुत सारी नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है. उन्हें अलग-अलग विचारों वाले व्यक्तियों को शामिल कर एक थिंक टैंक बनाना चाहिए. उनके पास गुरुमूर्ति हैं. अगर वे गुरुमूर्ति को नीति निर्धारण में शामिल करें तो यह एक बेहतर कदम होगा. स्वदेशी जागरण मंच हमेशा छोटे और मंझोले उद्योगों के हितों के लिए लड़ता रहा है. यह सरकार के लिए अच्छा होगा यदि वह विकासोन्मुखी नीति बनाती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

यूपी में भी शराबंबदी लागू हो

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का क्रांतिकारी कदम उठाया है. नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर जिस प्रकार से उसे अमलीजामा पहनाया है वो निश्चय ही सराहनीय कदम है. शराब पीकर घर आने के बाद पति अपनी पत्नियों से मारपीट करते थे. बिहार में शराबबंदी लागू होने की वजह से अब महिलाओं को अपने पतियों के इस कृत्यों से छुटाकारा मिल गया है. पहले पुरुषों की कमाई का आधा पैसा शराब में चला जाता था, लेकिन अब वो पैसा उनकी बुनियादी जरूरतों पर खर्च हो रहा है. बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के विकास पर खर्च हो रहा है. उनकी हालत में सुधार होने से परिवार में खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार को भी प्रदेश में शराबबंदी लागू करनी चाहिए, जिससे शराब की वजह से बर्बाद हो रहे परिवारों को बचाया जा सके. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार शराबबंदी को लागू करने में टाल-मटोल की नीति अपनाई हुई है. कहा जाता है कि यूपी सरकार को शराब से 17 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है. इसी वजह से सरकार तरह-तरह के बहाने बनाकर यूपी में शराबबंदी लागू नहीं कर रही है. यूपी में शराबबंदी लागू हो जाए, तो बिहार की तरह यूपी में बढ़ते अपराध में कमी आएगी.

अत: हमारी केंद्रीय और प्रदेशीय शासन से मांग है कि वो पूर्ण शराबबंदी की नीति को यथाशीघ्र लागू कर गांधी जी के सपनों को साकार करें. शराबबंदी से सभी देशवासियों का भला होगा.

–शिव कुमार फैजाबादी (स्वतंत्र पत्रकार),
फैजाबाद, उत्तर प्रदेश.

जनता सब जानती है

कमल मोरारका ने अपने आलेख हास्यास्पद दावे करना बंद कीजिए (04 जुलाई- 10 जुलाई 2016) में बिल्कुल सही कहा है कि मोदी सरकार के कुछ मंत्री जिस तरह के दावे कर रहे हैं, वे गलत हैं और कुछ हद तक हास्यास्पद भी. मोदी सरकार के मंत्रियों का ध्यान काम पर कम है और प्रचार पर ज्यादा है. उमा भारती दावा कर रही हैं कि हमारा गंतव्य अक्टूबर 2018 है और हम दुनिया को दिखा

देंगे कि गंगा दुनिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है. पीयूष गोयल के भी दावे भी हवा में हैं. इसी तरह कई ऐसे मंत्री हैं जिनके दावे गलत हैं और तथ्यों से परे हैं. वह चाहे सफाई अभियान को लेकर हो या गांवों में शौचालयों को लेकर. इसलिए मंत्रियों को झूठ कम बोलना चाहिए, क्योंकि जनता इसका जवाब मांगेगी.

–अभिराम सिंह, *बक्सर, बिहार.*

पार्टियों में मची भगदड़

जब तोप मुकाबिल हो-चौंकाने वाला होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव (04 जुलाई- 10 जुलाई 2016) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि किसी को अंदाजा नहीं था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में इस तरह की हलचल होगी, जो लोगों को चौंका देगी. यह बिल्कुल सत्य है. समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो घटनाएं घट रही हैं वह चौंकाने वाली हैं. सपा में अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच का मनमुटाव हो या अन्य घटनाएं. उधर बसपा से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, तो उसके कुछ ही दिन बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता आरके चौधरी ने भी बसपा छोड़ दी. उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव चौंकाने वाला होगा.

–विपुल मौर्य, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

कब तक साफ होगी गंगा

कवर स्टोरी-गंगा की सौगंध झूठ बोलो कम (04 जुलाई- 10 जुलाई 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. कवर स्टोरी की हेडिंग ने काफी आकर्षित किया. मोदी सरकार और उमा भारती गंगा की सफाई को लेकर हमेशा झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अब तक गंगा में कहीं भी सफाई नहीं दिख रही है. गंगा की सफाई पर अब तक करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं. गंदे नालों का पानी अभी भी गंगा में सीधे जाकर गिर रहा है. गंगा की सफाई को लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों की भी राय अलग-अलग है. हां एक चीज जरूर हुई है कि घाटों की सफाई कई जगहों पर दिखती है, लेकिन वो भी स्वच्छता अभियान के तहत. शफीक आलम ने बिल्कुल सही कहा है कि गंगा 2018 तक तो क्या, 2028 तक भी साफ हो सकेगी, ऐसा लगता नहीं. गंगा की सफाई की जिम्मेदारी हम सबकी है, इसलिए हम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हम गंगा को गंदा नहीं करेंगे. सरकार को गंगा की सफाई को लेकर जनता से सच बोलना चाहिए.

–हिमांशु शेखर, *देहरादून, उत्तराखंड.*

राजनीतिक पार्टियों का सच

आलेख-यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था का सच और सपा की प्राथमिकता उजागर, असामाजिकों से समाजवादियों का मेल (04 जुलाई- 10 जुलाई 2016) पढ़ा. दीनबंधु कबीर ने अपने आलेख में बिल्कुल तथ्यात्मक बातें कही हैं. कुख्यात अपराधी सरगना मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के बाद जो कुछ भी हुआ वह पहले से तय-नाटक (स्टेज्ड-ड्रामा) था. यह सारा नाटक जनता को दिखाने के लिए खेला गया. क्या ऐसा कभी हो सकता है कि अखिलेश यादव अपने पिता और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के फैसले को पलट दें. चुनाव का मौसम है चुनाव में आना-जाना लगा रहता है, नौटंकी होती रहती है. दूसरा आलेख-बहुजन समाज पार्टी में मची भगदड़, मौर्य के बाद कई और लाइन में, मायावती के खिलाफ मौर्य का शौर्य. इस आलेख में कही बातें बिल्कुल सत्य हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी से जाने के बाद बसपा के वरिष्ठ नेता आरके चौधरी ने भी बसपा अध्यक्ष मायावती पर गंभीर आरोप लगाकर पार्टी को छोड़ दिया. अभी बसपा के कई और नेता भी पार्टी छोड़ने को तैयार हैं. चुनाव आते ही नेताओं का पार्टियों में आना जाना लग जाता है. लेकिन एक बात जरूर पता चल जाती है कि राजनीतिक पार्टियां कितनी नैतिक और सिद्धांतवादी हैं.

–गौरव तिवारी, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

नशे के ख़िलाफ़ जनता का शंखनाद है पंजाब चुनाव

देश इन दिनों मजेदार स्थितियों से गुजर रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, तब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, जिसपर अब जाकर सीबीआई ने कार्रवाई की. दिल्ली सरकार का सारा काम केंद्र सरकार देखती है. मुख्यमंत्री चाहें, तो भी किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. एक संयुक्त सचिव, जो गृह मंत्रालय के मातहत काम करता है, वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के सारे फैसलों को बदल सकता है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है. अगर केंद्र सरकार चाहती तो प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार का पहले तबादला करती और फिर उन्हें सीबीआई से गिरफ्तार करने के लिए हरी झंडी दिखाती. इससे कम से कम ये संकेत तो नहीं जाता कि केंद्र सरकार केजरीवाल को काम करने नहीं देना चाहती है, पर केंद्र सरकार ने पूरे देश को यही संदेश दिया. बकौल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, उनके लगभग डेढ़ सौ अफसरों का ट्रांसफर केंद्र सरकार ने दिल्ली से बाहर ऐसी जगह कर दिया, जहां निर्धारित अफसरों की पूरी संख्या है. यह तर्क समझ से परे है, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि केंद्र सरकार में कोई है जो महान बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से दिल्ली के काम-काज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है. बिना यह समझे कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री को उसका कितना फायदा मिलने वाला है या कितना नहीं मिलने वाला है.

शायद इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, प्रकाश सिंह बादल और सरदार अमरिंदर सिंह यानी कांग्रेस ये तीनों आम आदमी के सामने भौचक खड़े हैं. जब मैं आम आदमी कह रहा हूं तो मेरा मतलब आम आदमी पार्टी से है. अब उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में पंजाब में चार सांसद मिल गए. कैसे उनमें तीन सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए, जिन सांसदों को एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल ने भी साधने की कोशिश की. उनमें से सिर्फ एक सांसद अरविंद केजरीवाल के साथ रहा, इसके बावजूद उन्हें पंजाब की जनता हाथों हाथ उठा रही है. अरविंद केजरीवाल को पंजाब की जनता द्वारा सर-माथे बिठाना राजनीतिक विश्लेषकों, कांग्रेस और खुद प्रकाश सिंह बादल की समझ में नहीं आ रहा है. दिल्ली का घटनाक्रम देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि राजनीति की गलियों में कभी-कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं या लोग अपना फैसला कुछ यूं करने लगते हैं जिससे किसी बड़े सिद्धांत की बू नहीं आती, लेकिन संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं. पंजाब में धांधली है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है और पूरा का पूरा पंजाब नशे की गिरफ्त में है.

पंजाब में नशे की गिरफ्त का हाल यह है कि नशे के सौदागर आतंक के सौदागर बन गए हैं. पंजाब का प्रशासन यानी वहां की पुलिस का एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स के कारोबार में लिप्त है. पठानकोट हमले के समय ड्रग्स तस्करों को लाने की कोशिश में पंजाब पुलिस का एसपी आतंकवादियों को देश के अंदर ही नहीं ले आया, बल्कि उसके सुरक्षित पहुंचने की योजना भी बनाई. पर ये तो एक किस्सा है जो सामने आ गया. पंजाब को जानने वाले दिल्ली में इंटेलीजेंस ब्यूरो के लोग बताते हैं कि पंजाब सरकार के पास वे सभी जानकारियां हैं कि उनके कौन से अफसर ड्रग्स के कारोबार में लिप्त हैं, लेकिन पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है. वह कार्रवाई कर भी नहीं सकती

पंजाब का यह चुनाव दरअसल प्रशासनिक व्यवस्था और नशाखोरी के खिलाफ जिसमें शराब, चरस या जितने भी प्रकार के ड्रग्स होते हैं, उनके नशे के खिलाफ जनता का एक शंखनाद है. हो सकता है ये शंखनाद पंजाब में नशे के खिलाफ देश के लोगों की हुंकार का पहला कदम साबित हो. बिहार में नीतीश कुमार ने नशाबंदी के पक्ष में अलख जगाया, उस अलख बे दूसरी दस्तक तमिलनाडु में दी और अब तीसरी दस्तक पंजाब में देने जा रहा है. पर सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में नशाबंदी या शराबबंदी कोई मुद्दा बनेगा.

क्योंकि जब उसके मंत्री रहे एक व्यक्ति का नाम ड्रग तस्करी में आ जाए और आमतौर पर ये खबर चारों तरफ फैल जाए कि पंजाब सरकार के सबसे बड़े ओहदेदार भी इस ड्रग्स कारोबार में हिस्सेदार हैं, तो भला कोई क्या करे? आज पंजाब में आमतौर पर यह धारणा बनी है कि ड्रग्स से अगर बचना है या जो बचे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश करनी है तो भारतीय जनता पार्टी, प्रकाश सिंह बादल और कांग्रेस की जरूरत नहीं है. इसलिए आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों का अंध समर्थन प्राप्त है. विरोधी दलों का एक अच्छा फैसला ये है कि वे पंजाब जाकर अरविंद केजरीवाल के अभियान को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. अन्यथा क्या मायावती, क्या मुलायम सिंह, क्या नीतीश कुमार, क्या शरद पवार, क्या देवगौड़ा सब पंजाब जा सकते थे, लेकिन वे पंजाब नहीं जा रहे. यहीं दूसरा खतरा पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं यह न समझ लें कि उनके डर की वजह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी पार्टियां हैं, वे पंजाब नहीं आ रही हैं. अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं. उनके प्रति समर्थन की वजह से ऐसा हो रहा है, डर की वजह से नहीं. भारतीय जनता पार्टी और प्रकाश सिंह बादल पंजाब में हारें इसलिए देश के विपक्षी दल पंजाब नहीं जा रहे हैं.

पंजाब का यह चुनाव दरअसल प्रशासनिक व्यवस्था और नशाखोरी के खिलाफ जिसमें शराब, चरस या जितने भी प्रकार के ड्रग्स होते हैं, उनके नशे के खिलाफ जनता का एक शंखनाद है. हो सकता है ये शंखनाद पंजाब में नशे के खिलाफ देश के लोगों की हुंकार का पहला कदम साबित हो. बिहार में नीतीश कुमार ने नशाबंदी के पक्ष में अलख जगाया, उस अलख ने दूसरी दस्तक तमिलनाडु में दी और अब तीसरी दस्तक पंजाब में देने जा रहा है. पर सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में नशाबंदी या शराबबंदी कोई मुद्दा बनेगा. देखते हैं कौन राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में इस नारे को लेकर एक नई ताकत खड़ी करने की कोशिश करता है. ■

editor@chauthiduniya.com

मोदी की चुनौतियां

मेघनाद देसाई

राजनीतिक नेतृत्व एक कठिन चुनौती है. आपको विशाल मतदाताओं के समूह के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ-साथ मुख्य जन संपर्क अधिकारी और मानव संसाधन अधिकारी की भूमिका भी अदा करनी होती है. इसके साथ ही आपको पता नहीं होता कि कब आपकी नौकरी चली जाएगी, जैसा कि पिछले हफ्ते डेविड कैमरन के साथ हुआ. अब ब्रिटेन में जल्द से जल्द उनकी जगह लेने की होड़ मची हुई है क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में शीर्ष पद को खाली छोड़ना हानिकारक हो सकता है. लेबर पार्टी भी इन दिनों नेतृत्व में विश्वास के संकट से गुजर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही वहां भी एक चुनाव आयोजित किया जाएगा.

भारतीय राजनीति में नेता का चुनाव अपारदर्शी तरीके से होता है. अपनी सबसे बड़ी हार के दो साल बाद भी कांग्रेस में नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं हुआ (यहां तक कि परिवार के भीतर से भी नहीं). खुद आश्वस्त रहना कांग्रेस की फितरत है. हालांकि भाजपा एक वंशवादी पार्टी नहीं है, लेकिन वहां भी नेता के चयन की प्रक्रिया का थाह लगाना मुश्किल है. यह तो निश्चित है कि वहां भी पार्टी सदस्यों के मतदान द्वारा नेता का चुनाव नहीं होता है. इसका परिणाम यह होता है कि नेता के अधिकार अनिश्चित हो जाते हैं. जब नरेंद्र मोदी को भाजपा के संसदीय अभियान का नेता चुना गया था, तब वहां कोई औपचारिक चुनाव नहीं हुआ था. लेकिन जब वे भारी बहुमत से चुनाव जीत गए तो उनकी शक्ति असीमित हो गई. यह शक्ति उन्होंने अपने प्रदर्शन से हासिल की. उन्होंने खुद ही कहा है कि वे दिल्ली के लिए एक बाहरी व्यक्ति हैं और दिल्ली की सत्ता के अभिजात वर्ग से अपरिचित हैं. यह बयान मोदी को न सिर्फ भाजपा के नेताओं से अलग करता है, बल्कि दूसरे तमाम नेताओं से भी अलग करता है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे पिछले दरवाजे से शीर्ष पर पहुंचे हैं और उन्हें दिल्ली के अभिजात वर्ग से निपटने के लिए अरुण जेटली को तैनात करना पड़ा है. नरेन्द्र मोदी को शक्ति उनके चुनाव जीतने की क्षमता से मिली है. उन्होंने भाजपा को सदन में बहुमत दिला दिया. जब तक वे चुनाव जीतते रहेंगे, तब तक पार्टी में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा. यही कारण है कि लोकसभा के बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव उनके लिए एक सदमे की तरह था. अब असम की जीत ने उन्हें फिर जीत की राह पर खड़ा कर दिया है. उनकी अगली परीक्षा उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों में होनी है.

हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सर यह कहा जाता है कि आपके विरोधी आपके सामने होते हैं और आपके दुश्मन आपके पीछे. 2014 में जीत के बाद भाजपा ने मोदी को बिना हस्तक्षेप अपना शासन चलाने के लिए वरिष्ठ सदस्यों को किनारे कर दिया. दरअसल एक बात जो किसी की समझ में नहीं आई वह यह कि भाजपा कांग्रेस की तरह एक पिरामिड नहीं थी, बल्कि हिमालय की तरह एक पर्वत श्रृंखला थी.

हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सर यह कहा जाता है कि आपके विरोधी आपके सामने होते हैं और आपके दुश्मन आपके पीछे. 2014 में जीत के बाद भाजपा ने मोदी को बिना हस्तक्षेप अपना शासन चलाने के लिए वरिष्ठ सदस्यों को किनारे कर दिया. दरअसल एक बात जो किसी की समझ में नहीं आई वह यह कि भाजपा कांग्रेस की तरह एक पिरामिड नहीं थी, बल्कि हिमालय की तरह एक पर्वत श्रृंखला थी.

इस परिप्रेक्ष्य में हमें डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी के हस्तक्षेप को समझने की जरूरत है. वे भाजपा के सबसे वरिष्ठ सक्रिय नेताओं में से एक हैं. आडवाणी की तरह उन्होंने चुप्पी नहीं साध ली है. अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके पास दृढ़ संकल्प है. आपातकाल (जब मौजूदा प्रधानमंत्री एक प्रचारक थे) के दौरान वे इंदिरा गांधी के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे. उन्होंने जयललिता और सोनिया गांधी को अदालतों में चुनौती दी. उन्होंने अपनी ताक़त सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल और असीम ऊर्जा से हासिल की है.

डॉ. स्वामी और प्रधानमंत्री में कई स्पष्ट समानताएं होने के साथ कई फर्क भी हैं. एक बात जो मोदी को स्वामी से अलग करती है, वह है मोदी में चुनाव जीतने की क्षमता. उन्होंने राज्य और केंद्रीय स्तर पर सरकारें चलाई हैं. मोदी ने अब स्वामी की चुनौती को पहचान लिया है और उन्हें रोकने की शुरुआत भी कर दी है. दरअसल यह इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि यह एक शुरुआत का अंत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कार्यपालक सहायक दक्षता परीक्षा में घपलेबाज़ी

जिला प्रशासन द्वारा नए सिरे से परीक्षा लेने की बात कह कर उन बेरोजगारों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है. जिनका चयन एक बार हो चुका था. प्रशासन का कहना है कि प्रशासनिक जांच के बाद दक्षता परीक्षा में अनियमितता का मामला उजागर हुआ. अनियमितता को लेकर परीक्षा तो रद्द कर दी गई, लेकिन जिनकी मेहरबानी से घपलेबाजी हुई उन अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई. इसे लेकर अब सफल अभ्यर्थियों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है. तय रणनीति के तहत वे लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं.

कुमार कृष्णन

बिहार में हर तरह की परीक्षा में घपलेबाजी और बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ एक नियति सी बन गई है. अभी इंटर की परीक्षा का मामला सुलझा भी नहीं था कि मुंगेर में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तहत कार्यपालक सहायक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम चर्चा में है. कार्यपालक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर की दक्षता परीक्षा में अनियमितता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. अब जिला प्रशासन द्वारा नए सिरे से परीक्षा लेने की बात कह कर उन बेरोजगारों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है. जिनका चयन एक बार हो चुका था. प्रशासन का कहना है कि प्रशासनिक जांच के बाद दक्षता परीक्षा में अनियमितता का मामला उजागर हुआ. अनियमितता को लेकर परीक्षा तो रद्द कर दी गई, लेकिन जिनकी मेहरबानी से घपलेबाजी हुई उन अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई. इसे लेकर अब सफल अभ्यर्थियों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है. तय रणनीति के तहत ये लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं.

कार्यपालक सहायक की दक्षता परीक्षा परिणाम को रद्द करने का विरोध करने वाले सफल अभ्यर्थियों अनंत कुमार झा, अर्चना रंजन, अशोक कुमार, रोशनी कुमारी, लक्ष्मण कुमार सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी द्वारा टंकण परीक्षा के फाइनल मेरिट लिस्ट को रद्द किए जाने पर रोष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि इस मामले में धांधली जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मी द्वारा किया गया और इसकी सजा अभ्यर्थियों को भोगने के लिए कहा जा रहा है जो पूरी तरह गलत है. इस मामले में दक्षता परीक्षा में संलिप्त अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन जिला प्रशासन वैसे अधिकारियों व कर्मियों को क्लीनचीट दे रहा है.

गौरतलब है कि कार्यपालक सहायक के टंकण परीक्षा समाहरणालय स्थित जिला सूचना केंद्र (एनआइसी) में ली गई. इस परीक्षा में लगभग 1516 परीक्षार्थी सरीके हुए थे. परीक्षा जिला प्रशासन के आलाधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति में हुई. उसके बाद विगत 3 मई 2016 को 1516 अभ्यर्थियों में से 651 अभ्यर्थियों की सूची फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया गया. उसके बाद नेताओं व असफल अभ्यर्थियों द्वारा आरोप-प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया. एंटी करप्शन एक्टिविस्ट फोरम के संजय केसरी ने अनियमितता का सवाल उठाया था. इस मामले में विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय जांच कमिटी का गठन किया गया. जब उपविकास आयुक्त रामेश्वर पांडेय के नेतृत्व में गठित जांच दल ने परीक्षा की जांच की तो बड़े पैमाने पर धांधली का मामला उजागर हुआ. जिसमें एक ही उत्तरपुस्तिका के परिणाम को कई अभ्यर्थियों के उत्तरपुस्तिका के रूप में उपयोग किया गया. जबकि कई उत्तरपुस्तिका समान थी. परीक्षा लेने वालों में जिला सूचना पदाधिकारी पंकज कुमार झा, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी खिलाफत अंसारी, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अखिलेश झा, वरीय उपसमाहर्ता प्रेमकांत सूर्य आदि पदाधिकारी थे. जाहिर है कि घपलेबाजी भी इन्हीं पदाधिकारियों व कर्मियों की मेहरबानी से हुई. लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है.

मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया. जिला प्रशासन के कई कर्मियों के नजदीकी रिश्तेदार थोक भाव में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए. जिससे धांधली की बू आ रही थी. जब प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच कराई गई तो मामले में धांधली भी उजागर हुई. जिला पदाधिकारी ने परीक्षा को रद्द करते हुए पुन: परीक्षा लेने की घोषणा की है. लेकिन जिन अधिकारियों के नेतृत्व में यह दक्षता परीक्षा लिया गया उन अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. मेरिट लिस्ट के सवाल पर उत्तीर्ण छात्र जब जिला पदाधिकारी से मिले थे तो उन्होंने संजय केसरी के आरोप और अनुत्तीर्ण छात्र का हवाला देते हुए कहा कि इसके बाद प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा. उसके बाद उत्तीर्ण छात्रों का गुस्सा भड़का और संजय केसरी के घर का घेराव किया. इस परीक्षा में उत्तीर्ण एक अभ्यर्थी का कहना है कि किसी परीक्षा में घपलेबाजी होती है पूरे परिणाम को रद्द कर बेरोजगारों को परेशान करना कहां का इंसाफ है.

इस परीक्षा में घपलेबाजी और नियुक्ति में विलंब का नतीजा यह है कि जिला प्रशासन के कई कार्यालय बिना कार्यपालक सहायक के चल रहे हैं. मजे की बात तो यह है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिना कार्यपालक सहायक के चल रहा है. जबकि इस विभाग में कार्यपालक सहायक की सख्त आवश्यकता है. यहां के अधिकारी को छोटे-छोटे काम के लिए दूसरे विभाग के कार्यपालक सहायक पर निर्भर रहना पड़ता है.■

feedback@chauthiduniya.com

हाईकोर्ट ने बीएड कॉलेजों की जांच पर रोक लगाई

सुनील सौरभ

बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पूरे देश में किरकिरी हो रही है. प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की भी स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. शिक्षकों की भारी कमी की वजह से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई एक तरह से ठप है. प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं. एक यो दो शिक्षक हैं, तो उन्हें भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के आंकड़े एकत्र करने में लगा दिया गया है. बिहार में शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति की शुरुआत लगभग दो दशक पहले ही हो गई थी. बिहार के सभी सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग(बीएड) कॉलेजों को बंद करा

दिया गया. निजी बीएड कॉलेज भी बिहार में केवल नाम मात्र थे. बाद में शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने लगी. उसके बाद बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद मुखिया, नगर पंचायत, नगर निगम और जिला परिषद को प्राप्तांक के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दे दिया गया. जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई और हजारों की संख्या में फर्जी शिक्षक बहाल कर दिए. समय-समय पर अयोग्य शिक्षकों का मामला सामने आता रहा. शिक्षा में सुधार के लिए बीएड कॉलेजों को मान्यता देने वाले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन(एनसीटीई) ने निर्देश दिया कि स्कूलों में सिर्फ ट्रेंड टीचर्स ही बहाल किए जाएंगे. एनसीटीई के आदेश के बाद भी बिहार में बंद पड़े सरकारी बीएड कॉलेजों को नहीं खोला गया. कुछ सरकारी कॉलेज खुले भी तो उनमें संसाधनों की भारी कमी रही. उसके बाद बिहार में कई निजी बीएड कॉलेज खुल गए. एनसीटीई ने मानक पर खरे उतरने वाले और सभी संसाधनों से लैस निजी बीएड कॉलेजों को मान्यता दे दी. संबंधित विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि निजी बीएड कॉलेजों में होने वाली बीएड की पढ़ाई की परीक्षा लें और संबद्धता प्रदान करें. लेकिन एनसीटीई के निर्देशों को दरकिनार कर बिहार का मानव संसाधन विकास विभाग निजी बीएड कॉलेजों को परेशान करने में लगा है. राज्य के मानव संसाधन विकास विभाग ने इन बीएड कॉलेजों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जबकि बिहार सरकार को भारत सरकार की संस्था एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैरसरकारी टीचर्स ट्रेनिंग(बीएड) कॉलेजों की जांच का अधिकार नहीं है. विश्वविद्यालय केवल निजी बीएड कॉलेजों की सिर्फ एक्जामिंग बॉडी हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी कर जांच का आदेश देकर बिहार के मानव संसाधन विभाग द्वारा निजी बीएड कालेजों को तंग किया जा रहा है.

कुछ लोगों का मानना है कि यह राजनीतिक द्वेष की वजह से किया जा रहा है. मानव संसाधन विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए पटना हाईकोर्ट ने निजी बीएड कॉलेजों की जांच पर रोक लगा दी है. भीमराव अम्बेडकर ऑफ एजुकेशन, मगध कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ज्ञान प्रकाश कॉलेज ऑफ एजुकेशन और अन्य कॉलेजों की ओर से दायर रिट याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए निजी बीएड कॉलेजों की जांच पर रोक लगा दी.

कोर्ट ने मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र पर टिपण्णी करते हुए कहा कि मुख्य सचिव को ऐसा निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है. टीचर्स ट्रेनिंग (बीएड) कॉलेज की जांच का अधिकार एनसीईटी को है न की राज्य सरकार को. कोर्ट ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव द्वारा निजी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों की जांच का आदेश देना नियम के खिलाफ है. इस आदेश के बाद ऐसा प्रतीत होता कि बिहार पुलिस स्टेट बन गया है और रूल ऑफ लॉ का कोई महत्व ही नहीं है. कोर्ट ने बिहार के सरकारी बीएड कॉलेजों की दयनीय स्थिति पर टिपण्णी करते हुए कहा कि पहले अपने घर की सफाई करें, फिर दूसरे के घर में सफाई अभियान चलाएं.

बिहार के माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों का एक-दो शिक्षकों के सहारे ही संचालन किया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर बिहार के विश्वविद्यालयों की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है.

– शेष पृष्ठ संख्या 11 पर

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org,
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate In Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/- only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

Made from Imported Chemicals

Lab Tested
ITALIAN
WHITE
Wall Putty
Slight Costly but Superior

For Trade Enquiry : 9431234022/9709401366.
E-mail: italianpaints@yahoo.com

Super Strength compared to ordinary Wall Putty
Super Whiteness compared to ordinary Wall Putty
Super Smoothness compared to ordinary Wall Putty
Super Covering capacity compared to ordinary Wall Putty
Increases Life of Walls & Paints compared to ordinary Wall Putty
Technical collaboration with Italian International Private Limited

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Laboratory Tested

Laboratory Tested
ISO 9001:2008
Laboratory Tested

।। सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ ।।

Tonic of Cement
Mr.
CHEMIST
Waterproofing
Slight Costly but Superior

For Trade Enquiry :
9431234022/9709401366.
E-mail: italianpaints@yahoo.com

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक मे अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, आपके घर को मजबुत बनाए

ख़तरे में दूल्हे के बाज़ार का वज़ूद

तत्कालीन विवाह प्रथा में वर व वधू पक्ष स्वयं दूल्हे की तलाश नहीं करते थे. घटकैती परंपरा के जरिए शादी के लिए जोड़ों की तलाश कर विवाह दान किया जाता था. बदलते परिवेश के साथ गांव की परंपराओं में भी बदलाव आया. लेकिन इस बीच अगर नहीं बदली तो सौराठ सभागाछी के दूल्हा बाज़ार की पुरानी संस्कृति.

संजय लोनी

मधुबनी जिले के सौराठ में दूल्हे का बाजार सजता है. यहां आप बिना दहेज के वर का चयन कर सकते हैं. समय के साथ इस बाजार का आकर्षण कम हो रहा है, लेकिन यह आज भी लोगों को अपने वजूद का अहसास करा रहा है. मिथिलांचल की इस अनोखी परंपरा को जीवित रखने के लिए आज भी कई लोग सक्रिय हैं. आधुनिकता का असर दूल्हे बाजार पर भी पड़ा है. आज यह बाजार अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है.

पुराने लोग बताते हैं कि कर्नाटक वंश में तिरहुत के शासक हरिसिंह देव ने 1296 से 1310 ई. के बीच मिथिला के कुल 14 स्थानों पर दूल्हा बाजार शुरू किया था. योग्य वंशावली विवाह सुविधा के लिए सौराठ, खामागढ़ी, परतापुर, शिवहर, गोविंदपुर, फतेपुर, सजहौल, सुखसैना, अखराही, हेमानगर, बलुआ, बरौली, समौल एवं सहसौल में बाजार लगते थे. लेकिन कालांतर में सभी विवाह बाजारों का वजूद मिट गया और एकमात्र मधुबनी जिले के सौराठ गांव के सभागाछी में लगने वाला विवाह बाजार आज भी अपनी पुरानी परंपरा को संजोये है.

तत्कालीन विवाह प्रथा में वर व वधू पक्ष स्वयं दूल्हे की तलाश नहीं करते थे. घटकैती परंपरा के जरिए शादी के लिए जोड़ों की तलाश कर विवाह दान किया जाता था. बदलते परिवेश के साथ गांव की परंपराओं में भी बदलाव आया. लेकिन इसबीच अगर नहीं बदली तो सौराठ सभागाछी के दूल्हा बाजार की पुरानी संस्कृति.

उत्तर बिहार के सौराठ, खामागढ़ी, परतापुर, शिवहर, गोविंदपुर, फतेपुर, सजहौल, सुखसैना, अखराही, हेमानगर, बलुआ, बरौली, समौल एवं सहसौल जैसे प्रमुख गांवों को वंशावली जानने वाले महापंडितों के गांव के रूप में जाना जाता था. मधुबनी जिला मुख्यालय से महज छह किलोमीटर दूर सौराठ गांव के सभागाछी में हरेक साल ज्येष्ठ व आषाढ़ माह में दूल्हा बाजार लगता है. इस दूल्हा बाजार में कभी आईएएस और आईपीएस वरों की भी चट्टी बिछा करती थी. दहेज संस्कृति के बढ़ते कुप्रभाव ने धीरे धीरे सभागाछी वर तलाश परंपरा को भी डस लिया.

मैथिल ब्राह्मणों की इस संस्कृति ने कर्ण कायस्थों को भी अपनी ओर आकर्षित किया. इस बाजार में जन्मपत्री व राशि फल के आधार पर लड़के व लड़कियों की कुंडली मिलाई जाती है. राशि का मिलान करने के बाद इन जोड़ों को पंजीकार अपनी पंजी में पंजीकृत करते हैं. पंजीकार शादी निश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि दरभंगा महाराजा ने सौराठ सभागाछी को 22 बीघा जमीन दान में दिया था. अब हालात ये हैं कि सभागाछी की इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल के पास कुछ अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है. कहा जाता है कि लगन के समय सौराठ सभागाछी में पहले मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों मैथिल ब्राह्मणों का जुटान होता था, लेकिन वे दिन अब लद गए.

सौराठ सभागाछी के वंशावली अभिलेखागार में पंजीकृत पं. घनश्याम मिश्र की वंशावली से ही ज्ञात होता है कि मिथिला के कालीदास कविवर विद्यापति किस वंशज के हैं. उनके पैतृक परिवारों की वंशावली आज भी यहां पंजीकृत है. पं. पुरुषोत्तम ठाकुर कविवर विद्यापति के ही वंशज हैं.

प्रत्येक परिवारों के पूर्वजों की जानकारी अभिलेखागार में पंजीकृत पंजी से अब भी मिल जाती है. पंजीकार विनोद झा ने अपने पंजीकार पिता सह भविष्यवेत्ता स्व. हरेकृष्ण झा के बारे में बताया कि वे कहते थे कि केवल सौराठ गांव में 42 गोत्र व 7 मूल के मैथिल ब्राह्मण परिवार हैं. वंशावली पंजी से मैथिल ब्राह्मणों के 10 पीढ़ी तक की जानकारी मिलती है. सात पुश्त तक समगोत्री माना जाता है और वैसे रिश्तों में कोई संबंध की चर्चा तक नहीं होती है. पुराने पंजीकारों में स्व. विष्णुदत्त मिश्र, स्व. शिवदत्त मिश्र एवं उनके पुत्र शंकर कुमार मिश्र, सकरौनी निवासी मोहन मिश्र की अपनी ख्याति है. पंजीकार का कोई शुल्क नहीं होता है और लाभार्थी के स्वेच्छा पर ही शुल्क की राशि निर्भर करती है.

मिथिलांचल क्षेत्र राजा जनक की नगरी के रूप में भी प्रख्यात है. रामायण में सीता स्वयंवर से भी इस प्रथा की जानकारी मिलती है. यही वजह है कि मधुबनी के गांव सौराठ के सभागाछी में स्वयंवर की तरह ही दूल्हों का बाजार लगता है. वर की प्रतिभा व विलक्षण को आधार मानकर ही दहेज रहित विवाह के लिए वधू पक्ष चयन करते हैं.

मिथिलांचल के मैथिल ब्राह्मणों द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित परंपरा व वर-वधू चयन के लिए ऐतिहासिक सौराठ सभा स्थल पर दहेज रहित दूल्हों के बाजार शुरू हैं. सौराठ सभा प्रवासी वर-वधू पक्ष के लोगों के लिए ठहरने व भोजन की व्यवस्था सौराठ सभा समिति की ओर से की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के सचिव इन्द्रमोहन झा ने बताया कि मिथिलांचल के पूर्वी क्षेत्र सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार के वर-वधू पक्ष के मैथिल ब्राह्मणों को मोबाइल से संदेश भेजकर सभा में पहुंचने का आमंत्रण दिया गया है. इसके अलावा आसपास के गांव पंडोल, डीहरोज, कल्याणपुर, सरिसपाही, जमसम, हाटी, बटुरी, मेघौल, गंगौली आदि गांवों के लोगों को भी सभास्थल पर पहुंचने का आग्रह किया गया है.

सौराठ सभा समिति के सचिव डॉ. शेखर चन्द्र मिश्र ने बताया कि सभा स्थल पर प्रवासी वर-वधू पक्ष के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है. मधुबनी के प्रगतिशील विचारक संजय झा कहते हैं कि मैथिल ब्राह्मणों सहित ब्राह्मण समाज के लिए सौराठ सभा गाछी एक धरोहर है, जहां दहेज रहित विवाह की परंपरा रही है. सामाजिक विकृतियों की वजह से सभागाछी के महत्व में गिरावट आई है. उन्होंने कहा कि इस धरोहर को बचाने के लिए सभा के समय निश्चित रूप से यहां सभी ब्राह्मणों को आना चाहिए. स्थानीय लोग दूल्हा बाजार की परंपरा को जीवित रखने के लिए जी जान से जुटे हैं, ताकि सौराठ सभागाछी के प्रति खत्म हो रहे आकर्षण को जिंदा रखा जा सके.■

feedback@chauthiduniya.com

हाईकोर्ट ने बीएड कॉलेजों की जांच पर रोक लगाई

– पृष्ठ 10 का शेष

देश में सरकारी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों को ग्रेडिंग देने वाली भारत सरकार की संस्था नैक ने बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय को सी ग्रेड प्रदान किया है, जबकि मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध मगध कॉलेज ऑफ एजुकेशन गया को नैक ने बेहतर शिक्षण व्यवस्था एवं तमाम संसाधनों से परिपूर्ण होने की वजह से बी ग्रेड दिया है. यही अंतर है सरकारी एवं निजी कॉलेजों में. राजनीतिक वजहों से ही बिहार का मानव संसाधन विकास विभाग करीब दो सौ निजी टीचर्स टीचर्स(बीएड) कॉलेजों को एनओसी नहीं दे रहा है, तो दूसरी ओर बिहार में चल रहे निजी बीएड कॉलेजों को तंग किया जा रहा है. विश्वविद्यालय भी अपनी मनमानी करने में लगे हैं और उन्होंने विश्वविद्यालय में ही सिर्फ आवेदन करने का विज्ञापन निकाला है और कहा कि विश्वविद्यालयों द्वारा ही छात्रों को नामांकन के लिए भेजा जाएगा. प्रवेश परीक्षा भी केवल विश्वविद्यालय ही आयोजित करेंगे. बिहार निजी टीचर्स ट्रेनिंग(बीएड) कॉलेज एसोशिएसन के अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि पिछले साल भी विश्वविद्यालय ने ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के इस आदेश को निरस्त कर दिया था और निजी बीएड कॉलेजों को स्वयं परीक्षा लेकर नामांकन करने की अनुमति दी थी. इस वर्ष एक बार फिर विश्वविद्यालयों की ओर से ऐसा ही आदेश निकाला गया है, जिसके खिलाफ हम लोग पुन: हाईकोर्ट की शरण में हैं. अभय कुमार ने बताया कि निजी बीएड कॉलेज भी एकजुट होकर बीएड में नामांकन के लिए संयुक्त परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार निजी बीएड कॉलेजों को तंग कर अपना मतलब साधना चाहती है, लेकिन हम लोग एकजुट हैं और राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग तथा विश्वविद्यालय के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

स्वस्थ्य मुँह सूचक है सम्पूर्ण स्वास्थ्य का

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ सादिया हसन जो इमारते सरिया अस्पताल फुलवारीशरीफ में कार्यरत हैं ने बताया कि स्वस्थ्य मुँह के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे दांत कैल्शियम फास्फोरस और अन्य खनिज से मिलजुलकर बने होते हैं क्योंकि इसानी शरीर का सबसे कठोर भाग उसके दांत ही होते हैं परन्तु लापरवाही की वजह से यह भी सड़न का शिकार हो जाते हैं। दांतों की सड़न होती है कैवेटी। कैवेटी का अर्थ होता है दांतों में छेद होना जो दांतों के सड़न के मुख्य कारण हैं- मुंह में मौजूद बैक्टीरिया- मुंह में मौजूद अम्ल के कारण दांतों के इनेमल को प्रभावित करने लगता है जिसके कारण टॅटल केरिज या कैवीटीज का निर्माण होता है। मुंह में मौजूद रहने वाले बैक्टीरिया दांतों की सतह पर जमा हो जाते हैं जिसे प्लाक (पटिटका) कहा जाता है प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया आपके खाने में मौजूद शुगर एवं कार्बोहाइड्रेट को अमल में परिवर्तित कर देता है इसी अम्ल के कारण दांत खोखले होने लगते हैं डॉ. सादिया ने खान पान के बारे में बातीचीत की और कहा कि वह खाद्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट और शक्कर की मात्रा अधिक हो या फिर चिपचिपा हो जैसे कि टॉफी, मिठाई, आलू, चिप्स तो फिर वह सड़न का कारण बनता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सड़न को न्योता न दें और हमेशा दो टाईम ब्रशिंग के अलावे खाने के बाद अपने अंगुलियों से मसाज करें अर्थात अपनी अंगुलियों को मसूड़ो पर घुमायें। दांतों की सड़न का पहला लक्षण है दांतों पर (इनेमल) भूरा दाग जैसा लगना यही बाद में छिद्र का रूप ले लेता है थोड़ा गहरा होने पर अंदरूणी सतह में पहुंच जाता है तब हमें ठंढ या मीठे से कनकनाहट होने लगती है, और अधिक होने पर दांतों की नस तक पहुंच जाती है और इसे संक्रमित कर देता है और तब हमें दांतों में जोरदार दर्द होता है। इससे बचने के लिए डॉ सादिया ने बताया कि- हर छः महिने में अपने दन्त चिकित्सक से अपने दांतों का चेकअप करायें, रात में प्लांस से दांतों के बीच की सफाई करें। मीठा और चिपचिपा पदार्थ, बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू छोड़ें। सड़े दांतों के इलाज के बारे में घबराने के जरूरत नहीं डॉक्टर आपका एक्सरे लेने के बाद या तो रूट कैनाल थेरेपी से इलाज करेंगे या बहुत ज्यादा खराब होने पर दांतों को निकाल देंगे, हो सकता है दांतों के छिद्र को साफ कर उसे फिलिंग करेंगे। अगर दांतों की अच्छे से केयरिंग की जाए अच्छे से ब्रशिंग दो टाईम किया जाय, मसूड़ों की मसाज की जाय तो संभव है कि आपको दांतों की समस्या न आये। ■ भारती

DR. SAADIYA HASAN
(BDS) DENTAL SURGEON

Carbo - XT Drops
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calculum & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. 60 ml
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylcobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

दुधवा के जंगल से शेर, हाथी और दूसरे दुर्लभ जानवर तेजी से हो रहे विलुप्त

ख़तरे में दुधवा के गैंडे

अजय गुप्ता

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में दो फरवरी 1977 को स्थापित हुआ दुधवा नेशनल पार्क सरकारी उपेक्षा और कुप्रबंधन के कारण 39 साल में ही अपनी पहचान खोने लगा है. समय रहते इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो दुधवा के जंगल में रहने वाले दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव डायनासोर की तरह इतिहास बनकर किताबों के पन्नों पर सिमट कर रह जाएंगे.

दुधवा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें एक सदी पूर्व तराई इलाके से लुप्त हो चुके एक सींग वाले भारतीय गैंडे को सफलतापूर्वक पुनरवासित किया गया था. अभी यहां 31 गैंडे रह रहे हैं, जिसके ऊपर इन-ब्रीडिंग का खतरा मंडरा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि बांके नाम के गैंडे से ही दुधवा का गैंडा परिवार पला-बढ़ा है, इसलिए अगर उनके जींस में कोई कमी होगी तो उसका असर सबके ऊपर पड़ेगा. इस कारण दुधवा में अब नर गैंडों की संख्या बढ़ाए जाने की बहुत आवश्यकता है. हालांकि इसके लिए निवर्तमान डिप्टी डायरेक्टर पीपी सिंह ने असम से नर गैंडों को लाए जाने की कार्य योजना तैयार करके शासन को भेजी थी, जो अभी तक विचाराधीन ही है. उन्होंने सोनारीपुर गैंडा परिक्षेत्र से जुड़े जंगल क्षेत्र को बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव दिया था, जिस पर धीमी गति से कार्य शुरू भी हो गया है. इसी बीच शासन ने उनका तबादला कर दिया, जिस वजह से सफलता के पायदान पर बढ़ रही विश्व की एकमात्र गैंडा पुनरवास परियोजना अधर में लटक गई. विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि दुधवा परिवार में नर गैंडों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो जवान हो रहे गैंडों के बीच भी संघर्ष हो सकता है, ऐसे में गैंडा परिवार को क्षति पहुंच सकती है. गैंडा पुनरवास परियोजना को दुधवा नेशनल पार्क की ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश की शान भी कहा जाता है, जिस पर खतरा मंडरा रहा है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट इटावा का लायन सफारी पहले ही फेल हो चुका है. बीमारी और गैर विशेषज्ञता के कारण नौ शेरों की मौत हो चुकी है. दुधवा में प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है इसकी असफलता की कहानी भी जगजाहिर है. बाघों के साथ-साथ अन्य वन्यजीव जंगल से बाहर क्यों भाग रहे हैं, यह मनुष्यों की जानवरी-वृत्ति का प्रतिफल है, यह एक अजीबोगरीब व्यथा कथा है. लोगों के अतिक्रमण और प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण दुधवा के जंगल में जानवरों का प्राकृतिक वास अस्त-व्यस्त हुआ है. चारागार सिमट गए हैं, प्राकृतिक झीलों, तालाबों का स्वरूप बदल गया है. इस कारण इनपर आश्रित वन्यजीव जंगल से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं. आबादी का दबाव एवं मानवजनित दुष्प्रभाव भी वन्यजीवों को अस्त-व्यस्त कर रहा है और वह जंगल छोड़ने के लिए विवश हैं. इसके लिए सरकारी तंत्र जिम्मेदार है. वन्यजीव संरक्षण में कार्यरत सृष्टि कंजरवेशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनूप गुप्ता का कहना है कि दुधवा नेशनल पार्क की छवि सरकारी उपेक्षा के कारण विश्व पटल पर धूमिल होती जा रही है. सरकार एवं शासन की उपेक्षा का आलम यह है कि जो अधिकारी या कर्मचारी वन्यजीव संरक्षण में दिलचस्पी से कार्य करते हैं या जानवरों का कुनबा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनका तबादला सामाजिक वानिकी विभाग में कर दिया जाता है. उनको अगर दुधवा में कार्य करने का मौका दिया जाए तो शायद दुधवा की छवि बरकरार रह सकती है, अन्यथा इसकी दशा बद से बदतर होती जाएगी. वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले डीडी पीपी सिंह को तत्कालीन डीएम किंजल सिंह से हुए शीत युद्ध के बाद हटा दिया गया, इस पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं. लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है. आला अफसर मूक-बधिर बन कर दुधवा की बर्बादी का जायजा ले रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

वन्यजीवों के घरों में घुस रहे लोग

कभी दुधवा के जंगल का दायरा इतना था कि जंगली जानवरों, खासकर बनराज का जंगल परिक्षेत्र में ही गुजर-बसर हो जाता था. परन्तु आज के समय में यहां के वाशिंदों ने इनके आरक्षित क्षेत्र में भीषण सेंधमारी की है. सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा हो चुका है. प्रशासन की लापरवाही के चलते जंगली जानवरों का आवास छिनता गया और आज आए दिन जंगली जानवर बेचैन होकर लोगों पर हमले कर रहे हैं.

चुनाव में यूपी के आदिवासियों का भी प्रतिनिधित्व हो, पीएम को पत्र

आदिवासियों के लिए अ-लोकतंत्र

यूफी यायावर

आजादी के 67 साल बाद भी आदिवासियों को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. संविधान रचयिताओं ने दलितों और आदिवासियों को भी लोकतांत्रिक प्रणाली में समुचित प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए सारे प्रावधान किए, लेकिन राजनीतिक दलों ने उन प्रावधानों को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई. अनुसूचित जाति के लोगों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में आरक्षण के जरिए संसद और विधानसभाओं तक पहुंचने का मौका मिला, लेकिन आदिवासियों को उस तरह नहीं मिल पाया. उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं. चुनाव के पहले ही आदिवासियों के प्रतिनिधित्व का मसला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन वह यथावत है. केंद्र सरकार ने आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की गारंटी करने वाले विधेयक को पारित कराने के बजाय राज्यसभा से वापस ले लिया है. यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में गरमा रहा है.

प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, इस मसले पर तगड़ा जन-विरोध सामने आ रहा है. कई ऐसे मसले भी सामने आ रहे हैं, जिन पर आम तौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता. ऐसा ही एक मसला है संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व पुनः समायोजन विधेयक (तीसरा)-2013 के वापस लिए जाने का. इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के वनक्षेत्रों और आदिवासी बहुल इलाकों में घोर विरोध हो रहा है और सामाजिक व राजनीतिक संगठन इस मसले को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं. इस मसले पर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर विधेयक लागू करने की मांग की है. विधेयक लागू नहीं होने पर आइपीएफ ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल करने की घोषणा की है और कहा है कि लाखों आदिवासियों के हस्ताक्षर के साथ गुहार-पत्र उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा.

आईपीएफ के प्रदेश संगठन महासचिव दिनकर कपूर ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के बारे में बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आदिवासी समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक (तीसरा)-2013 4 जुलाई 2014 को राज्यसभा से वापस लेकर आदिवासी समाज के साथ अन्याय किया है. यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आदिवासी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है. केंद्र सरकार की इस कार्रवाई के कारण उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में आदिवासी जातियों के लिए विधानसभा में एक भी सीट आरक्षित नहीं हो पाएगी. प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर मांग की गई है कि केंद्र सरकार इस मसले पर पुनरविचार करे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के आदिवासी समाज के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा व उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई 2016 से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करके उसे पारित कराए. इससे भारत निर्वाचन आयोग व परिसीमन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश विधानसभा की दुद्धी व ओबरा विधानसभा सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हो सकेंगी. प्रधानमंत्री से यह भी मांग की गई है कि कोल समेत सभी आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश के आदिवासी समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके.

उल्लेखनीय है कि राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी मूल के सांसद करते हैं. इसके बावजूद भाजपा ने सत्ता में आते ही संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक (तीसरा)-2013 वापस ले लिया. उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गोंड, खरवार, पनिका, भुईया, चेरो, बैगा, अगरिया, कोरवा, धारू, बोक्सा, राजी, जौनसारी, भोटिया, परहिया, सहरिया, पठारी जैसी अनुसूचित जनजातियां बसती हैं. 2003 में इनमें से कई जातियों को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया था, जो 2001 की जनगणना में अनुसूचित जाति की श्रेणी में थीं. यही वजह थी कि लोकसभा व विधानसभा की सीटों के सम्बन्ध में 2008 में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय परिसीमन में इन जातियों के लिए लोकसभा व विधानसभा में सीटें आरक्षित नहीं की गईं और लाखों की आबादी वाला आदिवासी समाज राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रह गया. इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए आइपीएफ से जुड़ी आदिवासी-वनवासी महासभा समेत तमाम संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय व इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं. ऐसी ही एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने इन जातियों के संसद व विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चुनाव आयोग को जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इस आदेश के अनुक्रम में केंद्र सरकार ने तीन बार अध्यादेश पेश किया. बाद में इसे 14 फरवरी 2013 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और बहस के बाद संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया. स्थायी समिति ने इस बिल को संसद से पास कराने की संस्तुति की थी. इस अध्यादेश एवं बिल के आलोक में निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय परिसीमन आयोग ने आदिवासी बहुल सोनभद्र के दुद्धी, ओबरा और रॉबर्ट्सगंज में जनसुनवाई आयोजित की. इसके बाद चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग ने दुद्धी विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति और ओबरा विधानसभा सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की थी.

सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली जनपद में लाखों की संख्या में निवास करने वाली कोल जाति समेत धांगर (उरांव), धरिकार और गोंड, खरवार, चेरों आदि आदिवासी जातियों को आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है. नतीजतन रॉबर्ट्सगंज (अनुसूचित जाति) संसदीय सीट पर आदिवासी जातियों की बहुलता के बावजूद यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है. यदि सरकार इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी दे देती है तो प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भी यूपी के आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाएगा. ■

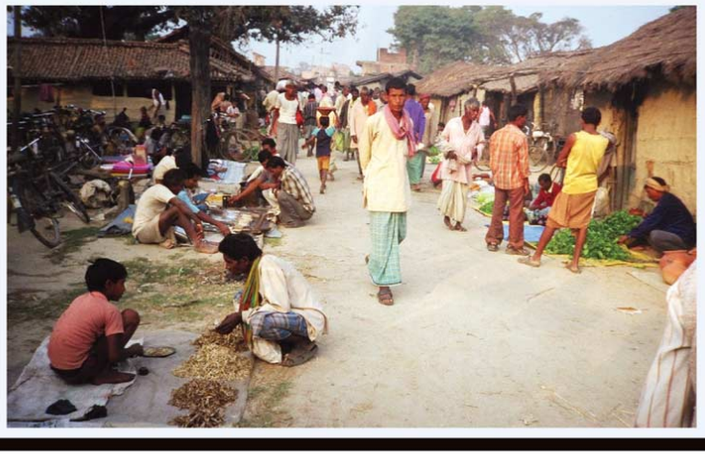

feedback@chauthiduniya.com

वजहें अलग-अलग, पर बिखर रहा सपा-बसपा का कुनबा

फोटो - प्रभात पाण्डेय

राजनीतिक स्थिति तेज गति से करवट ले रही है. कुछ दिनों पहले एक सर्वे में मायावती का प्रदेश में पलड़ा भारी बताया गया था और उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई गई थी, लेकिन आज माजरा बदला हुआ दिखता है. राजनीतिक प्रेक्षकों का भी कहना है कि अब मायावती का प्रभाव सम्पूर्ण दलित समुदाय के बजाय केवल जाटवों तक सिमट गया है, क्योंकि वे खुद भी इसी जाति से आती हैं. राज्य में 66 दलित जातियां हैं. अनुसूचित जाति की आबादी 21 प्रतिशत है. इसमें 56 प्रतिशत जाटव, 16 प्रतिशत पासी और 15 प्रतिशत धोबी, कोरी, वाल्मीकि आदि जातियां हैं. अभी अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश में हुए कुछ सर्वेक्षणों में बसपा को बहुमत के करीब सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी. सर्वे में भाजपा को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरता हुआ देखा गया था.

दीनबंधु कबीर

अपनी-अपनी वजहों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कुनबा बिखर रहा है. सपा पारिवारिक कलह के कारण बिखर रही है तो बसपा अंदरूनी असंतोष के कारण बिखर रही है. चुनाव के समय पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करने के बजाय समाजवादी पार्टी में वर्चस्व कायम करने की जो होड़ लगी है, उसमें पार्टी चार विभिन्न खेमों में बंट गई है. एक खेमा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, दूसरा खेमा शिवपाल सिंह यादव का, तीसरा खेमा रामगोपाल यादव का और चौथा खेमा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का. इसमें चौथा खेमा ही सबसे कमजोर साबित हो रहा है. मुलायम के साथ जो सपाई खड़े हैं वो सब पुराने और बुजुर्ग चेहरे हैं, लेकिन मुलायम के प्रति प्रतिबद्ध हैं. शिवपाल भी अपने भारी-भरकम खेमे के साथ मुलायम के ही साथ खड़े हैं. रामगोपाल अपने खेमे के साथ समाजवादी पार्टी को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनका मोहरा साबित हो रहे हैं. अखिलेश अपने पिता की ही अनदेखी और अवहेलना कर रहे हैं. सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अखिलेश यादव एक तरफ मुख्तार अंसारी के नाम पर कौमी एकता दल के सपा में विलय का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ सारे भ्रष्ट और अराजक तत्वों को अपने साथ रखते हैं. पिता ऐसे भ्रष्ट और अराजक तत्वों को निष्कासित कर देते हैं तो पुत्र उन्हें न केवल पार्टी में वापस कराते हैं, बल्कि उन्हें विधान परिषद की सीट या मंत्री की सीट देकर मुलायम के समक्ष ही अनुशासनहीनता और मर्यादाहीनता की बड़ी लाइन खींच देते हैं. मुलायम कार्यकारिणी की सूची जारी करते हैं तो अखिलेश विदेश से लौट कर समानान्तर सूची जारी कर अपना बढ़ा हुआ कद दिखाते हैं. पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि रामगोपाल यादव के साथ मिल कर अखिलेश वो सारे निर्णय पलटने पर जोर लगा देते हैं जो मुलायम और शिवपाल की सहमति से लागू होता है. अखिलेश आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पार्टी में नहीं आने देना चाहते और वे साफ-सुथरी छवि के लोगों को पार्टी में स्थान देने के पक्षधर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उनके मंत्रिमंडल में ही तमाम चेहरे आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं तो वे उन्हें क्यों नहीं निकाल बाहर करते! ऐसी ही बदनाम छवि के लोगों को वे विधान परिषद भेजने के लिए सिफारिश क्यों करते हैं कि राज्यपाल तक उसमें कानूनी सवाल खड़ा करने पर विवश हो जाते हैं! पिता मुलायम ने 2012 में पुत्र-मोह में सारी राजनीतिक नैतिकता ताक पर रख कर पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था. लेकिन पुत्र ने उसकी मर्यादा नहीं रखी. राजनीतिक पंडितों को उम्मीद थी कि युवा हाथों में प्रदेश की बागडोर आने से रोजगार और विकास की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. प्रदेश की सत्ता इन चार वर्षों में चार कोणों और कई प्रति-कोणों में फंसी रही. अब उन सारे कोणों का विरोधाभास चुनाव के समय सड़कछाप होकर सामने आ रहा है. मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के फैसलों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घर और मर्यादा की चारदीवारी से बाहर फांद कर विरोध करना शुरू कर दिया है. कौमी एकता दल के विलय को लेकर अखिलेश ने जो सार्वजनिक रुख दिखाया, वह अमर्यादित और अगंभीर था. सपाई ही कहते हैं कि इस मसले को घर के भीतर ही निपटाया जा सकता था. रामगोपाल यादव के इशारे पर लिखी गई विरोध की पटकथा अगले दिन लखनऊ में सार्वजनिक तौर पर दिखी, जब सत्ता-मद में मगरूर रामगोपाल यादव मीडिया वालों के सामने मुखातिब हुए. राजनीतिक गलियारे से लेकर समाज तक इन हरकतों से समाजवादी पार्टी के खिलाफ संदेश गया. बलराम की बर्खास्तगी और रामगोपाल के कहने पर फिर से वापसी को लेकर मुख्यमंत्री की तो भद्द हो गई. इसका असर चुनाव में पड़ेगा, इससे कोई सपाई इन्कार नहीं कर पाता.

उधर, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद महासचिव आरके चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया. दलित नेता आरके चौधरी ने भी मायावती पर वैसे ही गंभीर आरोप लगाए जो अन्य नेताओं ने लगाए थे. मायावती की धन के प्रति लोलुपता अब उनकी सार्वजनिक छवि के रूप में स्थापित हो गई है. बसपा छोड़ने वाले पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश दास, पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद, विधायक राजेश त्रिपाठी, राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर,

रामगोपाल यादव

सबने यही कहा था कि मायावती टिकट बेचती हैं और मोटा धन लेकर लोगों को राज्यसभा भेजती हैं. आरके चौधरी ने भी कहा कि बसपा अध्यक्ष मायावती को अब कैडर और जमीनी कार्यकर्ताओं के बजाय ठेकेदार, माफिया और रियल इस्टेट का धंधा करने वाले लोग अधिक प्रिय हैं. मायावती के कारण कांशीराम का सामाजिक परिवर्तन का नारा धरा का धरा रह गया. बसपा राजनीतिक दल के बजाय रियल इस्टेट कंपनी बनकर रह गई है. चौधरी ने कहा कि अभी और लोग बसपा छोड़ कर जाएंगे. आरके चौधरी बसपा संस्थापक कांशीराम के चहेतों में रहे हैं. मायावती ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बरखू राम वर्मा के साथ चौधरी को 21 जुलाई 2001 को पार्टी से निकाल दिया था. उसके बाद पहले वर्मा को और बाद में चौधरी को अप्रैल 2013 में पार्टी में फिर से वापस ले लिया गया था. चौधरी मोहनलालगंज से तीन बार विधायक रहे हैं. उन्होंने लोकसभा का पिछला चुनाव भी मोहनलालगंज (सुरक्षित) से लड़ा था, लेकिन भाजपा के कौशल किशोर के हाथों वे चुनाव हार गए थे. मायावती ने इस बार मोहनलालगंज (सुरक्षित) विधानसभा सीट से आरके चौधरी के बजाय रामबहादुर को उम्मीदवार घोषित कर दिया. चौधरी ने इसी वजह से बसपा छोड़ने का फैसला किया. अभी 22 जून को ही बसपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए बसपा छोड़ दी थी. मौर्य ने कहा था कि मायावती के भीतर पैसे की हवस पैदा हो गई है. यह कांशीराम

तेजी से बदल रहा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य

और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है. बसपा नीलामी का बाजार बन गई है. मायावती ने अंबेडकर के विचारों की हत्या की है. बसपा के कार्यकर्ता हताश हैं, इस पार्टी में दलितों के लिए जगह नहीं रह गई है.

लब्बोलुबाव यह है कि बहुजन समाज पार्टी में तकरीबन विद्रोह की ही स्थिति है. केवल स्वामी प्रसाद मौर्य ही क्यों, बसपा छोड़ने का क्रम तो पहले से जारी है. डॉ. अखिलेश दास, जुगल किशोर, फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी जैसे कई नाम हैं, जो बसपा के खास थे, लेकिन उन्हें पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ा. इनमें से करीब-करीब सबों ने मायावती पर यह आरोप लगाया कि वे पैसे लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव का टिकट बांटती हैं या भारी धन लेकर किसी को राज्यसभा के लिए मनोनीत करती हैं. सपा की लहर में भी बसपा से चिल्लूपार जैसी सीट जीतने वाले विधायक और पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी को बसपा छोड़नी पड़ी. राजेश त्रिपाठी को दरकिनार कर मायावती हरिशंकर तिवारी के किसी रिश्तेदार को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में थीं. इसकी भनक लगते ही राजेश ने बसपा से किनारा कर लिया. बसपा के राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश दास गुप्ता के इस्तीफे की कहानी से लोग परिचित हैं. मायावती ने डॉ. अखिलेश दास गुप्ता को राज्यसभा का टिकट दोबारा देने से मना कर दिया था. इस पर डॉ. दास ने यह आरोप लगाया था कि राज्यसभा

शिवपाल सिंह

का उम्मीदवार बनाने के लिए मायावती सौ-सौ करोड़ रुपये मांगती हैं. इसी तरह राज्यसभा के लिए चयनित नहीं होने का गुस्सा पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक में भी है. हालांकि उन्होंने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है. लेकिन चर्चा है कि मायावती के सतीशचंद्र मिश्र से एकल-ब्राह्मण प्रेम के कारण ब्राह्मण समुदाय के कई नेता जल्दी ही बसपा छोड़ेंगे. मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में जिस आईपीएस अफसर को सबसे अधिक तरजीह दी थी, वह बृजलाल भी रिटायरमेंट के बाद भाजपा में शरीक हो गए थे. जबकि बृजलाल के बारे में सबको यही लग रहा था कि वे बसपा में जाएंगे. बृजलाल को वर्दी वाला बसपाई तक कहा जाने लगा था. बसपाई बृजलाल के भाजपाई होने के बाद बसपा के राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर और मायाकालीन मंत्री फतेह बहादुर सिंह के सपरिवार भाजपा में शामिल होने का कदम भी मायावती के लिए बड़ा झटका था. जुगल किशोर और फतेहबहादुर के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ खासी संख्या में बसपाइयों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी. उनमें राज्यसभा सांसद जुगल किशोर की पत्नी दमयंती किशोर और उनके पुत्र सौरभ सिंह व फतेह बहादुर सिंह की पत्नी साधना सिंह और उनके समर्थक शामिल थे. फतेह बहादुर सिंह लंबे समय तक प्रदेश की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे थे. इनके पिता वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. कैपियरगंज इनकी परंपरागत सीट है. इसके अलावा पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्र, विधान परिषद सदस्य हरगोविंद मिश्र, आजमगढ़ के बसपा नेता अमित तिवारी और बांबी अवस्थी ने भी बसपा छोड़ कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी.

राजनीतिक स्थिति तेज गति से करवट ले रही हैं. कुछ दिनों पहले एक सर्वे में मायावती का प्रदेश में पलड़ा भारी बताया गया था और उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई गई थी, लेकिन आज माजरा बदला हुआ दिखता है. राजनीतिक प्रेक्षकों का भी कहना है कि अब मायावती का प्रभाव सम्पूर्ण दलित समुदाय के बजाय केवल जाटवों तक सिमट गया है, क्योंकि वे खुद भी इसी जाति से आती हैं. राज्य में 66 दलित जातियां हैं. अनुसूचित जाति की आबादी 21 प्रतिशत है. इसमें 56 प्रतिशत जाटव, 16 प्रतिशत पासी और 15 प्रतिशत धोबी, कोरी, वाल्मीकि आदि जातियां हैं. अभी अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश में हुए कुछ सर्वेक्षणों में बसपा को बहुमत के करीब सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी. सर्वे में भाजपा को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरता हुआ देखा गया था. जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को 80 सीटों पर सिमटता हुआ बताया गया था. उत्तर प्रदेश में तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को झटका लगा था जब मुजफ्फरनगर सीट भाजपा ने छीन ली और देवबंद सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया. ये दोनों सीटें सपा के पास थीं. तीसरी फैजाबाद की बीकापुर विधासभा सीट बचाने में सपा किसी तरह कामयाब हो पाई.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की भाजपा से अंतरंगता के कारण यूपी का मुस्लिम मतदाता बुरी तरह बिदका हुआ है. रामगोपाल के भाजपा-प्रेम के कारण ही सपा बिहार के महागठबंधन से अलग हुई थी और अब यूपी में उसका खामियाजा भुगतने को तैयार है. मुस्लिम मतदाता सपा छोड़ कर कांग्रेस या बसपा में जाने का विकल्प तलाश रहा है. प्रदेश में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होने वाला है. जनता दल (यू) आरजेडी, एनसीपी और ओवैसी की एमआईएम भी विधानसभा चुनाव में उतर रही है. इसका गठबंधन तैयार हो रहा है. इसमें कांग्रेस के भी शामिल होने की संभावना है. अगर ऐसा हुआ तब सपा का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. राजनीतिक कयास यह भी है कि शिवपाल अपना खेमा लेकर इस महागठबंधन के साथ शरीक हो जाएं, हालांकि यह महज एक कयास ही है. लेकिन यह तो तय है कि बिहार से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में आरजेडी-जेडीयू के साथ होने वाला संभावित गठबंधन मुलायम को नुकसान पहुंचाएगा. गठबंधन भी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचेगा और ओवैसी का दल भी खींचेगा. इसका नुकसान सपा को ही होगा. सपा रालोद के साथ तालमेल साधने की कोशिश कर रही है, रालोद की शर्त थी जयंत चौधरी को अखिलेश मंत्रिमंडल में शरीक किया जाए, लेकिन रामगोपाल ने ऐसा होने नहीं दिया. लिहाजा, रालोद से तालमेल भी मुश्किल में ही पड़ गया दिखता है. ■

अब प्रियंका और शीला के सहारे कांग्रेस की नाव

कांग्रेस नेतृत्व को अब यह सुध आ रही है कि प्रियंका गांधी का बेहतर राजनीतिक इस्तेमाल भी है. सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को राजनीति में आने से रोकती रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता रहा है कि प्रियंका के राजनीति में आने से राहुल गांधी छाया-क्षेत्र में चले जाएंगे. लेकिन अब स्थिति ऐसी बन रही है कि बिना प्रियंका के यूपी में तो नाव पार लगती दिखाई नहीं देती. लिहाजा, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव की कमान देने और सक्रिय राजनीति में उतारने का मन बना लिया है. प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी.

कांग्रेस के लिए यूपी में वापसी करना जीवन-मरण का प्रश्न है. अब उसे प्रियंका में ही उम्मीद दिखाई दे रही है. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी कह चुके हैं कि प्रियंका को अब सक्रिय राजनीति में आकर कमान संभालनी चाहिए. कांग्रेस के चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर ने भी प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की सलाह दी थी. अब इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस प्रियंका को ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पहले यूपी लाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन वे उत्तर प्रदेश आने से हिचक रही थीं. कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें अपनी राय पर दोबारा विचार करने को कहा था. शीला दीक्षित ने पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद कहा जाने लगा कि शीला दीक्षित अपनी नई भूमिका में आना स्वीकार कर लिया है. शीला दीक्षित के पास पंजाब और उत्तर प्रदेश का दो विकल्प रखा गया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश चुना. कांग्रेस पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की जद्दोजहद कर रही है. प्रियंका गांधी यूपी के साथ-साथ देश के दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार करेंगी. वह पहले भी रायबरेली और अमेठी में प्रचार करती रही हैं.

बयानों से बेनक़ाब होते चेहरे

अनंत विजय

फिल्म अभिनेता इरफान खान अपनी फिल्म 'मदारी' के प्रमोशन में निकले थे और उस दौरान दिए उनके एक बयान से बवंडर खड़ा हो गया. दरअसल इरफान खान ने बकरीद के मौके पर बकरों की कुर्बानी पर सवाल खड़ा किया था. इरफान खान ने कहा कि दो बकरे खरीद कर उसका वध कर देना कोई कुर्बानी नहीं है. इससे कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है. कुर्बानी का अर्थ है कि हम अपनी कोई प्रिय वस्तु किसी को दे दें, जिसके साथ हमारा प्यार का संबंध हो. इरफान के इस बयान के बाद बवाल मच गया और कई मुस्लिम उलेमाओं और धर्मगुरुओं ने इरफान के बयान की लानत मलामत शुरू कर दी. एक मौलाना ने कहा कि इरफान को इस्लाम की जानकारी नहीं है और वो अपनी अज्ञानता में इस तरह के बयान दे रहे हैं. इरफान का जिस तरह से विरोध हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो जाए. इरफान खान ने जो कहा है उसे गंभीर चर्चा के बगैर खारिज कर देना उचित नहीं होगा. इस्लाम में कुर्बानी की प्रथा बहुत पुरानी है और शरीयत के मुताबिक सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी का प्रावधान है. इरफान भी यही कह रहे हैं. लेकिन विवाद की शुरुआत तब हुई जब इरफान ने बकरीद के ठीक पहले ये बयान दे दिया कि बकरीद में दो बकरों को खरीद कर उसकी कुर्बानी से पुण्य नहीं मिलता है. दरअसल बकरीद पर बकरों की बलि की परंपरा बहुत पुरानी है और उस दिन कुर्बान किए गए बकरों का एक तिहाई जरूरतमंदों को, एक तिहाई दोस्तों को और तोहफे के तौर पर देने का रिवाज रहा है. बाकी बचा एक तिहाई हिस्सा कुर्बानी देने वाला खुद रखता है. खैर हम इस परंपरा में और उसके पालन करने वालों की श्रद्धा में नहीं उलझना चाहते हैं. सवाल यही है कि अगर इरफान खान ने कोई सवाल उठाया है तो बजाए उसकी लानत मलामत करने के उस पर विमर्श होना चाहिए. जिन भी उलेमाओं को उनके इस कथन से विरोध है वो अपनी बात तर्कों के साथ रखें. इरफान को मूर्ख और मूढ़ कहने और उनके खिलाफ आग उगलने से वही होगा जो इरफान अपेक्षा कर रहे थे. धर्मगुरुओं के विरोध पर इरफान खान ने अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो धर्मगुरुओं से डरने वाले नहीं हैं. इरफान ने ट्वीट किया- प्लीज भाइयों जो मेरे बयान से नाराज हैं वो या तो आत्मविश्लेषण करने को तैयार नहीं हैं या निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी में हैं. इरफान ने आगे लिखा कि मेरे लिए धर्म निजी आत्मविश्लेषण की तरह है, यह मेरे लिए दया, विवेक और संयम का स्रोत है ना कि रूढ़िवादिता और कट्टरवाद का. धर्मगुरू मुझे डरा नहीं सकते हैं. थैंक गॉड मैं ऐसे देश में नहीं रहता हूं जिसे धर्म के ठेकेदार चलाते हैं. इरफान ने अपने इस ट्वीट में कई सारी ऐसी बातें कह दीं जो कि विचार करने को मजबूर करती हैं.

इरफान ने साफ तौर पर कहा है कि धर्म बेहद निजी मामला है, लेकिन उसमें विरोधाभास दिखाते हुए वो धर्म को लेकर, उसकी परंपराओं को लेकर सार्वजनिक तौर पर अपनी बातें भी रख रहे हैं. संभव है कि वो अपने धर्म की कुछ बातों पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाकर उसमें बदलाव की ख्वाहिश रखते होंगे. बकरों की कुर्बानी पर दिए उनके बयान को इस आलोक में देखा जाना चाहिए. लेकिन धर्मगुरुओं को नाराज होने और इरफान को उल-जलूल कहने का हक क्यों होना चाहिए? जब इरफान पर हमले हो रहे हैं तो सवाल उठता है कि इस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी के झंडाबरदार कहां हैं? समाज में बोलने की आजादी के अधिकार के निरंतर ह्रास को लेकर छाती कूटने वाला समुदाय इस वक्त इरफान के पक्ष में क्यों नहीं मजबूती से खड़ा हो रहा है? इरफान को जिस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर उसके पक्ष में कहीं से किसी तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही है. देश में असहिष्णुता को लेकर बयान देने वाले शाहरुख खान भी बॉलीवुड के अपने साथी

कलाकार इरफान के पक्ष में खड़े दिखाई नहीं देते. शाहरुख खान को इरफान को चुप करवा देने की कोशिशों में कोई असहिष्णुता अब तक नजर नहीं आई है. उन दिनों जब देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर अवॉर्ड वापसी का कोलाहल था और उसके पक्ष-विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे तब शाहरुख खान ने ट्वीट किया था कि लोग बगैर सोचे समझे बयानबाजी करते हैं. धार्मिक असहिष्णुता और इस देश में धर्मनिरपेक्ष नहीं होना एक देशभक्त के तौर पर सबसे बड़ा अपराध है. शाहरुख की बात सही है, लेकिन अब जब इरफान ने इस्लाम की परंपरा पर सवाल खड़ा किया है और चंद मुस्लिम उलेमाओं द्वारा उनको खामोश करने की कोशिश हो रही है, तो पूरे देश को शाहरुख के उसी तरह के ट्वीट का इंतजार है. अगर धार्मिक असहिष्णुता उस वक्त गलत थी तो अब भी गलत होनी चाहिए. क्या धार्मिक असहिष्णुता का सवाल सिर्फ हिंदू कट्टरपंथियों के बयानों पर ही दिखाई देने लगता है. इसी तरह से बहुत संभव है कि आमिर खान को इरफान की आलोचनाओं के बाद भी डर नहीं लग रहा होगा और वो अपनी पत्नी से देश में डर लगने जैसी बातचीत नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये इस्लाम से जुड़ा मामला है. अगर ऐसा होता तो आमिर खान जरूर सामने आते और अपनी मन की बात को सामने रखते. तो क्या ये मान लिया जाए कि इस्लाम की परंपराओं की बात आते ही समाज के ये नायक खामोश हो जाते हैं. उनको न तो देश में डर लगता है और न ही देश की फिजां में कोई बुराई नजर आती है. मेरा मानना है कि ये मामला चूंकि एक धर्म विशेष से जुड़ा है लिहाजा हर कोई खामोशी की चादर ओढ़ कर सुविधा की नींद सो रहा है. अगर यही मामला हिंदू धर्म से जुड़ा होता तो अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन अब तक उछलकूद मचा रहे होते. सवाल यही है कि क्या इरफान को भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता है? क्या इरफान खान के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं को लेकर दिए जाने वाले बयानों में किसी को भी असहिष्णुता नहीं दिखाई दे रही है? ये सब कई ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे जाने चाहिए और सुविधा की खामोशी अख्तियार करने वालों से तो अवश्य ही पूछे जाने चाहिए. दरअसल, हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी आदि के मुद्दे पर हमारे चैंपियन अलग-अलग धर्मों को लेकर अलग-अलग रुख अपनाते रहे हैं. अब अगर इरफान ने इस्लाम की परंपराओं को लेकर कोई सवाल खड़ा किया है तो उसको धमका कर या विरोध का भय दिखाकर चुप करवा देना कहां तक जायज है. क्या इस्लाम में जारी परंपराओं पर बोलने का हक किसी को नहीं है और कोई बोले तो उसको ईशनिंदा की श्रेणी में डाल देना चाहिए. तब तो इरफान ने ठीक ही खुदा का शुक्रिया अदा किया है कि वो भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहां धर्म के ठेकेदार देश नहीं चला रहे हैं. इरफान के बयान से एक बार फिर से सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म का आंदोलन चलाने वालों के चहरे बेनकाब हो रहे हैं.

कुछ लोगों का तर्क है कि इरफान अपनी फिल्म 'मदारी' को हिट कराने के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं ताकि उनकी फिल्म को फायदा हो सके. हो सकता है ऐसी दलील देने वालों के तर्क में दम हो. लेकिन अगर इरफान अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए भी खुद को विवादित बना कर चर्चित होना चाहते हैं तब भी उनके अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को कोई कैसे रोक सकता है. संभव है कि इरफान को लगा होगा कि इस्लाम की परंपराओं के खिलाफ बयान देकर वो फिल्म को सफल करवा ले जाएंगे. अगर ऐसा है तो बजाए इरफान का विरोध करने के उनके इस डिजायन को उभारा जाना चाहिए. उलेमाओं को धर्म की दुहाई देकर उसकी परंपराओं और शरिया की आड़ में इरफान का विरोध करने की बजाय साफ कर देना चाहिए कि वो अपनी फिल्म को सफल बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. बजाए इसके वो भी उल्टे भड़काऊ बयान देकर इरफान की रणनीति को सफल बना रहे हैं. इस विवादित बयान को लेकर भले ही कुछ दिनों में बयानों की जंग ठंडी पड़ जाए, लेकिन इसका असर लंबे समय तक देखा जा सकेगा और मुझे लगता है कि ये कई तरह के गंभीर विमर्श को जन्म देने का पुख्ता आधार भी प्रदान करेगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

प्लैटिनम क्लब में शामिल हुआ अंकुश कैपिटल

अंकुश कैपिटल को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने सिंगापुर में प्लैटिनम क्लब में शामिल किया है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ जुड़कर दस हजार एसोसिएट्स काम कर रहे हैं. इन दस हजार एसोसिएट्स में सिर्फ 200 एसोसिएट्स ही प्लैटिनम क्लब में शामिल होने के लिए अर्हता प्राप्त कर सके हैं. इसमें अंकुश कैपिटल ने चौथे स्थान पर आने के साथ प्लैटिनम क्लब के टॉप फाइव में जगह बनाई. अंकुश कैपिटल ने साल भर में एक करोड़ बीस लाख का बिजनेस कर इंश्योरेंस सेक्टर में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है. हेमंत शर्मा, मुस्तकीम खान और आदिल परवेज की टीम ने प्लैटिनम क्लब में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत की. हेमंत शर्मा, मुस्तकीम खान और आदिल परवेज ने टीम वर्क और लगन से काम करते हुए सभी कर्मचारियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया. 2010 से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे अंकुश कैपिटल के लिए यह एक बड़ी सफलता है. अंकुश कैपिटल देश की महत्वपूर्ण ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस और जेनरल इंश्योरेंस कंपनी है. अंकुश कैपिटल लाइफ, मेडिकल और मोटर इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करती है. बेहतर कार्यक्षमता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा के कारण यह देश में फाइनेंशियल नेटवर्क क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही कंपनी के रूप में स्थापित हो रही है. तकनीकी दक्षता के साथ विश्वसनीय रिस्क मैनेजर्स की टीम देश भर में कई महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट्स में सफलता के झंडे गाड़ रही है. ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण ऑफर देती है, जिसमें ग्राहकों को उनके पैसे की बेहतर सुरक्षा के साथ उचित मूल्य भी मिलता है. ■

साईं वंदना

आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु के शिष्यत्व का संबंध

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

गुरु का संरक्षण

गुरु मार्ग पर चलते हुए गलतियां जरूर करेंगे, तो श्री गुरु को इस बात से कब और कैसे अवगत कराएं?

मनुष्य से गलतियां होती ही हैं. सद्गुरु को विदित है कि माया के खेल में उनका शिष्य गलती करेगा ही. सद्गुरु सचेत रहते हैं कि उसे गलतियां करने से रोकें. अपनी गलतियों के कारण यदि शिष्य संकट में भी पड़ जाए तो सद्गुरु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता अवश्य करते हैं. बाबा कहते थे- यह तुम जानो कि जहां भी तुम जो भी करते हो मुझे जानकारी है. उनके जीवन से पता चलता है कि वे सर्वज्ञाता थे. गुरु जानते हैं कि अपने किस शिष्य को कैसे आगे बढ़ाना है और किसे गलतियां करने से कैसे रोकना है. अनजाने में की गई गलतियों के लिए हमें गुरु का संरक्षण अवश्य मिलेगा परन्तु हमें प्रयास करना चाहिए कि जानबूझ कर की गई गलतियों की पुनरावृत्ति न हो. कभी-कभी गुरु के मार्ग का अनुसरण करने में सफल नहीं हो पाते. गुरु इस बात का बुरा नहीं मानते. वे तो केवल शिष्य की गुरु-मार्ग पर आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति की प्रबलता को परखते हैं. यदि इच्छा प्रबल है और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है, तो गलतियां होने पर भी वे शिष्य को गुरु-मार्ग पर अपने साथ रखते हैं.

गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास एवं निर्देशों का पालन

एक शिष्य के रूप में विकसित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उसे कैसे अर्जित किया जाए?

सभी व्यक्तियों में एक गुरु एवं साथ ही साथ एक शिष्य बनने के गुण अन्तर्निहित होते हैं. बचपन में माता-पिता बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जो कि उनको विकसित करने के लिए आवश्यक होती है. जब वे कुछ बड़े होते हैं, तो स्कूल एवं कॉलेज जाते हैं और अपने अध्यापकों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं. सामान्य जीवन में भी व्यक्ति जाने-अनजाने किसी न किसी से कितनी ही बातें सीखता है. जहां तक आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु के शिष्यत्व का संबंध है, इसके लिए कुछ विशेष आचार एवं नियमों का पालन करना आवश्यक है. शिष्य बनने के लिए पहली आवश्यक योग्यता है- गुरु के प्रति सम्पूर्ण विश्वास अर्थात यह कि शिष्य के लिए गुरु जो भी कर रहे हैं, वह शिष्य के हित में होगा. दूसरी बात यह है कि गुरु जो भी कहें, उनके दिशा-निर्देशों एवं उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए और जहां तक हो सके यथाशक्ति उनका पालन करना चाहिए. उदाहरण के लिए यदि गुरु कहते हैं कि दयालु बनो और गरीबों को भोजन कराओ, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह कार्य करना चाहिए. यदि सद्गुरु के निर्देशों का पालन करने में उसके समक्ष कोई कठिनाई आती है, तो उसे अपने गुरु को उस संबंध में बता देना चाहिए. असली गुरु सदैव परिस्थितियों के अनुरूप उस समस्या का सरल समाधान करेंगे. गुरु एक ऐसा रास्ता सुझाएंगे जो कि इस जटिल संसार में उपयुक्त और आसान होगा. जहां गुरु देह-रूप में नहीं है, जैसे कि श्रीसाईं, उस संबंध में उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं को समझ कर उत्तर पाने का प्रयत्न करना चाहिए. इसीलिए श्री साईं सच्चरित्र का नियमित पारायण करने के लिए कहा गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आम

पिछले अंक से आगे

नासा रोग :

❖ **नकसीर-** आम के फूलों के स्वरस को 1-2 बूंद नाक में डालने से नकसीर में लाभ होता है.

कण्ठ रोग :

❖ **स्वरभेद-** आम के 40 ग्राम पत्तों को 400 मिली पानी में उबालकर चतुर्थांश शेष क्वाथ बनाकर, 10-20 मिली क्वाथ में शहद मिलाकर धीरे-धीरे पीने से गले की खराश ठीक होती है.

मुख रोग :

❖ आम फल की छाल व पत्तों को समभाग पीसकर जल में मिलाकर कुल्ला करने से दांत व मसूढ़े मजबूत होते हैं.

वक्ष रोग :

❖ **खांसी-** पके हुए आम को आग में भूनकर ठंडा होने पर धीरे-धीरे चूसने से सूखी खांसी मिटती है.

❖ **हिक्कारोग-** आम के ताजे पत्तों को कूटकर निकाले गए रस (2-3 मिली) में थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करने से हिचकी बंद हो जाती है.

❖ आम के पत्ते व धनिया दोनों को कूटकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर गुनगुने जल के साथ सेवन करने से हिक्का में लाभ होता है.

उदर रोग :

❖ **तृष्णा-** आम गुठली की गिरी से निर्मित 10-20 मिली क्वाथ में 10 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से अत्यधिक प्यास शांत होती है.

❖ **अतिसार-** 10 ग्राम आम की गुठली की गिरी को 100 मिली जल में उबालें. इसे दिन में 3 बार छाछ के साथ सेवन करें, पथ्य में चावल और दही का सेवन करें.

❖ 1 भाग आम की गुठली की गिरी, 1 भाग बेलगिरी तथा 1 भाग मिश्री तीनों को चूर्ण बनाकर 3-6 ग्राम की मात्रा में लेकर जल के साथ सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है.

❖ आम की गुठली की गिरी तथा आम की गोंद को समभाग लेकर 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 2-3 बार सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है.

❖ आम की गुठली की 10-20 ग्राम गिरी को कांजी के साथ पीसकर उदर पर गाढ़ा लेप करने से अतिसार में लाभ होता है.

❖ आम वृक्ष की अन्तरछाल को कुट कर आधा लीटर जल में अष्टमांश क्वाथ होने तक पकाएं. ठंडा होने पर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिलाने से अतिसार विशेषत: आमातिसार में लाभ होता है.

❖ आम की ताजी छाल को दही के पानी के साथ पीसकर उदर में लेप करने से अतिसार में लाभ होता है.

❖ 10 मिली आमपत्र-स्वरस में 10-10 मिली शहद और दूध तथा 6 ग्राम घी को मिलाकर पिलाने से रक्तातिसार में विशेष लाभ होता है.

❖ 1-2 ग्राम आम की गुठली की गिरी को भूनकर चूर्ण कर, 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में दो बार चटाएं.

❖ **संग्रहणी-** ताजे मीठे आमों को 50 मिली स्वरस में 20-25 ग्राम मीठा दही तथा एक चम्मच शुंठी चूर्ण बुरक कर दिन में दो-तीन बार देने से कुछ ही दिनों में पुरानी संग्रहणी में लाभ होता है.

❖ **गर्भिणी अतिसार-** पुराने आम की गुठली 4 ग्राम चूर्ण को शहद या जल के साथ भोजन के दो घंटे पूर्व दिन में तीन बार सेवन करने से लाभ होता है.

जारी...

आचार्य बालकृष्ण

मेसी के चमकदार करियर का दुखद अंत!

लेकिन संन्यास का कारण कुछ और है

सैयद मोहम्मद अब्बास

फुटबॉल की दुनिया में उसे अर्जेंटीना टीम का सितारा कहते हैं. फुटबॉल में उसकी चपलता देखकर दुनिया सलाम करती है. फुटबॉल के मैदान पर अगर मेसी चल पड़ा तो बड़ी से बड़ी विरोधी टीम भी आसानी से घुटने टेक देती है. आलम तो यह रहता है कि विरोधी उसे मैच में रोकने के लिये नये-नये हथकंडे अपनाते हैं लेकिन फुटबॉल की गेंद मेसी के पाले में है तो उसे रोकना नामुमकिन है. पर अफसोस शायद अब इस खिलाड़ी को आप मैदान पर दोबारा गोल करते नहीं देखेंगे. अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अचानक अलविदा कह दिया है. जिसके बाद लियोनल मेसी की वापसी के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आया है. इतना ही नहीं उनके समर्थन में रैली निकाली जा रही है. बारिश और भीषण ठंड के बावजूद अर्जेंटीना की राजधानी में हजारों लोगों ने रैली निकाली और मेसी से राष्ट्रीय टीम में वापसी करने की गुजारिश की.

देशभर में उनके प्रशंसक मायूस हैं कि अब मेसी का जादू देखने को नहीं मिलेगा. दरअसल कोपा अमेरिका फुटबॉल में अर्जेंटीना टीम का प्रदर्शन शानदार था. मैच दर मैच अर्जेंटीना खिताब के करीब पहुंच रहा था लेकिन अंतिम लड़ाई में वह फिसल गया. हार की सारी जिम्मेदारी लियोनल मेसी पर डाल दी गई, क्योंकि चिली के खिलाफ इस मुकाबले में पेनाल्टी से मेसी चूक गये थे. इसके बाद मेसी ने इस खेल को अलविदा कहना मुनासिब समझा. जानकारों की मानें तो यह मुकाबला संन्यास का कारण नहीं था बल्कि ओलम्पिक की टीम से उनका नाम गायब होना था. शायद इसी मलाल में उसने खेल को एक झटके में छोड़ने का फैसला कर लिया. जिसके इशारे पर गेंद नाचती थी उसको अर्जेंटीना की ओलम्पिक टीम में जगह तक नहीं दी गई थी. यह गम मेसी को अन्दर ही अन्दर खा रहा था. फाइनल मैच हारने के बाद मेसी की आंखें आंसू से भरी थीं. दुनिया सोच रही थी मेसी इस मैच की हार से आहत हैं लेकिन यह बात भी सत्य है कि विश्व का दिग्गज फुटबॉलर अपनी टीम को अब तक कोई खिताब नहीं दिला सका है. दुनिया की नजर में वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय टीम के लिये चमत्कार नहीं कर पाता है. संन्यास के बाद अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वह बॉर्सिलोना के लिए खेलना जारी रखेंगे या नहीं. जिस उम्र में खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में होते हैं वहां मेसी जैसी स्टार खिलाड़ी खेल को छोड़ने का मन बना लेते हैं. मेसी की तुलना माराडोना से होती है. दोनों ही अपने वक्त के सुपर स्टार माने जाते हैं. माराडोना के करियर पर नजर दौड़ायी जाये तो इतना तो साफ है कि उसने अर्जेंटीना के लिए बहुत कुछ किया है. उसमें प्रमुख है 1986 का विश्व कप फुटबॉल का खिताब. माना जाता है कि यहीं से माराडोना और मेसी के बीच का अन्तर देखा जा सकता है. भले ही मेसी दुनिया के महानतम फुटबॉलरों की सूची में शामिल हों लेकिन जब देश की बात आती है तो वह फिसड्डी साबित होते हैं. क्लब खेलों में मेसी का कोई सानी नहीं है. मेसी का उम्दा खेल भले ही उनके देश के लोगों ने नहीं देखा हो, लेकिन बार्सिलोना क्लब को मेसी ने अपने खेल के दम पर कई बार चैम्पियन बनाया है. यूरोप की नम्बर एक टीम बनाने में मेसी का खास योगदान रहा है. मेसी की तूती पूरे विश्व में बोलती है, लेकिन माराडोना से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है. अतीत में फुटबॉल की दुनिया पेले और माराडोना के नाम से चलती थी. मौजूदा दौर में कई और नाम सामने आये हैं लेकिन मेसी को मैराडोना के समकक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता है. अक्सर फुटबॉल जगत में मेसी को अव्वल बताया जाता है. माराडोना ने हाल में मेसी की खूब आलोचना की थी. मैराडोना के अनुसार मेसी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है. 29 साल के मेसी ने देश के लिये खेलते हुए सबसे ज्यादा 55 गोल किये हैं. विश्व के कई बड़े पुरस्कार उनकी झोली में जा चुके हैं. उन्हें तीन बार यूरोपियन गोल्डेन शू अवॉर्ड भी मिला है. स्वर्णिम करियर और पांच बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीतने वाले मेसी देश की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं. इसका ताजा उदारहण है अर्जेंटीना की टीम का साल 2014 के बाद तीसरी बार किसी बड़े टूर्नामेंट में पराजित होना. शायद इसी हार को मेसी पचा नहीं पा रहे हैं. बड़े चौंकाने वाले अंदाज में उन्हें संन्यास की घोषणा करनी पड़ी. 2014 विश्व कप में अर्जेंटीना खिताब का तगड़ा दावेदार था. टूर्नामेंट की शुरुआत में मेसी के खेल की चर्चा हर तरफ हो रही थी. टीम भी पूरे जोश के साथ मैदान पर जीत दर्ज कर रही थी. विश्व कप के खिताब को जीतने के बेहद करीब थी अर्जेंटीना की टीम, लेकिन जर्मनी ने उसे 1-0 से पराजित कर मेसी के अरमानों पर पानी फेर दिया. 2015 के कोपा अमेरिका कप के खिताबी मुकाबले में यही सब कुछ देखने को मिला. तब चिली ने अर्जेंटीना का विजय रथ रोक दिया था. 2007 के कोपा अमेरिका कप में भी मेसी की मौजूदगी में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा.

मेसी का करियर बेहद चमकदार रहा है. इसमें कोई दो राय नहीं है. मेसी केवल 13 साल की उम्र में विश्व के जाने माने फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से जुड़ गये थे. उस वक्त मेसी से करार करने के लिये बार्सिलोना क्लब भी बेहद उतावला दिखा था. अगस्त 2005 में हंगरी के खिलाफ मेसी ने अर्जेंटीना की तरफ से खेलना शुरू किया था. उस वक्त उनकी उम्र केवल 18 साल की थी. हालांकि शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और केवल 47 सेकेंड में उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया था. फुटबॉल में रेड कार्ड तभी मिलता है जब खिलाड़ी नियमों को तोड़ता है. हालांकि इसके बाद मेसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. तमाम बाधाओं को पार करते हुए मेसी आगे बढ़ रहे थे. ऐसे में देश की टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन भी गिर रहा था लेकिन देश की उम्मीदों का बोझ शायद मेसी उठा नहीं पा रहे थे. उनके गोल करने का अंदाज भी बेहद निराला था. वह मैदान पर हमेशा उत्साह भरे अंदाज में दिखते थे. मेसी ने अपने बेजोड़ खेल से सबको अपना मुरीद बनाया है. इसी खेल की बदौलत उन्हें द लिटिल मैजिशियन के नाम से पुकारा जाता है. कुल मिलाकर हर खेल में जीत और हार लगी रहती है. कभी खुशी होती तो कभी गम होता है लेकिन इसके बावजूद दुनिया चलती है. मेसी ने भले ही संन्यास ले लिया हो लेकिन उनके इस खेल के प्रति जुनून को दुनिया याद रखेगी. ■

पीटी उषा के बाद दुती चंद बन सकती हैं नई उड़नपरी

ओलम्पिक बेहद करीब है. रियो के खेल में भारतीय उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं. देश के नामी गिरामी एथलीट अपनी तैयारी को अन्तिम रूप देने में लगे हुए हैं. इसी क्रम में भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक और खुशी की खबर आयी है. 100 मीटर की दौड़ में अब भारत की सबसे तेज धावक दुती चंद रियो ओलम्पिक में भारतीय तिरंगे को बुलन्द करती दिखेंगी. यह पहला मौका होगा जब पीटी ऊषा के बाद किसी धावक को 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने का अवसर मिला है. 1980 में पीटी उषा को भारतीय टीम में शामिल किया गया था. दुती की रफ्तार को देखकर यही लगता है कि वह ओलम्पिक में भारत का नाम रौशन कर सकती हैं. दुती ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. एक वक्त ऐसा भी था जब लगा कि उनका करियर खातमे की ओर है लेकिन दुती ने इसे धता बताकर सबको चौंका दिया. तमाम बाधाओं को पार करते हुए वह अब रियो के खेल में दम दिखाने को बेताब हैं.

दुती के करियर में तब बड़ा विवाद पैदा हो गया जब पुरुष हार्मोन के चलते उन पर बैन लगा दिया गया था. यह घटना साल 2014 की है. इस साल दुती को केवल इसलिये एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरॉन का स्तर अधिक पाया गया था. टेस्टोस्टेरॉन पुरुष हार्मोन को कहा जाता है. इतना ही नहीं, उनके लिंग परीक्षण की रिपोर्ट को काफी असंवेदनशील तरीके से सार्वजनिक किया गया था, जिसके बाद कहा जाने लगा कि वह एक पुरुष हैं जो महिलाओं की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं. इसके बाद दुती का करियर गर्त की ओर बढ़ने लगा था. इसके बाद उन्हें खेल से अलग-थलग कर दिया गया था. इस बैन के खिलाफ दुती ने स्विट्जरलैंड की खेल पंचाट में गुहार लगायी. इसके बाद उन्हें दोबारा खेलों की दुनिया में लौटने की अनुमति मिल गयी. दुती के लिये यह बहुत बड़ा दिन था. वापसी करने वाली दुती ने एक बार फिर मैदान पर पसीना बहाना शुरू कर दिया. वह अब नये लक्ष्य की ओर बढ़ने लगीं.

भारत में अगर रफ्तार की बात की जाये तो इसमें सबसे पहला नाम पीटी उषा का आयेगा. दरअसल पीटी उषा ने भारतीय खेल जगत में खूब नाम कमाया है. उन्हें उड़नपरी कहा जाता है. दुती भी पीटी उषा की तरह दौड़ना चाहती हैं. उन्होंने दिल्ली में आयोजित फेडरेशन कप में अच्छा प्रदर्शन किया, वहां नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान कायम किया था लेकिन रियो का टिकट हासिल करने में वह चूक गई थीं. इसके बाद उन्होंने कज़ाखस्तान में आयोजित प्रतियोगिता में 11.24 का समय निकालते हुए 100 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल करते हुए रियो ओलम्पिक का टिकट हासिल कर लिया. दुति का मौजूदा प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि आने वाले दिनों में वह भारत को पदक दिला सकती हैं. 1980 और 1984 में पीटी उषा ने भारत को भले ही पदक न दिलाया हो, पर इस बार दुती चंद एक नई उम्मीदों के साथ रियो ओलम्पिक में जा रही हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दोस्ती टूटने की ख़बर पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा

दीपिका से दोस्ताना संबंधों में कोई बदलाव नहीं

मैं स्पष्ट कर रही हूं कि हम दोनों के बीच जैसा पहले था वैसा अब भी है. मुझे दीपिका से किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं है. हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और आज भी अच्छे दोस्त हैं. आपका नज़रिया बदल गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था. प्रियंका ने यह एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा था.

प्रवीण कुमार

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने और दीपिका पादुकोण के बीच लड़ाई की ख़बरों के उलट कहा कि उन दोनों के बीच दोस्ताना संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है. कुछ समय पहले ख़बर थी कि हॉलीवुड में पहचान बनाने में लगीं दोनों हीरोइनों की दोस्ती टूट गई है. देखते ही देखते यह बात पूरे सोशल मीडिया और अख़बारों में तेज़ी से फैल गई. लेकिन प्रियंका ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा कि आपने कहा कि हम दोस्त हैं. पहले आप कहते थे कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं तो अब यह कैसे बदल गया, क्यों और कैसे बदल गया? मैंने नहीं कहा कि यह (समीकरण) बदल गया, आपने कहा कि यह बदल गया.

प्रियंका ने आगे कहा कि मैं स्पष्ट कर रही हूं कि हम दोनों के बीच जैसा पहले था वैसा अब भी है. मुझे दीपिका से किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं है. हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और आज भी अच्छे दोस्त हैं. आपका नज़रिया बदल गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था. प्रियंका और दीपिका इस समय हॉलीवुड की फिल्मों में व्यस्त हैं.

इससे पहले इन दोनों के बीच मनमुटाव की ख़बरें कुछ समय से लगातार आ रही थीं. मगर आइफा 2016 के मंच पर इन दोनों का मनमुटाव खुल कर सामने आया जब दीपिका ने प्रियंका के संग पिंगा सॉन्ग पर ठुमके लगाने से साफ़ इंकार कर दिया और दीपिका मल्हारी गाने पर थिरकती दिखीं. इसके बाद जब प्रियंका से दीपिका के साथ डांस न करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से सवाल को ही टाल दिया. प्रियंका ने कहा कि ये आप आइफा वालों से पूछिए.

इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच संघर्ष सोशल मीडिया पर भी देखा जा चुका है. फिलहाल हम तो इतना ही कह सकते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें फिट नहीं हो सकतीं. भगवान करें दोनों की दोस्ती पहले जैसी ही बनी रहे.■

feedback@chauthiduniya.com

कुर्बानी विवाद

इरफ़ान खान ने धर्मगुरुओं को दिया करारा जवाब

इरफ़ान ने जयपुर में अपनी आने वाली फिल्म मदारी के प्रमोशन के दौरान बकरीद पर होने वाली कुर्बानी प्रथा पर अपनी राय रखी थी. उन्होंने कहा था, जितने भी रीति-रिवाज़, त्यौहार हैं, हम उनका असल मतलब भूल गए हैं, हमने उनका तमाशा बना दिया है. कुर्बानी एक अहम त्यौहार है. कुर्बानी का मतलब बलिदान करना है. किसी दूसरे की जान कुर्बान करके मैं और आप भला क्या बलिदान कर रहे हैं?

कुर्बानी से जुड़ा बयान देने के बाद इरफ़ान खान के खिलाफ़ इस्लामिक धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है. धर्मगुरुओं ने इरफ़ान को बॉलीवुड में अपने काम पर ध्यान लगाने और धार्मिक मामलों में न पड़ने की सलाह दी है. हालांकि इरफ़ान का कहना है कि वह धर्मगुरुओं से डरने वाले नहीं हैं. अच्छा है कि वह ऐसे देश में नहीं रहते जिसे धर्म के ठेकेदार चलाते हैं.

इरफ़ान ने फेसबुक पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि वह धर्म के ठेकेदारों द्वारा चलाए जाने वाले देश में नहीं रह रहे हैं. उन्होंने लिखा, *प्लीज भाइयों, जो भी मेरे बयान से दुखी हैं या तो वो आत्मनिरीक्षण करने के लिए तैयार नहीं हैं या फिर आपको परिणाम तक पहुंचने की बहुत जल्दी है. मेरे लिए धर्म व्यक्तिगत आत्मविश्लेषण है, यह करुणा, ज्ञान और संयम का स्रोत है, यह रूढ़ीवादिता और कट्टरता नहीं है. धर्मगुरुओं से मुझे डर नहीं लगता. शुक्र है ईश्वर का कि मैं धर्म के ठेकेदारों द्वारा चलाए जाने वाले देश में नहीं रहता हूं.*

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले इरफ़ान ने जयपुर में अपनी आने वाली फिल्म *मदारी* के प्रमोशन के दौरान बकरीद पर होने वाली कुर्बानी प्रथा पर अपनी राय रखी थी. उन्होंने कहा था, *जितने भी रीति-रिवाज़, त्यौहार हैं, हम उनका असल मतलब भूल गए हैं, हमने उनका तमाशा बना दिया है. कुर्बानी एक अहम त्यौहार है. कुर्बानी का मतलब बलिदान करना है. किसी दूसरे की जान कुर्बान करके मैं और आप भला क्या बलिदान कर रहे हैं?*

इरफ़ान के इस बयान पर कुछ इस्लामिक जानकारों ने आपत्ति जताई. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जयपुर के शहर काज़ी ख़ालिद उस्मानी ने कहा, इरफ़ान अभिनेता हैं और उन्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. उन्हें धार्मिक ज्ञान नहीं है और उन्हें कुर्बानी या रमजान पर सवाल उठाने से पहले किसी धर्मगुरू से संपर्क कर इसके बारे में सीखना चाहिए था. उन्होंने कहा कि इस्लाम अस्पष्ट नहीं है और इरफ़ान को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए. वहीं इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल लतीफ़ ने कहा है कि इरफ़ान एक्टिंग के मास्टर हैं, लेकिन धार्मिक मामलों के नहीं.■

सलमान के साथ एक स्टेज पर कतई नहीं ऋतिक रोशन

ऋतिक और सलमान के बीच तकरार तब से है जब सलमान खान ने ऋतिक रोशन की फिल्म गुजारिश की सबके सामने बुराई की थी और कहा था - गुजारिश फिल्म का तो कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया.

स्पेन में हुए आईफा-2016 के दौरान बॉलीवुड के तमाम सितारे मौजूद थे. आईफा की टीम ने बॉलीवुड सितारों के लिए स्पेशल प्रेस कांफ्रेंस आयोजित किया था. जहां सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा सहित अन्य सितारें शामिल रहे. प्रेस कांफ्रेस की शुरूआत में सभी सितारें एक साथ स्टेज पर गए. लेकिन ऋतिक एक ऐसे स्टार थे, जिन्होंने नीचे रहना ही बेहतर समझा.

काफी लोगों को शायद पता नहीं है कि ऋतिक रोशन और सलमान खान एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते. हो सकता है यहां भी ऋतिक-सलमान के साथ स्टेज नहीं शेयर करना चाहते हों. यहां तक की ऋतिक कई बार सलमान खान को इग्नोर करते भी दिखे. इसकी भी एक वजह है जिससे इन दोनों सुपरस्टारों में तकरार बनी हुई है. दरअसल ऋतिक और सलमान के बीच यह तकरार तब से है जब सलमान खान ने ऋतिक की फिल्म *गुजारिश* को लेकर सबके सामने बुराई की थी और कहा था- गुजारिश फिल्म को तो कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया. सलमान की यह बात ऋतिक आज तक नहीं भूले और इन दोनों में दूरियां अभी तक बनी हुई हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

फ्लैशबैक

कैसे अमजद खान बने गब्बर

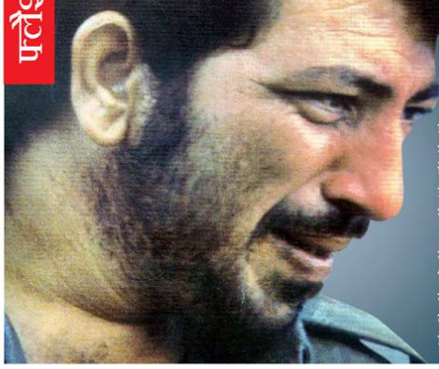

शोले में गब्बर सिंह का रोल अदा करने वाले अमजद खान आज हमारे बीच तो नहीं हैं पर उनकी यादें सबको यह कहने पर मज़बूर कर देती हैं कि वह खलनायक नहीं नायक थे. चाहे फिल्मों में डाकू का किरदार हो या एक हास्य कलाकार का किरदार, हर रोल में अमजद खान ने खुद को फिट किया. हिन्दी सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्म शोले का किरदार गब्बर तो सबको याद होगा. आखिर गब्बर का रोल निभाने वाले अमजद खान को यह फिल्म कैसे मिली यह बहुत कम लोग जानते हैं.

ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह ने अमजद खान को फिल्म इंडस्ट्री में सशक्त पहचान दिलायी. फिल्म के निर्माण के समय गब्बर सिंह वाली भूमिका पहले डैनी को दी गई थी लेकिन उन्होंने उस समय फिल्म *धर्मात्मा* में काम करने की वजह से उन्होंने शोले में काम करने से इन्कार कर दिया. इसके बाद शोले के कहानीकार सलीम खान की सिफारिश पर रमेश सिप्पी ने अमजद खान को गब्बर सिंह का किरदार निभाने का अवसर दिया. जब सलीम खान ने अमजद खान से फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाने को कहा तो अमजद खान घबरा गए लेकिन बाद में उन्होंने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और चंबल के डाकुओं पर बनी किताब *अभिशप्त चंबल का* बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया. बाद में जब फिल्म शोले प्रदर्शित हुई तो अमजद खान का निभाया किरदार गब्बर सिंह दर्शकों में इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग उनकी आवाज़ और चाल ढाल की नकल आज तक करते हैं.

12 नवंबर 1940 को जन्मे अमजद खान को अभिनय की कला विरासत में मिली. उनके पिता जयंत फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक रह चुके थे. अमजद खान ने बतौर कलाकार अपने अभिनय जीवन की शुरूआत वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म *अब दिल्ली दूर नहीं* से की थी. इस फिल्म में अमजद खान ने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी. वर्ष 1965 में अपनी होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म *पत्थर के सनम* के जरिये अमजद खान बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरूआत करने वाले थे लेकिन किसी कारण से फिल्म का निर्माण नहीं हो सका.

वर्ष 1973 में बतौर अभिनेता उन्होंने फिल्म *हिंदुस्तान की कसम* से अपने करियर की शुरूआत की, लेकिन इस फिल्म से दर्शकों के बीच वह अपनी पहचान नहीं बना सके. लेकिन उसके बाद अमजद नाम का सितारा ऐसा चमका कि लोग देखते ही रह गए. उन्होंने फिल्म शोले, हम किसी से कम नहीं, परवरिश, शतरंज के खिलाड़ी, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, कुर्बानी, बरसात की एक रात, कालिया, लावारिस जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी. फिल्म रूदाली अमजद खान की अंतिम फिल्मों में से एक थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज़ हुई थी.■